R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.akshews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 19 । अंक : 22
16 से 31 अगस्त 2021
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

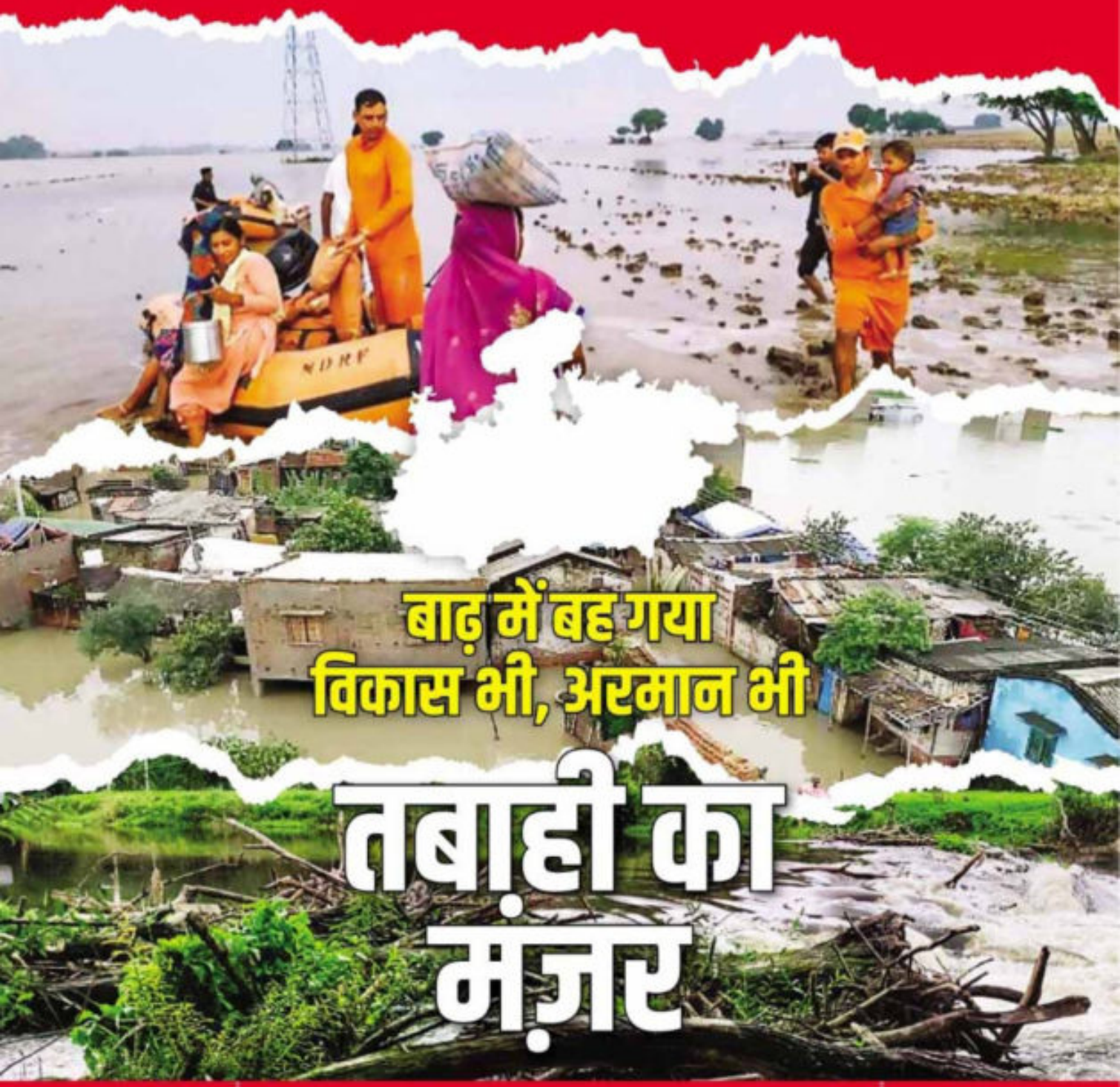

बाढ़ में बह गया विकास भी, अरमान भी

तबाही का मंज़र

कई लोगों की **मौत** | 30 हजार **घर तबाह**

हजारों पशुओं की **मौत** | आठ जिलों में **तबाही**

सुरक्षित स्तनपान
सभी की जिम्मेदारी
विश्व स्तनपान सप्ताह
1–7 अगस्त 2021

माँ का दूध, अमृत है ये बूंद

नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत समान है। यह नवजात का पहला टीका है, जो उसे रोगों से लड़ने में और जीवनभर उसके उत्तम स्वास्थ्य तथा सही शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 पर हम हर माँ का साथ देने और शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराने हेतु प्रोत्साहित करने का संकल्प लें।

आइए! अपनाएं स्तनपान के 3 मंत्र

शिशु जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान करना चाहिए।

पहले 6 महीने दिन रात शिशु को केवल स्तनपान करायें, ऊपर से दूध, घुट्टी या पानी बिल्कुल न दें।

6 माह पूरे होने पर ऊपरी आहार की शुरुआत करें। 2 साल या अधिक उम्र तक शिशु की मांग अनुसार स्तनपान जारी रखें।

किसी भी प्रकार का ऊपरी दूध, माँ के दूध की जगह नहीं ले सकता। विशेषकर बीमार, कम वजन या समय से पहले पैदा हुए कमजोर नवजात के लिए डिब्बा बंद दूध हानिकारक हो सकता है। माता के स्तनपान कराने में असमर्थ होने पर स्तन से निकाला हुआ दूध या अन्य स्वस्थ माता का दान किया दूध शिशु को पिलाएं। स्तनपान कमजोर शिशुओं को बीमारियों से बचाता है और उन्हें जल्दी स्वस्थ होने में मदद करता है।

माँ अथवा शिशु के बीमार होने की दशा में भी स्तनपान जारी रखें तथा इन 3 बातों का ध्यान रखें।

- संक्रमण से बचाव करें।
- साफ-सफाई का ध्यान रखें।
- डॉक्टर से सम्पर्क करें और डॉक्टर की बताई गई बातों का पालन करें।

अधिक जानकारी के लिए खण्ड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करें

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

इस अंक में

भर्राशाही

9 | तबादला बना उद्योग

मप्र में इन दिनों तबादलों का मौसम है। इस मौसम में अधिकारी-कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार तबादला कराने के जतन में लगे हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए दलाल सक्रिय हो गए हैं और सुविधा...

राजपथ

10-11 | 2023 की बिछने लगी चौसर

दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा काफी सजग और सतर्क है। इस बार पार्टी किसी गलतफहमी में नहीं दिख रही है। इसलिए चुनावी घोषणा से पहले ही उपचुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दी है।

विडंबना

12 | राशन के झोले में झोल

यह कहावत हम सभी ने अक्सर सुनी है कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन मप्र में माननीयों की स्थिति यह है कि समुंद्र में बैठे होने के बाद भी वे बूंद-बूंद बटोरने में लगे हुए हैं। इस मामले में गरीबों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ताजा मामला गरीबों...

राजकाज

13 | कबाड़ हुआ 70 करोड़ का विमान

आपने गरीबी में आटा गीला वाली कहावत तो पढ़ी और सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ मप्र सरकार के साथ हो रहा है। यानी सरकार हर माह कर्ज लेकर काम चला रही है, लेकिन उसके सामने नित नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इस समय बड़ी समस्या है एक अदद सरकारी विमान की।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

देश के हृदय स्थल में स्थित मप्र प्राकृतिक आपदा-विपदा में सबसे सुरक्षित प्रदेश माना जाता है। इस बार आफत की बारिश ने सारी मान्यताएं तोड़ते हुए ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ का वह मंजर दिखाया, जिसे वर्तमान पीढ़ी ने महसूस भी नहीं किया होगा। मप्र की इस बाढ़ में सरकारी विकास के साथ ही लोगों के घर-द्वार और अरमान भी पानी में बह गए। प्रारंभिक आंकलन में बाढ़ से 8 जिलों में 29 लोगों की जान गई। 3,746 पशुओं की मौत, 30 हजार घर टूटे और 1.11 लाख हैक्टेयर की फसलें तबाह हो गई हैं।

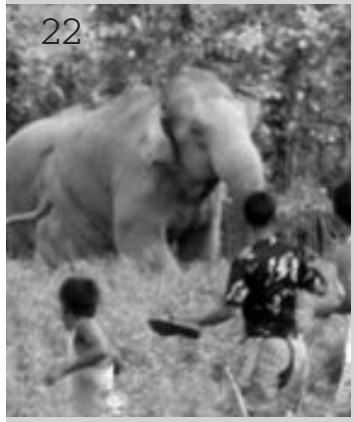

22

32-33

34

45

राजनीति

30-31 | कमजोर धुरी पर विपक्षी एकता

मई के पहले सप्ताह में बंगाल चुनाव के नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और उसके साथ ही पूरे देश खासकर उत्तर भारत में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करने की बहस छिड़ गई। विपक्ष मजबूत रहे, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है...

बिहार

36 | राजनीतिक भविष्य की खोज

नीतीश कुमार की मुश्किल ये है कि एनडीए में वापसी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी तो बची हुई है, लेकिन इर्द-गिर्द भाजपा ने पहरा लगा रखा है। नीतीश कुमार को कमजोर करने का कोई भी मौका भाजपा नहीं छोड़ती और मजबूरी में मन मसोस कर रह जाने के अलावा...

विदेश

38 | अफगान में अब तालिबान शासन

आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। इससे अफगानिस्तान में अफरा-तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। अब पूरे विश्व की निगाह तालिबान हुकूमत पर रहेगी।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

अपनी बर्बादी पे कितने खुश थे हम लेकिन...

शायर अहमद फराज का एक शेर है...

अपनी बर्बादी पे कितने खुश थे हम लेकिन फराज
दोस्त दुश्मन का निकल आया है अपना आशना

यह शेर इन दिनों मप्र की राजनीति का आईना बना हुआ है। दरअसल, सत्तारूढ़ पार्टी में जिस तरह वर्चस्व की अघोषित जंग चल रही है, उसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों के बीच करीब दो माह के अंतराल के बाद भोपाल आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दौरा बेहद सुर्खियों में बना हुआ है। वे इस दौरान जिस तरह से पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों से मिले और उसके बाद अपनी चिर-परिचित शैली में उन्होंने जिस तरह से भुट्टा पार्टी की उसके मायने तो निकलना ही थे। उनके इस दौरे को एक बार फिर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के पहले तक वे प्रदेश के उन गिने-चुने शीर्ष नेताओं में शामिल थे, जिनके बगैर सत्ता व संगठन में कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं होता था। यह बात अलग है कि उनके मंत्री रहते सूबे के पूर्व और वर्तमान मुखिया शिवराज सिंह चौहान से कभी भी पटरी नहीं बैठ पाने की खबरें आम होती रहीं और अब भी हो रही हैं। लेकिन विधानसभा में आयोजित भुट्टा पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान के साथ दोस्ती का जिस तरह प्रदर्शन किया उससे एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई दोनों में दोस्ती है या फिर दिखावटी दोस्ताना। वैसे देखा जाए तो विजयवर्गीय मप्र की राजनीति में जो कुछ भी करते हैं वह चर्चा का विषय जरूर बन जाता है। बंगाल चुनाव के बाद वे फ्री हैं। इसलिए माना जा रहा है कि वे मप्र में अपनी धाक जमाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि इसके पहले वे जब भोपाल आए थे तो उस समय भी उनके द्वारा तमाम नेताओं से मेल-मुलाकात की गई थी। तब प्रदेश में तमाम नेताओं के बीच मिलने-जुलने का दौर चल रहा था। इसके बाद अब फिर से राजधानी आए तो तमाम सत्ता साकेत से जुड़े पूर्व और वर्तमान नेताओं से मिलने के बाद फिल्म शोले के गीत पर जिस तरह से सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आए वह तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। दरअसल कहा जाता है कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है और जो नहीं होता है वह दिखता है। भुट्टा पार्टी को भी इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस पार्टी में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा तमाम अफसर शामिल हुए उससे कुछ अलग ही संदेश निकल रहे हैं। विजयवर्गीय न तो मौजूदा समय में विधायक हैं और न ही लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि कहीं उनका यह दौरा अब उनकी प्रदेश में फिर से राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद तो नहीं हैं। विजयवर्गीय ने भुट्टा पार्टी से पहले जिस तरह मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की, उसको देखकर लगता है कि वे प्रदेश में कोई नई राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। साथ ही वे मुख्यमंत्री को यह भी अहसास करा रहे हैं कि उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। हालांकि कैलाश की भुट्टा पार्टी और नेताओं से मुलाकात के तरह-तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि मप्र की राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में चौथी पारी खेल रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह लेने के लिए कई नेता आतुर हो रहे हैं। अब देखना यह है कि मेल-मुलाकात और भुट्टा पार्टी के बाद अगला कदम क्या नजर आता है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 22, पृष्ठ-48, 16 से 31 अगस्त, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

आबादी की राजनीति

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लाया गया जनसंख्या नियंत्रण नीति का प्रस्ताव मात्र शिगूफा है। योगी सरकार जानती है कि इस बार उसका जीतना खटाई में है। यही वजह है कि वह ऐसे अजीबो-गरीब प्रस्ताव ला रही है। लगता नहीं इस नीति से उन्हें कोई फायदा होगा।

● **शिवराज तोमर,** उज्जैन (म.प्र.)

भागो और मौज करो

आम आदमी मेहनत के बाद भी जो सुविधा हासिल नहीं कर पाता, कुछ लोग सरकार को करोड़ों का चूना लगा कर हासिल कर लेते हैं। भागने वालों की इतनी बड़ी सूची है इसका मतलब है कि बैंकिंग प्रणाली मजबूत नहीं है। उधर सरकार इन भगोड़ों को लाने की कोशिश करने का नाटक कर रही है।

● **रूपेश वाजपेई,** जबलपुर (म.प्र.)

महंगाई का दंश

महंगाई की मार से लोगों का हाल बेहाल है। जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ऐसा लगता है जैसे किसी को जनता की चिंता नहीं है। जबकि आलम यह है कि आटे, दाल से लेकर तेल-मसाले तक महंगे हो गए हैं।

● **प्रभू प्रताप वैश्य,** रायपुर

कब साकार होगा सपना

भोपाल और इंदौर के लोग मेट्रो ट्रेन की सवारी करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट दिन पर दिन लंबा खिंचता जा रहा है। भोपाल मेट्रो का पहला रूट 16.05 किमी लंबा है। यह एम्स टू करोंद तक जाता है। फिलहाल रूट निर्माण हो रहा है। अब तक एम्स, होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर, एमपी नगर जैसे क्षेत्र में पिलर खड़े किए गए हैं। वहीं इंदौर में पिलरों का काम अब शुरू हुआ है।

● **तपस्या गर्ग,** भोपाल (म.प्र.)

यह कैसी चौकीदारी

पिछले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे देश के चौकीदार हैं। तब लोगों ने मैं भी चौकीदार नारे को खूब हवा दी थी। लेकिन शायद उनके कहने का अर्थ होगा कि वे पहरेदार हैं, जो हर किसी के फोन, मेल और आवाजाही की पहरेदारी करेंगे! इन दिनों पेगासस वाली खबर तो कम से कम यही बताती है कि यह चौकीदार अब पहरेदारी करने लगा है। पहरेदारी भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि इतनी कि हर बात सुनी जा सके, उसकी हर गतिविधि देखी जा सके। हर सरकार थोड़ी-बहुत निगरानी तो करती ही है। लेकिन यह निगरानी देश पर बाहरी हमले को रोकने, आतंकवादी हमले जैसी बातों के लिए हो तब तक ही ठीक है।

● **रमाशंकर शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

जांच करवाने से गुरेज क्यों...?

इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं, अधिकारियों, पत्रकारों, जजों और मंत्रियों के फोन हैक कर जासूसी करने पर वाद-विवाद जारी है। विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही नहीं चल रही। केंद्र सरकार है कि जासूसी करने के हर आरोप से इनकार कर रही है। फोन टैप करना कोई नई बात नहीं, ऐसा होता रहा है। लेकिन केंद्र के जासूसी के आरोप से इनकार की वजह से बात संदिग्ध हो रही है। चाहे जो भी हो केंद्र सरकार को जांच से भागना नहीं चाहिए।

● **अल्पना नायर,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

सेना-भाजपा और राणे

मोदी मंत्रिमंडल में गत माह हुए विस्तार से पहले खासी चर्चा थी कि शिवसेना एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी संग मुलाकात ने इन चर्चाओं को हवा देने का काम किया था। ठाकरे और संघ के बड़े नेताओं का आपस में मिलना, शिवसेना सांसद संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को सराहना और सेना के एक विधायक द्वारा उद्धव को पत्र लिखकर भाजपा संग गठबंधन की खुली पैरोकारी करना स्पष्ट संकेत थे कि भीतरखाने कुछ न कुछ चल रहा है ऐसा लेकिन हो नहीं पाया। जानकारों का दावा है कि इसकी एक बड़ी वजह शिवसेना के पूर्व नेता नारायण राणे रहे। सेना से बगावत कर भाजपा में शामिल हो चुके राणे से उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत तौर पर खफा बताए जाते हैं। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के अति विश्वस्त राणे को बाल ठाकरे ने 1999 में मनोहर जोशी को हटा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बनते ही राणे के तेवर बदल गए। उन्होंने सेना से इतर अपना राजनीतिक वजूद बनाना शुरू कर दिया था। 2005 में उन्हें शिवसेना से निकाल दिया गया। इसके बाद राणे ठाकरे परिवार के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए।

फिर सपाई होंगे शिवपाल

उप्र विधानसभा चुनाव अब मात्र कुछ माह दूर हैं। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक तापमान प्रतिदिन के हिसाब से चढ़ने लगा है। एक तरफ एंटी इन्कमबेंसी से घबराई भाजपा हर कीमत पर अपनी सत्ता राज्य में बनाए रखने को आतुर है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भाजपा के कमल को सपा की साइकिल से रौंदने की फुल प्रूफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर मुलायम सिंह यादव के गढ़ इटावा तक इन दिनों खासी चर्चा है कि चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश अपने मत और मनभेद दूर कर पाने में सफल हो चुके हैं। खबर गर्म है कि शिवपाल अपनी लड़खड़ाती हुई पार्टी का विलय सपा में करने को लगभग राजी हो चुके हैं। सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लेकिन सीटों के बंटवारे पर रजामंदी न होने के चलते अभी अधर में लटका हुआ है। सूत्रों की मानें तो सपा प्रमुख अखिलेश और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अब आपस में बैठ इस मुद्दे को सुलझाने वाले हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश भाजपा को चुनौती देने की हैसियत रखने वाले छोटे से छोटे राजनीतिक दल संग भी वार्ता करने में जुटे हैं। चर्चा है कि शीघ्र ही सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर संग सपा सीटों का बंटवारा फाइनल करने जा रही है।

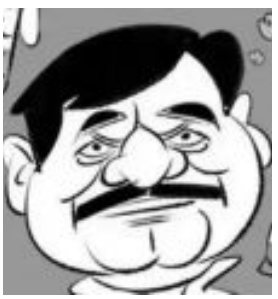

अधर में चिराग, अब बंगला भी खतरे में

लोकजन शक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की मृत्यु बाद विरासत के लिए छिड़ी जंग में पासवान के पुत्र चिराग हाल-फिलहाल बैकफुट पर हैं। एक तरफ उनके सगे चाचा पशुपतिनाथ पारस और तीन अन्य सांसदों ने पार्टी पर अपने अधिकार का दावा पेश कर चिराग के खिलाफ खुली बगावत कर डाली है तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी पशुपति के दावे को एक तरफा स्वीकारते हुए उन्हें एनडीए कोटे से केंद्र में मंत्री बना डाला है। खुद को मोदी का हनुमान कहते न थकते चिराग इस सबके चलते भारी सदमे में बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने वाले चिराग को भाजपा ने नीतीश कुमार के खिलाफ बतौर 'टूल' इस्तेमाल किया और उपयोगिता खत्म होने बाद इस 'टूल' को कबाड़ में डाल दिया है। चिराग को सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी ने उनके चाचा पशुपति को अपना मंत्री बना दे डाला है। अब खबर है कि दशकों से दिल्ली में स्व. रामविलास पासवान का घर रहे सरकारी बंगले 12 जनपथ से भी चिराग को बाहर निकाले जाने की तैयारियां हो रही हैं। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने यह बंगला पशुपति पासवान को एलॉट कर दिया है लेकिन भाई द्रोह के आरोप से बचना चाह रहे पशुपति ने इस बंगले को रिजेक्ट कर डाला है।

सहमे-सहमे भाजपाई सीएम

दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बदले जाने का बना हुआ है। मोदी-शाह के नेतृत्व वाली भाजपा में प्रदेशों के मुख्यमंत्री न बदलने की रवायत अब टूटने लगी है जिसका बड़ा असर वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर काबिज नेताओं पर पड़ा है। 2016-21 तक भाजपा आलाकमान ने केवल गुजरात में मुख्यमंत्री बदला था। अगस्त 2016 में वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को हटाकर पार्टी ने विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब पार्टी नेतृत्व तेजी से अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने में जुट गया है। इसकी शुरुआत गत् मार्च में उत्तराखंड से हुई, जहां यकायक ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर सांसद तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी करा दी गई। जब तीरथ सिंह रावत के विधायक बनने में संवैधानिक अड़चन आती दिखी तो भाजपा ने एक बार फिर बदलाव कर राज्य को पुष्कर सिंह धामी के रूप में नया मुख्यमंत्री दे डाला।

सोरेन पर मंडराता खतरा

कर्नाटक और मप्र में जोड़ जुगत कर अपनी सरकार बनाने के बाद अब भाजपा की नजर झारखंड पर बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने तो सीधे भाजपा पर झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा डाला है। प्रदेश सरकार में शामिल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी भाजपा द्वारा उन्हें भारी रकम और मंत्री बनाने जैसे प्रलोभनों का खुलासा कर प्रदेश की राजनीति में भारी तनाव पैदाकर डाला है। सूत्रों की मानें तो हेमंत सोरेन सरकार को गिराने में एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मुख्य किरदार की भूमिका में हैं। इन महाशय का कुछ अर्सा पहले तक हेमंत सोरेन संग करीबी रिश्ता था जो अब दरक चुका है। इन महाशय पर इन दिनों राज्य की खुफिया पुलिस की कड़ी निगरानी तो है ही इनके कई करीबियों को भी खुफिया एजेंसियों ने अपने रडार में ले लिया है। प्रदेश की राजधानी रांची में सबसे ज्यादा कानाफूसी हेमंत सोरेन सरकार के मुंबई कनेक्शन की है।

कस्तूरी की धमक से सभी परेशान

संत कबीरदास का यह दोहा तो आपने सुना ही होगा...'कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही।' कुछ ऐसी ही स्थिति प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में पदस्थ अफसरों की हो रही है। मृग के अंदर जो कस्तूरी बसती है वह खुशबू देती है लेकिन यहां जिस कस्तूरी की बात हो रही है, वह परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल, व्यावसायिक राजधानी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहां बिना दलाल के दाल नहीं गलती है। वर्तमान समय में इस शहर में दलाली की कमान एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो पूर्व मुख्य सचिव और यहां के कलेक्टर रहे एक आईएएस का दलाल रह चुका है। अब उसने जिले के प्रभारी मंत्री का दामन पकड़ लिया है। मंत्रीजी पहले से ही कड़वे हैं और अब उन्हें नीम का साथ मिल गया है। इससे कड़वापन और बढ़ गया है। इस कड़वेपन से व्यावसायिक राजधानी में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो उठे हैं। बताया जाता है कि माननीय के नाम पर उक्त व्यक्ति अफसरों से जमकर वसूली कर रहा है। यही नहीं अफसरों के माध्यम से वह व्यावसायियों को भी नहीं छोड़ रहा है। स्थिति यह है कि उक्त दलाल से धीरे-धीरे पूरा शहर परेशान हो उठा है। अब उसकी करतूतों की शिकायत सत्ता और संगठन के पास भी पहुंचने लगी है। लेकिन सरकार के सबसे रसूखदार का हाथ उसके ऊपर होने के कारण फिलहाल कोई उसका बाल बांका नहीं कर पा रहा है।

भाभी की मुंह दिखाई की तैयारी

प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में इन दिनों एक सगाई काफी चर्चा में है। इसकी वजह यह है कि जिस व्यक्ति ने सगाई की है, उन्होंने आजीवन शादी न करने की बात कही थी। कुछ साल पहले तक प्रदेश की राजनीति में बड़ी हैसियत रखने वाले नेताजी की रंगीन मिजाजी की चर्चा वैसे तो खूब हुआ करती थी, लेकिन किसी को इसका तनिक भी भान नहीं था कि वे विवाह बंधन में बंधेंगे, वह भी अधेड़ उम्र में। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। संघ पृष्ठभूमि के इन जनाब की शिक्षा-दीक्षा तो वैसे काशी विश्वनाथ के शहर में हुई है, लेकिन उनकी कर्मभूमि देश का हृदय प्रदेश रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश लेकर प्रदेश की राजनीति में आए ये जनाब कुछ ही दिन में गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे और सुविधा भोगी बन बैठे। संगठन में उच्च पद होने के कारण उनके सामने वह सभी चीजें परोसी गईं जो नैतिकता से परे थीं। सूत्र बताते हैं कि जनाब ने उसका तनिक भी परहेज नहीं किया। बताया जाता है कि उन पर लगने वाले दाग से उन्हें बचाने के लिए प्रदेश के बाहर भेज दिया गया। वर्तमान समय में उनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों के साथ उक्त नेता ने अब वैवाहिक जीवन की भी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है और अपने गृह राज्य में सगाई कर ली है। उधर, हृदय प्रदेश में उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है जब वे भाभी के साथ आएं और उनकी मुंह दिखाई की रस्म पूरी की जाए।

सुशासन संस्थान में अनुशासन नहीं

मप्र में सरकार ने सुशासन संस्थान की स्थापना की है। लेकिन इन दिनों इस संस्थान में अनुशासन पूरी तरह गायब है। इसकी वजह यह है कि संघ के कहने पर सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को इस संस्थान की कमान सौंप दी है, जो यहां अपनी मनमानी पर उतर आया है। नैतिकता की बड़ी-बड़ी बात करने वाला उक्त व्यक्ति अफसरों से भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहा है। इसकी वजह से सुशासन संस्थान में अनुशासन गायब है। सूत्रों का कहना है कि उक्त व्यक्ति के कारण कई अफसर नाराज चल रहे हैं और छुट्टी लेकर घर बैठ गए हैं। इससे संस्थान की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। बताया जाता है कि अपनी कलाकारी के लिए पहले से ही ख्यात इस व्यक्ति ने सुशासन संस्थान में आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। संस्थान में अपने कमरे को फाइव स्टार साज-सज्जा करवाना शुरू कर दिया है। विजिटर और वेटिंग रूम को भी आकर्षक ढंग से सजवाया जा रहा है। वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साहब ऐसा क्यों करवा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि संघ ने जिस व्यक्ति पर भरोसा करके सुशासन संस्थान की कमान दिलवाई है, उक्त व्यक्ति लक्ष्मीजी का बड़ा भक्त है। यहां अन्य कहीं से लक्ष्मीजी के आगमन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्होंने यह रास्ता निकाला है। देखना यह है कि साहब और क्या-क्या रास्ते निकालते हैं।

ऐसी सादगी किस काम की

यह शेर तो आपने सुना होगा- 'इस सादगी पर कौन न मर जाए, वे कत्ल भी करते हैं और इल्जाम भी नहीं।' कुछ ऐसी ही स्थिति मालवा रेंज के पुलिस मुखिया की भी है। साहब बेहद ईमानदार अफसर हैं, इसमें कोई शक नहीं। अपनी ईमानदार और सादगीपूर्ण छवि के कारण वे कठोर भी नहीं हैं। इसका फायदा उनके मातहत और अपराधी जमकर उठा रहे हैं। साहब जिस रेंज में पदस्थ हैं, उस रेंज में इन दिनों आपराधिक मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में बड़े-बड़े अपराध हो रहे हैं। जबकि साहब इस क्षेत्र में डीआईजी के पद पर भी रह चुके हैं। यानी साहब के पास क्षेत्रीय अनुभव की कोई कमी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि साहब जबसे इस रेंज के बड़े अधिकारी बने हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था से लगभग मुंह ही मोड़ लिया है। इस कारण यहां आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। साहब की निष्क्रियता को देखते हुए उनके नीचे के अफसर भी निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन क्षेत्र में घटित होने वाले आपराधिक मामले पुलिस की निष्क्रियता को राजधानी तक पहुंचा रहे हैं।

हम सोचते ही रह गए...

फिल्म शक्ति का यह गाना... 'जाने कैसे, कब, कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया' तो आपने सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ विगत दिनों मप्र में भी हुआ। यहां 6 टोल नाकों के लिए टेंडर निकाले गए। इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल हुई, जिसको देखकर अफसरों को लगा कि यह कंपनी इसमें शामिल होकर क्या करेगी। क्योंकि कंपनी के पास अर्थव्यवस्था की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एमपीआरडीसी के अफसर अपनी सोच की उधेड़बुन में लगे रहे और कंपनी ने तय रेट से कहीं अधिक उच्च बोली लगाकर सभी 6 टेंडर उठा लिए। अफसरों को यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि उक्त कंपनी ने इतनी बड़ी रकम कहां से जुगाड़ की। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि कंपनी तो मात्र चेहरा भर है। उसके पीछे कई माननीयों का मान है। बताया जाता है कि कंपनी में इन्हीं माननीयों की रकम लगी हुई है। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश के टोल नाकों पर कमाई को देखते हुए माननीयों ने कंपनी को आगे करके यह खेल खेला है। गौरतलब है कि कई योजनाओं-परियोजनाओं में भी यह खेल पहले से चल रहा है।

मेरा ट्विटर अकाउंट बंद कर वे राजनीतिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहे हैं। एक कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने का बिजनेस बना रही है। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मैं इसे पसंद नहीं करता। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

● **राहुल गांधी**

धरती माता एक दाने के बदले हमें चार सौ गुना अधिक फसल देती है, लेकिन हम उसके पेट में भी रसायन के रूप में जहर दे रहे हैं। लुभावने विज्ञापनों ने किसानों को गुमराह कर रखा है। जैविक खेती को हमें गहराई से समझना होगा। यह जैविक नहीं, दैविक खेती है। आदिकाल से हम जैविक खेती ही करते आ रहे हैं। परंपरागत खेती इसी का नाम है।

● **भैयाजी जोशी**

बार्सिलोना मेरे घर जैसा है। यहां पर 21 साल बिताने के बाद इसे छोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, पर स्पेनिश लीग के वित्तीय नियमों के कारण क्लब के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे जारी रखना संभव नहीं था। हालांकि मुझे भरोसा था कि मैं क्लब के साथ बना रहूंगा।

● **लियोनेल मेसी**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं लेकिन जिस बिहार ने उन्हें 39 सांसद दिए, उस राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे। ये बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझें।

● **तेजस्वी यादव**

लिव-इन काफी मजेदार है। घर में हर समय लोग होते हैं, हम इस स्टेज को एंजॉय कर रहे हैं। शादी बहुत अलग है और हम अभी ऐसी किसी चीज में कदम नहीं रखना चाहते हैं, जो हमें तनाव दे सके। हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, और फिर दो साल बाद फैमली की प्लानिंग करना चाहते हैं। फिर एक बच्चा चाहते हैं, और फिर यह और वह। हम चाहते हैं कि शादी से पहले सब कुछ सेट हो जाए। जब शादी होती है तब तक सब कुछ सेट होना चाहिए, और फिर जब भी बच्चा होता है, जो कुछ भी होता है। उम्मीद है कि अगले साल तक हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। घर सेट होने के बाद मैं और वरुण शादी के लिए जा रहे हैं। हमारा बस एक छोटा सा सपना है कि हमारे पास एक सुंदर सा घर हो। हम बस इसे बनाना चाहते हैं। हम उस गोल के लिए ही काम कर रहे हैं। हम अपने सपने और अपने काम को लेकर काफी पैशनेट हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें मजबूत बनाती हैं।

● **दिव्या अग्रवाल**

वाक्युद्ध

राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार ने मानसून सत्र में विपक्ष के नेताओं की एक नहीं सुनी। न तो विपक्षियों की मांगों पर विचार किया गया और न ही उन्हें बोलने दिया गया। सदन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार पूरी तरह दोषी है।

● **प्रियंका चतुर्वेदी**

भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का बिगड़ा रूप पहली बार लोगों के सामने आया है। सदन में विपक्ष के नेताओं ने आसंदी का जिस तरह अपमान किया है, वह निंदनीय है। महिला मार्शलों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। अब विपक्ष की पोल जनता के सामने आ गई है। लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं दिखा।

● **पीयूष गोयल**

तबादला बना उद्योग

मप्र में इन दिनों तबादलों का मौसम है। इस मौसम में अधिकारी-कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार तबादला कराने के जतन में लगे हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए दलाल सक्रिय हो गए हैं और सुविधा को उद्योग बनाने में जुट गए हैं। ऐसे ही दलालों की करतूत सामने आई है। मंत्रियों से संबंध रखने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के यहां चपरासी रह चुका है तो दूसरा सिलवानी (रायसेन) से भाजपा विधायक रामपाल सिंह का कुक था। ये दोनों मिलकर दो कम्प्यूटर ऑपरेटर से लेटर टाइप कराते थे। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति की मदद से फर्जी डिस्पैच नंबर डालकर कर्मचारी से रुपए खाते में डलवाते थे। चिट्ठी और नोटशीट तैयार होने के बाद इसे वल्लभ भवन की आवक-जावक शाखा के बॉक्स में डालकर प्राप्ति रसीद ले लेते थे। कर्मचारियों को शक न हो, इसके लिए आरोपी उन्हें मंत्री-विधायकों के बंगलों के बाहर बुलाकर डील करते थे।

आरोपियों के पास से पुलिस ने विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की खाली नोटशीट, लेडर हेड बरामद किए हैं, जिन्हें आरोपियों ने जनप्रतिनिधियों को बंगले से चोरी किया था। आरोपी अब तक 30 कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए प्रपोजल भेज चुके थे। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल धाकड़ ने बताया कि हाल में शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ विधायक, सांसदों के लेटर हेड पर स्थानांतरण के प्रस्ताव सीएमओ वल्लभ भवन में प्राप्त हो रहे हैं। शिकायत की जांच में पाया गया कि सांसद, विधायक के लेडर हेड, नोटशीट फर्जी हैं। पुलिस ने जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रपोजल भेजा गया था, उन्हें नोटिस देकर पूछताछ शुरू की। जिससे पूरे मामले का खुलासा हो सका।

पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, उनमें रामप्रसाद राही जो सुनहरी बाग जवाहर चौक का रहने वाला है। जनप्रतिनिधियों के बंगले में वह कुक का काम करता है। वह फर्जी लेटर हेड तैयार करता था। खुद ही विधायक, सांसद के हस्ताक्षर कर प्रपोजल संबंधित विभाग को भेज देता था। लखनलाल ग्राम कानीबड़ा उपयपुरा, रायसेन का रहने वाला है। फर्जी लेटर हेड में डिस्पेच नंबर अंकित करने का काम करता था। इसके साथ ही ट्रांसफर करवाने वाले से अपने खाते में रकम जमा कराता था। रामकृष्ण राजपूत टिमरनी, हरदा का रहने वाला है। वह कम्प्यूटर ऑपरेटर है। लेटरहेड में वह ही टाइपिंग करता था। इसके लिए उसे कमीशन मिलता था। दशरथ राजपूत खामापडवा, हरदा का रहने वाला है। कम्प्यूटर ऑपरेटर है। वह रामकृष्ण के साथ मिलकर नोटशीट में प्रपोजल तैयार करता था। रामगोपाल पाराशर मॉडल स्कूल परिसर टीटी नगर, भोपाल में रहता है। वह शिक्षा विभाग में सरकारी भृत्य है। लेटरहेड उपलब्ध कराने का काम करता था।

ये मामले दर्शाते हैं कि प्रदेश में किस तरह तबादला उद्योग चल रहा है। कांग्रेस शासनकाल में भाजपा आरोप लगाती रही कि तबादला उद्योग चलाया जा रहा है और अब कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है। दरअसल, प्रदेश में तबादला एक बड़े उद्योग के रूप में तब्दील हो चुका है। स्थिति यह है कि अधिकारी और कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पाने के लिए लाखों रुपए चढ़ाने पड़ रहे हैं। लाखों रुपए देकर पद पाने वाला अपनी मनमानी करता है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्रियों के बंगले से चलने वाले इस गोरखधंधे की पोल खुलकर सामने आ गई है। तभी तो मंत्रियों के बंगलों पर काम करने वाले लोग इस धंधे में जुट गए हैं। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा गिरोह का सरगना रामगोपाल पाराशर है। वह मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले में काम कर चुका है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि मंत्री के बंगले से ही उसने विधायक रामपाल सिंह का एक खाली लेडर हेड चोरी किया था। इसके अलावा कई अन्य जनप्रतिनिधियों के भी फर्जी लेडर हेड बनाए हैं। गिरफ्तार आरोपी रामप्रसाद राही ने विधायक रामपाल सिंह के फर्जी लेडर हेड, नोटशीट से अकेले छतरपुर के रहने वाले 27 कर्मचारियों की अनुशंषा की है। एएसपी धाकड़ ने बताया कि रामप्रसाद ने सबसे अधिक नोटशीट भेजी हैं। वह विधायक रामपाल सिंह के बंगले में कुक रह चुका है। प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े लोग अब सांसद, विधायक और मंत्रियों के फर्जी सिफारशी पत्र बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में अभी तक मंत्री मोहन यादव, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र सिसोदिया के नाम से फर्जी सिफारशी पत्र जांच में पकड़े जा चुके हैं।

● **विकास दुबे**

हर मंत्री के यहां लग रही बोली

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में इस समय तबादला उद्योग चल रहा है। हर मंत्री के यहां मनमाफिक तबादले की बोली लगाई जा रही है। निर्माण विभाग से जुड़े एक मंत्री के पीए ने तबादले के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है। वहीं इंदौर से जुड़े एक मंत्री के यहां भी जमकर लेनदेन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जवाबदारी वाले विभाग में मंत्रीजी ने तो एक सब इंजीनियर को अपना पीए बना लिया है। दोनों स्कूल सखा हैं। पीए साहब का हाईवे पर आलीशान मकान बन रहा है। बताया जा रहा है, नैपकिन मशीन में उन्होंने जमकर कमाई की है। अब वे तबादले कराकर कमाई कर रहे हैं। प्रदेश में होने वाले निर्माण की निगरानी करने वाले विभाग में सालभर से भले ही एक टेंडर भी नहीं निकला है लेकिन इस विभाग के मंत्रीजी ईएनसी को स्थापित करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश के कमाऊ विभागों में से एक विभाग के मंत्रीजी के यहां भी एक ऐसे व्यक्ति तैनात हैं जो मंत्रीजी के नाम पर जमकर कमाई कर रहे हैं। वहीं एक महिला मंत्री के यहां भी पंडित जी के हाथ में कमाई की जिम्मेदारी है। वे मंत्री के नाम पर जमकर कमाई कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में अपने उटपटांग कार्यों के लिए चर्चा में रहने वाले एक मंत्रीजी के भाई ने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। जबकि ग्वालियर-चंबल संभाग से आने वाले एक मंत्रीजी अपने भाई से परेशान चल रहे हैं। दरअसल, भाई ने विभाग में अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है और जमकर कमाई कर रहे हैं। वैसे मंत्रीजी ने कमाई के लिए अपना मनपसंद स्टाफ भी रखा है।

मप्र में खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। पृथ्वीपुर और जोबट कांग्रेस और बाकी दो सीटों पर भाजपा का कब्जा था। भाजपा की रणनीति है कि चारों सीटों को जीतकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आधार मजबूत किया जाए। इसलिए भाजपा ने चुनावी घोषणा से पहले ही अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। उधर, कांग्रेस भी दमोह उपचुनाव से उत्साहित है। लेकिन फिलहाल चुनावी तैयारी में काफी पीछे है।

2023 की बिछने लगी चौसर

दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा काफी सजग और सतर्क है। इस बार पार्टी किसी गलतफहमी में नहीं दिख रही है। इसलिए चुनावी घोषणा से पहले ही उपचुनाव के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दी है। अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना का कहर कम होने से चुनाव होने की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए इन सीटों पर टिकट के दावेदारों की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। लेकिन, अभी टिकट के फैसले के पहले सत्ता-संगठन इन इलाकों का पूरा मिजाज भांपना चाहते हैं। इसलिए स्थानीय व प्रभारी मंत्रियों से लेकर संगठन के पदाधिकारियों तक को इन सीटों पर दौरों पर भेजना शुरू कर दिया गया है। सत्ता-संगठन इन सीटों पर टिकट के फैसले से पहले ही पूरी स्थिति का आंकलन करना चाहते हैं। इस कारण हर बूथ तक माइक्रो स्टडी की शुरूआत कर दी गई है।

खंडवा लोकसभा और रैगांव, पृथ्वीपुर तथा जोबट विधानसभा उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही भाजपा ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऊपर प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी होगी। दरअसल, मप्र भाजपा में ये पांच नेता कुशल रणनीतिकार के साथ ही लोकप्रियता के शिखर पर भी हैं। इसलिए पार्टी चुनाव में इनकी लोकप्रियता को भुनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो उपचुनाव जीतने में माहिर खिलाड़ी हैं। पार्टी में शिवराज ऐसा चेहरा हैं जिसे प्रदेश की जनता अपना मानती है। इसलिए पार्टी हर चुनावी मोर्चे पर उन्हें आगे रखती है। वहीं वीडी शर्मा मप्र भाजपा के लिए शुभंकर बन गए हैं। उनके पास युवाओं की बड़ी टीम है। भाजपा ने उन्हें कई मोर्चों पर परख कर बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसलिए पार्टी को उनसे बड़ी उम्मीद है। तोमर और सिंधिया भाजपा में वह चेहरा हैं जो किसी भी मोर्चे पर काम कर सकते हैं। जबकि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा मप्र के अलावा कई राज्यों में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके हैं। इसलिए उपचुनाव में इन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।

उपचुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी सिंधिया को एक बार फिर सक्रिय करने जा रही है। पिछले माह ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा-निमाड़ का दौरा छोड़ दिल्ली चले गए थे, जहां उन्हें केंद्रीय मंत्री की शपथ लेना थी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया अब फिर से अपने दौरे शुरू कर रहे हैं। वे 16 अगस्त से मालवा और निमाड़ के चार शहरों का दौरा करेंगे और इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सिंधिया के कार्यालय से उनका तीन दिनी दौरा कार्यक्रम आने के बाद भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिंधिया तीन दिनी दौरे के दौरान रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे, इसलिए यहां के प्रमुख नेताओं को दौरे की जवाबदारी सौंपी जा रही है। सिंधिया दिल्ली से सीधे इंदौर आएंगे और फिर यहां से देवास रवाना हो जाएंगे। देवास के कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे शाजापुर भी जाएंगे

दांव पर शिव-नाथ की साख

मप्र में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। दावेदारों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं दोनों पार्टियों में मंथन तेज हो गया है। लेकिन एक बात तो यह है कि उपचुनावों में प्रत्याशी कोई भी क्यों न हो साख तो शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की ही दांव पर होगी। भाजपा जहां शिवराज सरकार के भरोसे है, तो कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने कार्यकाल के ओबीसी वर्ग को आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी पर दांव लगाने को तैयार है। हालांकि लोकसभा की एक और विधानसभा की तीन सीटों पर जीत-हार से सत्ता की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा।

और इसी दिन रात इंदौर आकर विश्राम करेंगे। दूसरे दिन 17 अगस्त को पूरे दिन वे इंदौर में ही रहेंगे। 18 अगस्त को वे खरगोन में रहेंगे और इसी दिन रात को इंदौर आ जाएंगे।

प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में दावेदार कतार में लग चुके हैं। चार सीटों के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था। यहां से 2019 के चुनाव में नंदकुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे और अब भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव में नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन को टिकट दिया जाए। हालांकि यहां पर भाजपा में अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा यहां कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसलिए संभावनाओं पर मंथन चल रहा है। वही रैगांव विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में जुगल किशोर बागड़ी ने चुनाव जीता था और भाजपा यहां पर बागड़ी के बड़े बेटे पुष्पराज को टिकट देने की तैयारी में है। टिकटों को लेकर भाजपा में अभी मंथन का दौर जारी है। अब कांग्रेस के कब्जे वाली 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। पृथ्वीपुर सीट पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा जोबट विधानसभा सीट पर कलावती भूरिया के रिश्तेदार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को टिकट देने की तैयारी में हैं। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। हो सकता है, जिन सीटों पर पार्टी का कब्जा था उसी परिवार के सदस्य को उपचुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए।

फिलहाल सत्ता-संगठन के लिए सबसे अहम खंडवा लोकसभा सीट है। यह सीट पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के कोरोना से निधन के चलते खाली हुई है। इस सीट पर नंदकुमार के बेटे हर्ष की दावेदारी है। लेकिन, साथ ही क्षेत्रीय पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और इंदौर के नेता कृष्ण मुरारी मोघे के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से यहां पर पूर्व सांसद अरुण यादव का नाम चल रहा है। भाजपा इस क्षेत्र में मंत्रियों व अन्य नेताओं को सक्रिय कर चुकी है। मंत्री कमल पटेल, ऊषा ठाकुर सहित अन्य यहां दौरे कर चुके हैं। यहां टिकट का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सलाह करके उनकी रजामंदी के हिसाब से ही होगा। उपचुनाव वाली तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए रस्साकशी के हालात हैं। कोरोना के कहर के कारण उपजे नकारात्मक माहौल को कवर करने के लिए संगठन की टीमें इन सीटों वाले इलाकों में काम कर रही हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

खंडवा नाक का सवाल

खंडवा लोकसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। भाजपा जहां अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस इसे कब्जाने की कोशिश कर रही है। खंडवा उपचुनाव को लेकर भाजपा में अंदर ही अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है। भाजपा यहां से उम्मीदवार घोषित करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, फिर भी यहां से दमदार उम्मीदवार के नाम पर विचार कर रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। टिकट के लिए मुख्य मुकाबला मोघे, अर्चना और हर्ष के बीच ही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर और संगठन का एक धड़ा नंदू भैया के पुत्र हर्ष चौहान को यहां से उम्मीदवार बनाने के पक्ष में हैं, ताकि सहानुभूति के वोटों के साथ-साथ भाजपा के वोट भुनाए जा सके, लेकिन जिस तरह से कृष्णमुरारी मोघे और अर्चना चिटनीस हर्ष के पीछे लगे हैं, उससे हर्ष की राह भी आसान नहीं है। हर्ष चौहान के खंडवा विधानसभा में बंधे रहने के कारण वे दूसरी विधानसभा में कितने वोट ला पाते हैं, उसमें संशय हैं। मोघे जैसे कद्दावर नेता संघ और संगठन के भरोसे यहां से दावेदारी कर रहे हैं, वहीं कोरोना काल में उन्होंने सक्रिय रहकर बता दिया था कि वे भी खंडवा उपचुनाव में एक सशक्त दावेदार हैं। मोघे पहले खरगोन से सांसद रह चुके हैं और उनका खरगोन, भीकनगांव और बड़वाह में अच्छा होल्ड है। खंडवा तथा बुरहानपुर के कुछ नेता भी उनके साथ हैं, लेकिन वे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अर्चना चिटनीस की बुरहानपुर, नेपानगर में अच्छी पैठ हैं और वे नंदू भैया के दिवंगत होने के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रही हैं और प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

ओबीसी आरक्षण बनेगा चुनावी मुद्दा

जिन चार क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां ओबीसी मतदाता अधिक हैं। इसलिए पार्टियों का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण चुनावी मुद्दा बनेगा। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने का असर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। यद्यपि पिछड़ा वर्ग महासभा का पहला प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक दिखाई नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक पटल पर हलचल जरूर दिखाई दे रही है। कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाया था। लेकिन, हाईकोर्ट ने क्रियान्वयन पर रोक लगाई हुई है। कमलनाथ की कोशिश पिछड़ों के बीच शिवराज सिंह चौहान से आगे निकलने की है। जबकि वर्ष 2003 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मप्र में भाजपा की पूरी राजनीति अन्य पिछड़ा वर्ग के चेहरे पर चल रही है। उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान अन्य पिछड़ा वर्ग के ही हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मप्र हाईकोर्ट में आंकड़े प्रस्तुत कर यह दावा किया है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। सरकार ने यह दावा वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया है।

राशन के झोले में झोल

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा कोशिश रही है कि प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित हो। लेकिन उनके चौथे कार्यकाल में देखा जा रहा है कि उनकी सरकार के ही लोग उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। इसमें खाद्य विभाग के मंत्री बिसाहूलाल सिंह तो सारी हदें पार कर रहे हैं। पहले गरीबों को राशन वितरण करने के लिए थैलों की संख्या 5 गुना करने पर अड़े रहे और जब उसमें दाल नहीं गली तो अब अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।

या कहावत हम सभी ने अक्सर सुनी है कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन मप्र में माननीयों की स्थिति यह है कि समुंद्र में बैठे होने के बाद भी वे बूंद-बूंद बटोरने में लगे हुए हैं। इस मामले में गरीबों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ताजा मामला गरीबों के राशन वितरण के लिए इस्तेमाल होने वाले झोले (थैले) से जुड़ा हुआ है। दरअसल, प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह अपने चहेते व्यवसायी को झोले का टेंडर दिलाना चाहते थे, लेकिन उसका मूल्य अधिक होने के कारण टेंडर दूसरी कंपनी को मिल गया। ऐसे में अब अधिकारियों पर गुस्सा निकाला जा रहा है।

दरअसल, कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों को हर माह 10 किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त को अन्न उत्सव से हो गई है। मप्र में उस दिन एक साथ 30 लाख परिवारों को मुफ्त अनाज बांटा गया। इसलिए उस समय 30 लाख थैले सप्लाई किए गए। शेष थैलों की सप्लाई जल्द होने वाली है। क्योंकि इसके बाद भी यह अभियान जारी है और मप्र में 1 करोड़ 11 लाख 32 हजार लोगों को 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। यह अनाज एक थैले में दिया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में गरीबों को अनाज बांटने के लिए 1 करोड़ 20 लाख थैलों का टेंडर निकाला गया था। इसमें इंदौर की एक कंपनी ने 4 टेंडर डाले थे, जबकि दिल्ली की भी एक कंपनी इस टेंडर में शामिल हुई थी। इंदौर वाली कंपनी ने तीन-चार टेंडर डालकर दांव खेला था, जिसमें उन्होंने 19 रुपए से लेकर 19.50 रुपए तक का न्यूनतम रेट प्रति थैला रखा था, जबकि दूसरी और कंपनियों की दरें 14.50 रुपए से 15 रुपए तक की थीं। न्यूनतम दर जबकि 13.99 रुपए थी। इसलिए दिल्ली वाली कंपनी को 14 रुपए प्रति थैले की दर से 1 करोड़ 20 लाख थैलों का टेंडर मिल गया।

टेंडर होने के बाद थैलों की गुणवत्ता की शिकायत भी कोर्ट में की गई। इस पर टेंडर पाने वाली कंपनी के थैले की गुणवत्ता जांचने के लिए सीपेट से जांच भी कराई गई। जिसमें थैले मानक स्तर के निकले। लेकिन यह बात मंत्रीजी को पसंद नहीं आ रही है। वे उसमें मीनमेख निकाल रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि मंत्रीजी ने इंदौर की कंपनी को थैले खरीदने का टेंडर दिलाने के लिए मोटी रकम ले रखी है। इंदौर के वेंडर ने तीन-चार टेंडर सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी चाहते हैं कि जैसे भी हो थैले सप्लाई करने वाली दिल्ली की कंपनी को घेरा जाए। इसके लिए तरह-तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उधर, 1 करोड़ 20 लाख थैलों के भुगतान का भी मामला फंसा हुआ है। इस थैलों की रकम का भुगतान कौन करेगा, इसे अभी सरकार ने तय नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि इन थैलों का भुगतान वेयरहाउस लॉजिस्टिक व कॉरपोरेशन करेगा। यह खबर मिलते ही कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल लोधी ने एमडी तरुण पिथोड़े को वॉट्सएप पर मैसेज किया है कि भुगतान से संबंधित नस्ती हमें भी अवलोकनार्थ भेजें। हालांकि इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब पिथोड़े को फोन लगाया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। वहीं लोधी का कहना है कि पेमेंट हमारे विभाग से होना है, इसलिए अवलोकनार्थ नस्ती मांगी है।

उधर, गरीबों के राशन वितरण में किस तरह का भ्रष्टाचार होता रहा है, इसका खुलासा थैले की खरीदी प्रक्रिया में सामने आ गया है। पहले मंत्री ने अपनी चहेती कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए मोटी रकम ली, अब वेयरहाउस लॉजिस्टिक व कॉरपोरेशन के अध्यक्ष की भी मंशा कुछ ऐसी ही है। ये मामले यह दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुशासन को किस तरह उनके ही लोगों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश के हर गरीब की भूख मिटाने के अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही लोग उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

ईमानदार अफसर पर लगाई जा रही तोहमत

अपनी पसंद की कंपनी को टेंडर दिलाने में विफल रहे मंत्रीजी अब विभाग के अफसरों को घेरने में जुट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि विभाग के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने धर्म के व्यवसायी की कंपनी को थैले खरीदने का टेंडर दिलवाया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि दिल्ली की जिस कंपनी को टेंडर मिला है, उसके ऑनर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इत्तेफाक से खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव भी इसी समुदाय से हैं। इसलिए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि उक्त अफसर ईमानदार छवि के हैं। उन पर कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं। फिर भी उनकी साफ-सुथरी छवि को धूमिल करने के लिए संघ के दिल्ली कार्यालय से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं तक यह शिकायत की जा रही है कि उन्होंने गरीबों को राशन बांटने वाले थैले का टेंडर अपने ही समुदाय के एक व्यक्ति को दिलवा दिया है। जबकि मंत्रीजी और शिकायत करने वालों को यह कौन बताए कि जब टेंडर डाला जाता है तो वहां जाति-धर्म का जिक्र नहीं होता है।

कबाड़ हुआ 70 करोड़ का विमान

अब 90 करोड़ के जेट पर नजर

मप्र की माली हालत किसी से छुपी नहीं है। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। आम जनता पर बेतहाशा टैक्स लगाया जा चुका है। मप्र के आम नागरिकों को 1 लीटर पेट्रोल पर सभी प्रकार के टैक्स के अलावा 5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त देना पड़ रहा है। लोगों को मनमाने बिल भेज दिए हैं ताकि सरकारी खजाने में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। ऐसी स्थिति में सरकार 90 करोड़ रुपए की लागत से जेट कंपनी का विमान खरीदने की तैयारी में लगी हुई है। सवाल उठता है कि बेतहाशा कर्ज में डूबे होने के बावजूद सरकार 90 करोड़ रुपए का विमान क्यों खरीद रही है। विमान खरीदने की सरकारी कोशिश की प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तो चर्चा है ही साथ ही कर्मचारी भी नाराज हैं कि सरकार आम जनता की समस्या को दरकिनार कर यह कदम उठा रही है।

आपने गरीबी में आटा गीला वाली कहावत तो पढ़ी और सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ मप्र सरकार के साथ हो रहा है। यानी सरकार हर माह कर्ज लेकर काम चला रही है, लेकिन उसके सामने नित नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इस समय बड़ी समस्या है एक अदद सरकारी विमान की। पिछले सालों में प्रदेश सरकार ने जो 70 करोड़ का विमान खरीदा था आज वह कबाड़ बन गया है। ऐसे में अब मप्र सरकार नया विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 9 सीटर जेट विमान खरीदने की योजना बनाई है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में मप्र 2 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार ने विभागों को मितव्ययता बरतने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि सरकार नया विमान खरीदने जा रही है। जबकि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने 70 करोड़ रुपए में जो विमान खरीदा था, वह ग्वालियर एयरपोर्ट पर कबाड़ की शक्ल में पड़ा हुआ है। दरअसल, मई में प्रदेश में कोरोना जब अपने पीक पर था, तब रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी शुरू हो गई थी। सरकार ने अस्पतालों में इंजेक्शन पहुंचाने के लिए सरकारी हेलिकॉप्टर और स्टेट प्लेन का इस्तेमाल शुरू किया था। यह विमान 6 मई को जब गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर पहुंचा था, तभी ग्वालियर स्थित महाराजपुरा एयरबेस के रनवे पर बैरियर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कॉकपिट के आगे का हिस्सा, प्रोपैलर ब्लैड, प्रोपैलर हब और व्हील क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके बाद से विमान वहीं खड़ा है। अमेरिका की जिस कंपनी से सरकार ने विमान खरीदा था, उसने कोरोना संक्रमण को देखते हुए विमान सुधारने के लिए इंजीनियर भेजने से इंकार कर दिया था।

बाद में कंपनी ने सरकार को बता दिया कि इस विमान की मरम्मत नहीं की जा सकती। यदि मरम्मत होगी तो भी कंपनी की कोई गारंटी नहीं होगी। स्टेट प्लेन खराब होने की वजह से सरकार किराए का विमान लेकर काम चला रही है। विमान के किराए पर ज्यादा खर्च होने के कारण सरकार ने नया विमान खरीदने की तैयारी शुरू की है। वहीं सरकार खराब पड़े विमान को बेचने को तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। वर्तमान में सरकार के पास दो हेलिकॉप्टर हैं, जिसमें एक खराब है, उसे भी बेचने की तैयारी की जा रही है। पिछले साल अगस्त में नया विमान खरीदने से पहले मप्र सरकार ने पुराने विमान एयर किंग-200 को गुजरात की एक कंपनी को 8 करोड़ में बेच दिया था। उस विमान को मप्र सरकार ने 2002 में एक अमेरिकी कंपनी से खरीदा था। खास बात यह है कि वह विमान 18 साल सरकार के बेड़े में शामिल रहा था, जबकि पिछले साल खरीदा गया नया विमान एक साल भी उड़ान नहीं भर पाया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

यह अपने आप में काफी मजेदार और अनुसंधान के योग्य आंकड़ा है। नया विमान 70 करोड़ में खरीदा और पुराना अभिमान 8 करोड़ में बेच दिया। खरीदने वाली कंपनी गुजरात की है। इसके पहले सरकार एक हेलीकाप्टर भी बेच चुकी है। प्रदेश सरकार के पास 2013 में खरीदा हुआ एक हेलीकॉप्टर बचा है। ऐसे में नया विमान आने के बाद सरकारी हवाई बेड़े में एक विमान और एक हेलीकाप्टर हो जाएंगे।

जो विमान कबाड़ बन गया है, वह दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस क्लास विमान माना जाता है। किंग्स एयर क्राफ्ट विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह मीडियम रेंज होने के कारण किसी भी जगह आसानी से उतारे जाने के कारण बिजनेसमैन ग्रुप की पहली पसंद है। किंग एयर 250 इंटीरियर और सीटों को बहुत ही तैयार व सुसज्जित किया गया है जिन्हें आसानी से झुकाया, गिराया और वापस खड़ा किया जा सकता है। इसके अंदर की बनावट ऐसी है जो एक आलीशान क्लब में तब्दील हो जाती है, जहां बिजनेस मीटिंग्स या दोस्तों के साथ पार्टी हो सकती है। किंग एयर 250 और सुपर किंग एयर फैमिली को 1976 से बनाया जा रहा है जो इस क्लास के एयर क्राफ्ट में लगने वाला सबसे लंबा टाइम है। इस एयर किंग की खासियत यह भी है कि यह इस रेंज के अन्य विमानों की तुलना में ज्यादा बड़ा और खूबसूरत दिखता है। किंग एयर 250 बीचक्राफ्ट जैसा दिखता है जो सभी टॉस्क अपने लेवल के एयर क्राफ्ट की तुलना में बेहतर साबित होता है। यह मीडियम रेंज के दूसरे विमानों से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यह कस्टमर के आराम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किंग एयर 250 की एक घंटे की ट्रिप की शुरुआती कीमत 1400 डॉलर होती है। डुअल फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक अलर्ट और भिड़ने की स्थिति से आगाह कर सकता है। लेकिन यह विमान साल भर भी नहीं चल सका। अब सरकार फिर से नया विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। एक तरफ प्रदेश में पैसों की किल्लत के कारण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार नया विमान खरीदने की कोशिश कर रही है।

● **प्रवीण कुमार**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि तय समय के भीतर किसानों को क्लेम नहीं मिलता है, तो बीमा कंपनियों को 12 फीसदी ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जब इसका प्रावधान किया गया हो। दरअसल, बीमा के मकड़जाल को कोई समझ नहीं पा रहा है।

बीमा का मकड़जाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन बीमा कंपनियों के लिए यह योजना फायदे का सौदा साबित हुई। पांच साल में इन कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर 1,26,521 करोड़ रुपए जमा कराए गए, जबकि कंपनियों ने नुकसान के एवज में 87,320 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यानी कंपनियों ने लगभग 69 फीसदी मुआवजे का भुगतान किया और लगभग 31 फीसदी बचत की। कृषि पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह आंकड़े दिए गए हैं। समिति को यह आंकड़े कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने उपलब्ध कराए हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन पांच सालों में 7.25 करोड़ किसानों को मुआवजा दिया गया है। समिति की इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े अप्रैल 2016 से लेकर 14 दिसंबर 2020 के बीच के हैं। इस दौरान किसानों ने फसल बीमा के लिए 26.99 करोड़ आवदेन जमा कराए और 23.54 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कराया।

चूंकि किसानों को कुल प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत (खरीफ सीजन) और 2 प्रतिशत (रबी सीजन) ही जमा कराना होता है। बाकी प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर जमा कराती हैं। इसलिए इन पांच साल के दौरान किसानों ने 19,913 करोड़ रुपए जमा कराए, जबकि कुल प्रीमियम के तौर पर 1,26,521 करोड़ रुपए जमा कराए गए। आंकड़े बताते हैं कि फसल का नुकसान होने पर किसानों ने 92,954 करोड़ रुपए का क्लेम किया था, लेकिन उन्हें भुगतान 87,320 करोड़ रुपए का किया गया। यानी दिसंबर 2020 तक किसानों को क्लेम का 5,724 करोड़ रुपए नहीं दिया गया था। अब सवाल उठता है कि इस योजना का किसने ज्यादा फायदा उठाया? सरकारी बीमा कंपनियों को अधिक फायदा हुआ या प्राइवेट कंपनियां आगे रही?

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से 2019-20 के दौरान पांच में से दो सरकारी बीमा कंपनियों ने जितना प्रीमियम वसूला, उससे ज्यादा क्लेम का भुगतान किया। यानी कंपनियां घाटे में रहीं। जबकि पांचों कंपनियों के कुल बिजनेस की बात की जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इन कंपनियों को 10.86 फीसदी ही फायदा हुआ। स्थायी समिति की यह रिपोर्ट बताती है कि कुल फसल बीमा बिजनेस में पांचों सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (एआईसी) लिमिटेड की है। एआईसी के अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सरकारी कंपनियां हैं। इस बिजनेस में सरकारी कंपनी के तौर पर केवल एआईसी ही ठीकठाक स्थिति में है। इस कंपनी ने चार साल में 32,429.24 करोड़ रुपए का प्रीमियम हासिल किया, जबकि 26,874.6 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान किया। यानी एआईसी को लगभग 17.12 फीसदी का फायदा हुआ।

न्यू इंडिया एश्योरेंस और ओरियंटल इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घाटे का सौदा रही। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को चार साल के दौरान 4660.31 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जबकि उसने 5145.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसी तरह ओरियंल इंश्योरेंस को 3893.16 करोड़ रुपए का प्रीमियम मिला, जबकि कंपनी ने क्लेम के रूप में 4305.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया। नेशनल इंश्योरेंस ने 2574.34 करोड़ रुपए के प्रीमियम के बदले 2514.77 करोड़ रुपए का भुगतान किया। तीन साल तक यह कंपनी भी घाटे में रही। संसद की स्थायी समिति ने कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से कहा कि जो कंपनियां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मुनाफा कमा रही हैं, उनसे कहा जाए कि वे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत जिन जिलों से यह मुनाफा कमा रही हैं, उन जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर एक तय रकम खर्च करें। हालांकि कृषि विभाग ने तर्क दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाला मुनाफे का सीएसआर फंड बनाया जाए। विभाग ने यह भी तर्क दिया कि कई बार फसलों का नुकसान अधिक होने के कारण प्रीमियम से काफी अधिक क्लेम देना पड़ जाता है, इसलिए मुनाफे की गणना करना सही नहीं है।

● **नवीन रघुवंशी**

मुनाफे में हैं निजी कंपनियां

स्थायी समिति की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि निजी कंपनियों को चार साल के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक फायदा हुआ। कई कंपनियों ने 60 से 70 फीसदी तक मुनाफा कमाया। भारती एएक्सए 2017-18 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुई और तीन साल के दौरान कंपनी ने 1575.42 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, जबकि क्लेम का भुगतान 438.80 करोड़ रुपए किया। यानी कंपनी 72.14 फीसदी मुनाफे में है। रिलायंस जीआईसी लिमिटेड ने चार साल में 6150.22 करोड़ रुपया प्रीमियम के तौर पर वसूला, जबकि किसानों को 2580.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यानी कंपनी को इस योजना से लगभग 59 प्रतिशत का मुनाफा हुआ। इसी तरह फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस को 60.91 प्रतिशत, इफ्को को 52 फीसदी, एचडीएफसी एग्रो को लगभग 32 फीसदी का मुनाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जिन प्राइवेट कंपनियों को नुकसान हुआ या कम मुनाफा हुआ, उन्होंने इस योजना से अपने हाथ खींच लिए। श्रीराम जीआईसी लिमिटेड ने 2016-19 में 170.95 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया था, लेकिन जब उसे क्लेम के तौर पर 256.95 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा तो उसके बाद कंपनी ने फसल बीमा करना बंद ही कर दिया।

फर्जी पोर्टल से ईटीपी घोटाला

मप्र में फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ईटीपी) से बड़ा घोटला सामने आया है। घोटालेबाजों ने फर्जी पोर्टल बनाकर जाली ईटीपी जारी की। खनिज माफिया ने खनिज विभाग के ई-खनिज जैसा एक फर्जी पोर्टल ही तैयार कर लिया। इसके माध्यम से फर्जी ईटीपी बनाकर फर्जी क्यूआर कोड से पुलिस और मैदानी अमले को गुमराह कर रहे थे। यह मामला प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के गृह जिले पन्ना में सामने आया है। सतना में पकड़े जाने पर इसका खुलासा हुआ है। नागौद में दो ट्रक मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। अभी मामले की जांच चल रही है।

खनिज कारोबार में रॉयल्टी की चोरी के लिए रेत माफिया ने ई-खनिज का एक फर्जी पोर्टल ही तैयार कर लिया है। इस पोर्टल के जरिए ही फर्जी ई-ट्रांजिट पास जेनरेट कर डंके की चोट पर रेत की चोरी की जा रही थी। बंद पड़ी रेत खदानों से विभाग की जानकारी के बगैर न केवल बालू निकाली जा रही थी, बल्कि अवैध रूप से रेत का भंडारण कर उसकी बिक्री और परिवहन भी कराया जा रहा था।

वाहनों के साथ जो ईटीपी दी जा रही थी वह स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के पोर्टल में नजर नहीं आती थी। क्यूआर कोड स्कैन करने पर भी जो पोर्टल खुलता वह न तो माइनिंग कॉर्पोरेशन का था और न ही खनिज साधन विभाग का, लेकिन हूबहू उसकी जैसा होने की वजह से पकड़ में नहीं आता था। रेत के कारोबार के जरिए सरकार को चूना लगाने का यह नेटवर्क प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के गृह जिले पन्ना में फल-फूल रहा था। यूरेका माइंस एंड मिनरल के नाम पर पन्ना जिले में रेत खदानों का ठेका चला रहे रसमीत मल्होत्रा का नाम इस घोटाले में नाम आया है। पन्ना के बहेरा में फर्जी भंडारण बताकर मल्होत्रा ने रेत का पहाड़ खड़ा कर रखा है। इस स्टॉक से ही रेत की गाड़ियां लोड हो रही थीं और फर्जी पोर्टल से तैयार जाली ईटीपी के जरिए परिवहन कर रही थीं।

खनिज विभाग की टीम ने पन्ना से रेत लेकर सतना आए छतरपुर के ट्रक (एमपी 16 एमएच 1976) समेत दो वाहनों को नागौद में कुछ दिन पहले पकड़ा था। इन वाहनों के प्रकरण बनाए जाने लगे तो ट्रक मालिक ईटीपी लेकर खड़ा हो गया। सतना के प्रभारी खनिज अधिकारी सतेंद्र सिंह ने जब ईटीपी चेक कराई और उसका विवरण पोर्टल पर नहीं खुला तो प्रथमदृष्टया उन्हें लगा कि सर्वर की कठिनाई हो सकती है। लेकिन, जब ईटीपी के क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो खनिज अधिकारी की आंखें भी फटी रह गईं। क्यूआर कोड की स्कैनिंग के बाद एक पोर्टल खुल तो रहा था, लेकिन वह पोर्टल न तो खनिज विभाग का था और न ही स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन का था। जब उन्होंने स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन में संपर्क किया तो पता चला कि मल्होत्रा के भंडारण से ईटीपी जारी होने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में प्रश्न ही नहीं उठता कि उसे पोर्टल में एक्सेस मिले। इसके बाद जांच शुरू हुई, तो मामला सामने आया है। इस मामले में और कौन-कौन शामिल हैं, इसकी जांच चल रही है।

जांच की गई तो पता चला कि मल्होत्रा ने भंडारण की ईटीपी ब्लॉक होने और खदान बंद होने के बाद बेहद शातिराना योजना बनाई और इसमें टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी किया। उसने सरकारी पोर्टल से मिलता-जुलता पोर्टल बनवाया और उसकी फंक्शनिंग भी बिल्कुल वैसी ही रखी। इसी फर्जी पोर्टल से ईटीपी जारी की जाने लगी, जिनका वास्तव में स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन अथवा खनिज विभाग से कोई वास्ता ही नहीं था। इंतजाम ऐसे दुरुस्त किए कि किसी विभाग को यह जानकारी भी न लगने पाए और कोई इस पोर्टल से जारी होने वाली जाली टीपी पकड़ भी न पाए। जो ईटीपी जारी हो वो देखने मे बिल्कुल असली ईटीपी जैसी ही हो। इसका फायदा रास्ते में होने वाली रोकटोक से बचने के लिए उठाया जाता था, लेकिन सतना में यह पकड़ा गया।

ईटीपी का सच जानने के लिए शुरू हुई जांच के दौरान सतना के खनिज महकमे को यह भी पता चला कि जिस खदान से रसमीत मल्होत्रा रेत निकालकर डंप कर रहा है। उस खदान को बंद करने का आवेदन विभाग को दिया जा चुका है। बड़ा सवाल यह भी है कि जब खदान सरकारी तौर पर बंद है तो फिर मल्होत्रा आखिर किसकी शह पर खदान से रेत की चोरी कर रहा था। पन्ना जिले के माइनिंग कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार जिस स्टॉक से रेत लाई जा रही थी, उस स्टॉक के साथ संबंधित रेत खदान की ईटीपी बंद है। खदान समर्पण के लिए ठेकेदार रसमीत मल्होत्रा ने आवेदन किया है। खनिज माफिया बैकडोर से रेत का कारोबार करते हुए रॉयल्टी की बड़ी चोरी की है। इससे पन्ना में भी जांच शुरू की है। जांच में जुटी साइबर टीम एसपी धर्मवीर सिंह ने साइबर टीम को जांच के निर्देश दिए हैं। इससे पता चलेगा कि सतना में रेत परिवहन के मामलों में किस तरह से फर्जीवाड़ा कर राजस्व नुकसान किया गया है।

● **अरविंद नारद**

दिसंबर 2012 में ही बना था डमी पोर्टल

ईटीपी घोटाला सामने आने के बाद रेत का काला कारोबार करने वालों में हड़कंप है। खनिज विभाग ने दो ट्रक मालिकों से दो फर्जी ईटीपी मिलने के बाद थाना नागौद में एफआईआर दर्ज कराई है। संबंधित ट्रकों के मालिक और चालकों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार खनिज विभाग की फर्जी ईटीपी जनरेट करने वाला डमी पोर्टल 1 दिसंबर 2012 को बनाया गया था। इसका रजिस्ट्रार 101 है। इसे 25 नवंबर 2020 को पुनः पोर्टल के रेग्युलर उपयोग के लिए तैयार किया गया था। दरअसल, घोटालेबाजों ने फर्जी पोर्टल बनाकर जाली ईटीपी जारी की और उनके जरिए करोड़ों की रेत चोरी की। प्रदेश के खनिज मंत्री के गृह जिले पन्ना में हुए इस घोटाले के सतना में पकड़े जाने के बाद जांच शुरू की गई है। थाना प्रभारी नागौद निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने बताया, 3 अगस्त 2021 को खनिज निरीक्षक आशुतोष मिश्रा, कमलकांत परस्ते, पवन कुशवाहा ने कचनार मोड़ से रेत से भरे दो ट्रक पकड़े थे। ट्रकों में एमपी 16 एच 1976, जिसके मालिक राम सुहावन अहिरवार निवासी अमौधा हैं। दूसरा ट्रक एमपी 16 एच 1721 है, जिसके मालिक गया प्रसाद यादव निवासी सतना है। चालकों के पास रेत परिवहन से संबंधित ईटीपी नहीं मिली थी। अगले दिन 4 अगस्त को दोनों ट्रकों के मालिकों ने जो ईटीपी खनिज विभाग में जमा की वह डमी पोर्टल से फर्जी तरीके से बनाई पाई गई। इसके बाद नागौद पुलिस ने दोनों ट्रकों के मालिक और चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने नागौद क्षेत्र से जुड़े अन्य ट्रक मालिकों को भी पूछताछ की है।

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र मात्र 4 घंटे चला। प्रदेश के इतिहास में यह सबसे छोटा सत्र रहा। लेकिन इस सत्र में हंगामा जमकर हुआ। 4 दिनी सत्र के पहले दिन से ही हंगामा शुरु हुआ, जो दूसरे दिन इस स्थिति में पहुंच गया कि विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों में से कोई भी इस मूड में नहीं दिखे कि वे सदन को चलाना चाहते हैं।

4 घंटे की विधानसभा

कभी देश में सबसे अच्छी विधानसभा और विधायक का दर्जा पाने वाले मप्र में अब हंगामा ही हंगामा नजर आता है। यानी विधानसभा सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि जैसे भी हो बिल और विधेयक पास करा लिया जाए और विपक्ष का केंद्र बिंदु रहता है कि बिना मुद्दे के भी सत्तापक्ष को घेरा जाए। यह परंपरा पिछले एक दशक से लगातार बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि विधानसभा सत्र कम दिनों में सिमट रहे हैं। ऐसा होने से सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है।

विधानसभा का चार दिन वाला मानसून सत्र दूसरे ही दिन, वो भी कार्यवाही के बीच में ही अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष यकीनन अपनी उस हुल्लड़ ब्रिगेड को इसका अघोषित श्रेय देगा, जिसने हंगामा कर के कार्यवाही को चलने ही नहीं दिया। साथ ही उसका यह आरोप भी खालिस राजनीतिक चलन से प्रेरित है कि सत्तारूढ़ पक्ष ही सदन को चलने देना नहीं चाहता था। लेकिन सतही आंकलन भी करें तो साफ नजर आता है कि विरोधी दल केवल और केवल विरोध की नीयत से ही सदन में पहुंचा था। वहीं सत्तापक्ष भी सदन चलाने के प्रति उत्सुक नहीं दिखा।

मानसून सत्र से पहले दोनों पार्टियां प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के तैयारियों में जुटी हुई थीं। इसलिए सत्र के दौरान ऐसा लगा जैसे दोनों का मकसद यही है कि हंगामा को बहाना बनाकर सदन अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। दूसरे दिन हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट और दो संशोधन विधेयक पास करा लिए। सरकार ने अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक विधानसभा में पेश किए थे। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पास करा लिया। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधानसभा शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह मुद्दा उठाया। इसको लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हो गया, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया कि पेट्रोल-डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय पर बढ़े थे। इस पर कमलनाथ ने कहा कि महंगाई देश और प्रदेश में गंभीर मुद्दा है। इस पर सदन में बहस होना चाहिए। इसको लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद सत्तापक्ष के विधायक इसका विरोध करने लगे तो कांग्रेस के विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए। विपक्ष के विधायक मांग करने लगे कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा होना चाहिए। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।

विधानसभा में दूसरे दिन फिर आदिवासियों का मुद्दा उठा। इस बार सत्तापक्ष ने यह मामला उठाया। भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन

ओबीसी आरक्षण पर सियासत

बिहार और उप्र के बाद अब मप्र में भी पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक गत दिनों सरकार विरोधी नारे लिखे काला एप्रिन पहनकर विधानसभा पहंचे। सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की मांग थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रखे। हंगामे के बीच ही बहुमत के आधार पर सरकार ने अनुपूरक बाजट और दो विधेयक पाारित कराए। विधानसभा में सदन के बाहर कांग्रेस और भाजपा ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए। कमलनाथ ने कहा कि मप्र में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, लेकिन इस पर स्टे हो गया, लेकिन शिवराज सरकार के कोर्ट में दिए गलत बयान से प्रदेश की इस वर्ग की 55 प्रतिशत आबादी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करे। सदन के अंदर जब कांग्रेस विधायक हंगामा कर रहे थे, उस बीच ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभ परिसर में मीडिया के सामने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिया था। 10 मार्च को याचिका लगी और 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया। शिवराज ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया। कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ जवाब दें कि 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पाखंड कर रही है, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया।

सिंह यादव ने क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच तहसीलदार से कराई गई जो एक महिला अधिकारी है। विधायक ने इस अधिकारी के लिए बेचारी शब्द का प्रयोग किया। इसको लेकर धार्मिक न्यास एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने आपत्ति जताई और कहा कि आदिवासी महिला बेचारी नहीं हो सकती। उन्होंने विधायक से माफी मांगने की मांग की। इसे लेकर सदन में कुछ देर गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन अध्यक्ष ने मामले को शांत करा दिया। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के मामले में पाखंड कर रही है। वह घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले तो कांग्रेस को चार दिन के सत्र में कई आवश्यक चर्चाएं न हो पाने का भय सता रहा था। फिर इस डर ने कुछ ऐसी शक्ल ली कि विपक्ष सत्र की व्यवस्थाओं के साथ चार कदम चलने में भी रूचि लेता नहीं दिखा। कांग्रेस को यदि ओबीसी आरक्षण की वाकई इतनी फिक्र थी, तो उसके पास चार दिन का समय था कि सरकार को इस विषय पर पूरी ताकत से घेर लेती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जाहिर है कि कमलनाथ को इस बात का डर सता रहा था कि 'बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासीनता का सबब पूछेंगे।' वह उदासीनता जो कमलनाथ ने सरकार में रहते हुए इस आरक्षण पर पूरे समय दिखाई। यदि सदन में इस विषय पर बात होती तो कांग्रेस को इस सब पर जवाब देना भारी पड़ जाता। वैसे ही, जैसे भारी मन से यह दल लोकसभा में ओबीसी को लेकर संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर मोदी सरकार का समर्थन कर रहा है। इस विषय पर सही और गलत की तराजू में कांग्रेस का पलड़ा काफी हलका दिख रहा है।

भाजपा विधायक कहते हैं कि विपक्ष की नीति तो विचित्र है ही, अब तो उसकी नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसान सहित आम आदमी का बड़ा वर्ग तबाह हो चुका है। क्या यह कांग्रेस का कर्तव्य नहीं था कि विपक्ष में होने के नाते वह इस विषय पर सदन में चर्चा के जरिए लोगों के लिए राहत और बचाव के और अधिक पुख्ता प्रबंध करवाती? लेकिन उसने विपक्ष की शक्ति का सारा जोर आज नाहक शोर में बर्बाद कर दिया। कमलनाथ को अचानक याद आया है कि वह भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। इस आधार पर वह कह रहे हैं कि सत्र का यूं खत्म किया जाना गलत है। लेकिन कमलनाथ को यह तथ्य क्या समय रहते याद नहीं आया कि विधानसभा में चर्चा के माध्यम से आम जनता को यह संदेश दिया जा सकता था कि राज्य में प्रतिपक्ष नामक कोई ऐसी संस्था का अस्तित्व अब भी कायम है, जिससे सरकार से किसी नाराजगी या शिकायत की सूरत में मदद ली जा सकती है? सदन में जो काले एप्रिन दिखे, यदि उन्हें उठाकर अंदर देख लिया जाता तो साफ दिखता कि ये आवरण कांग्रेस की नाकामियों और काहिली वाले धब्बों को छिपाने के लिए ओढ़ा गया था।

एक उस चौपाये की कहानी याद आ गई, जिसके साथी के ऊपर उसके मालिक ने नदी के दूसरे छोर पर पहुंचाई जाने वाली नमक की बोरियां लाद दी थीं। वह साथी चौपाया चतुर था। नदी में उतरते ही उसने डुबकी लगाई और देखते ही देखते काफी सारा नमक बह गया। उसकी पीठ का बोझ कम हो गया। यह देख इस चौपाये को भी होशियारी सूझी। उसने भी वजन कम करने के लिए नदी में डुबकी लगा दी। जबकि उसकी पीठ पर रुई लदी हुई थी। रुई ने पानी सोख लिया और इस चौपाये का वजन पहले के मुकाबले काफी अधिक बढ़ गया। कांग्रेस जातिवादी राजनीति को लेकर इसी रुई वाले चौपाये जैसी चूक कर चुकी है। आजादी के बाद करीब पचास सालों तक केंद्र और राज्यों में शासन करने के बाद भी कांग्रेस समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने में नाकाम रही। उसने बस अंधाधुंध तरीके के तुष्टिकरण के महासागर में डुबकी लगाने को ही अपनी सफलता का सूत्र मान लिया। नतीजा यह कि अब वह अपनी ही गलतियों का बोझ ढोने को मजबूर हो गई है। जाति संबंधी राजनीति की उसकी काठ की हांडी अब नहीं चढ़ सकती, इस बात को कांग्रेस आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है।

● **सुनील सिंह**

विधानसभा में पप्पू, मिस्टर बंटाधार जैसे शब्द कहने पर रोक

मप्र विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सदन में असंसदीय भाषा से बचने के लिए 'असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह' पुस्तक का प्रकाशन किया है। गत दिनों इस किताब का विमोचन किया गया ताकि सदन की गरिमा बने रहे और सदस्यों द्वारा कहे गए ऐसे शब्दों को बार-बार कार्यवाही से हटाना न पड़े। मप्र विधानसभा के चार दिन के मानसून सत्र के एक दिन पहले विधानसभा ने 38 पन्नों की इस किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक में 1,161 असंसदीय शब्दों और वाक्याशों का संग्रह है, जो वर्ष 1954 से लेकर अब तक विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। यह शब्द और वाक्यांश अधिकांश हिंदी के हैं। विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई इस पुस्तक के संकलन के अनुसार विधानसभा के सदस्यगणों से अब सदन में 'पप्पू' और 'मिस्टर बंटाधार' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने की उम्मीद की जाती है। बता दें कि भाजपा के समर्थक उपहास के तौर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 'पप्पू' कहते हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को वो 'मिस्टर बंटाधार' कहते हैं। इनके अलावा, इस संग्रह में ढोंगी, निकम्मा, चोर, भ्रष्ट, तानाशाह और गुंडे सहित कई शब्दों और झूठ बोलना व व्यभिचार करना जैसे वाक्याशों को भी शामिल किया गया है। इसमें 'ससुर' शब्द का भी जिक्र किया गया है, जिसका उपयोग सदन में 9 सितंबर, 1954 को किया गया था, जिसे बाद में कार्यवाही से हटा दिया गया था।

पुलिस के रिकॉर्ड में चंबल दस्यु मुक्त हो गया है, लेकिन आज भी बीहड़ में डकैत सक्रिय हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में जो ईनामी डकैत हैं, वे भी गायब हैं। उधर, बीहड़ में आए दिन डकैत वारदातें करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

बीहड़ों में 'गायब' ईनामी डकैत

डकैतों के कारण देश-दुनिया की सुर्खियों में रहे ग्वालियर-चंबल अंचल के बीहड़ों में अब कोई डकैत गिरोह नहीं है। यह सरकारी दावा है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। पुलिस के टॉप टारगेट पर रहे रामबाबू-दयाराम गड़रिया और घीसा बंजारा जैसे कुख्यात डकैतों की गैंग में बरसों सक्रिय रहे कई ईनामी डकैत अभी भी पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। कारण, ये डकैत जिंदा हैं या मर चुके हैं, पुलिस के पास इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लिहाजा, इनके नाम पुलिस रिकार्ड में न तो सूचीबद्ध डकैतों में हैं और न ही असूचीबद्ध डकैतों में। इनमें से कभी किसी डकैत के मरने की खबर भी फैली लेकिन जांच में लाश किसी और की निकली। इसके बाद भी पुलिस ये मानकर बैठी है कि काफी समय से डकैतों का कोई मूवमेंट न होने से संभावना है कि उनकी मौत हो गई होगी।

हालांकि रामबाबू-दयाराम गड़रिया जैसे कुख्यात डकैतों के सफाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अफसर इस बात से इनकार नहीं करते कि अगर ठीक से तलाशा जाए तो इन डकैतों तक पहुंचना असंभव नहीं है। कारण, कई डकैत भेष बदलकर यहां-वहां रह रहे हैं।

गड़रिया गैंग का एक डकैत चिंटू गड़रिया 2019 में पकड़ा गया था। श्योपुर पुलिस ने उसे पकड़ा था। जब गिरोह का खात्मा हुआ तो वह बचने के लिए मथुरा भाग गया। पहले कुछ दिन तक शिवपुरी के ही मंदिर में साधु का भेष रखकर छिपा रहा। फिर वृंदावन, मथुरा में 6 साल तक रहा। उसने अयोध्या पुत्र कुंजबिहारी निवासी मथुरा के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। उसे साधु के भेष में ही पुलिस ने 2019 में गिरफ्तार किया।

वहीं अभी कई ऐसे डकैत हैं जो पुलिस का सिरदर्द बने हुए हैं। इनमें उपाई यादव, गुड्डा गुर्जर, सिरनाम आदिवासी, विशाल गड़रिया, रणवीर बंजारा, बृखभान गड़रिया आदि शामिल हैं। उपाई यादव पर आईजी ग्वालियर की ओर से 30 हजार रुपए का ईनाम है। एसपी बारां ने इस पर 5 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया है। इस डकैत का मूवमेंट 3 साल पहले शिवपुरी, घाटीगांव के जंगलों में था। लेकिन पुलिस का दावा है, अब इस डकैत का मूवमेंट राजस्थान में है। गुड्डा गुर्जर पर आईजी ग्वालियर एवं आईजी चंबल जोन की ओर से 30 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया है। डकैत का मूवमेंट मुरैना के जौरा, ग्वालियर के तिघरा व राजस्थान बॉर्डर पर रहता है। कुछ समय पहले तिघरा के जंगल में इसका मूवमेंट नहीं था, लेकिन पुलिस जब सर्चिंग पर जंगल में उतरी तो यह मुरैना की ओर लौट गया।

सिरनाम आदिवासी की लाश मिली तो फाइल बंद कर दी, डीएनए रिपोर्ट में शव किसी और का निकला। पुलिस की सूची में टारगेट नंबर-1 पर दर्ज डकैत गैंग रामबाबू-दयाराम गड़रिया के मारे जाने के बाद 26 दिसंबर 2006 को मोहना-शिवपुरी सीमा में पार्वती नदी के जंगल में एक लाश मिली। 50 हजार के ईनामी सिरनाम आदिवासी (30) निवासी रामपुरा आरोन के रूप में हुई। सिरनाम के भाई अमर सिंह और प्रताप ने पुलिस को बताया कि विवाद के बाद अमर सिंह ने उस पर गोली चलाई, जिसमें सिरनाम मारा गया। सिरनाम के भाई और पिता के ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया। 4 साल बाद रिपोर्ट आई तो डीएनए मैच नहीं हुआ। सिरनाम के भाई और परिजन गायब हो गए।

वहीं 50 हजार का ईनामी डकैत विशाल गड़रिया एनकाउंटर में बचकर भागा, फिर नहीं मिला। 2005 में प्रकाश का एनकाउंटर अमोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने किया। विशाल भाग निकला था। दतिया पुलिस ने उसके एनकाउंटर का दावा किया पर लाश नहीं मिली। इसके बाद एक-दो बार उसे देखा भी गया। पुलिस ने कुछ समय ढूंढा, फिर मरा समझकर ढूंढना बंद कर दिया।

रणवीर बंजारा ने बहनोई और भाई के बाद गैंग चलाई। वह 6 साल से लापता है। टी-44 डकैत घीसा बंजारा के पकड़े जाने के बाद उसके राइट हैंड मोहरू बंजारा ने गैंग चलाई। इसमें उसके साले रणवीर और बलवीर पुत्र हरीराम बंजारा निवासी भगवानपुरा, थाना आरोन भी शामिल हो गए। मोहरू पकड़ा गया तो गैंग की कमान बलवीर ने संभाली। ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना के जंगलों में इनका मूवमेंट रहा। 27 दिसंबर 2014 को ग्वालियर जोन के आईजी ने दोनों भाईयों पर 15-15 हजार का ईनाम घोषित किया। 26 सितंबर 2015 को श्योपुर के बलावनी के जंगल में पुलिस ने घेराबंदी की। मुठभेड़ में बलवीर पकड़ा गया, रणवीर भाग गया। तब से वह लापता है।

● बृजेश साहू

मप्र फिर बनेगा टाइगर स्टेट

अखिल भारतीय स्तर पर तीन साल पहले हुई बाघ गणना में 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर काबिज रहकर मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। इस साल होने वाली गणना के प्रारंभिक संकेतों के अनुसार इस बार भी मप्र को टाइगर स्टेट के रूप में मान्यता मिलने की प्रबल संभावना है।

प्रदेश सरकार ने वन्य-प्राणी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचारों को लागू किया, जिनकी बदौलत मप्र टाइगर स्टेट की प्रक्रिया का आधार स्तंभ बना। पिछले डेढ़ दशक में बाघों और अन्य वन्य-प्राणियों के लिए आवास क्षेत्र की सुविधा कराने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से 167 ग्रामों का मुकम्मबल स्थान पर पुनर्स्थापन कराया गया। दुर्गम वन क्षेत्रों के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाओं के साथ रह रही 15 हजार से ज्यादा परिवार इकाइयों को वनों से बाहर लाया जाकर ग्राम-नगरों में बसाया गया। नतीजा यह हुआ कि वन्य-प्राणियों को व्यवधान रहित स्वछंद रूप से रहवास मिल गया। साथ ही वनवासियों की माली हालत में भी सुधार हुआ। इन तमाम नवाचारों में राज्य सरकार ने 900 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई।

प्रदेश के बाघ न केवल टाइगर रिजर्व में है बल्कि अन्य क्षेत्रीय वन मंडलों अपितु भोपाल जैसे बड़े शहरों की सीमा में भी अन्य प्राणी की तरह विचरण करते पाए जाते हैं। वर्ष 2018 में पन्ना से बाघों का अस्तिव ही समाप्त हो गया था। वन विभाग द्वारा बाघ संरक्षण के लिए सक्रिय पहल की गई, जिसमें बाघों को अन्य संरक्षित क्षेत्रों से लाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापित किया गया। पिछले 9 वर्ष की सतत प्रक्रिया के कारण आज पन्ना टाइगर रिजर्व पुराने वैभव की ओर लौट चुका है। यहां 20 से ज्यादा वयस्क बाघ और 15 अवयस्क बाघ-शावक मौजूद हैं। संपूर्ण पन्ना लैंड स्केप में शावकों सहित तकरीबन 50 बाघ उपलब्ध हैं।

प्रदेश में वर्ष 2005-06 में बिछड़े अनाथ शावकों को उनके प्राकृतिक रहवास में मुक्त करने की नई पहल की शुरूआत की गई थी। इससे अनाथ बाघ शावक चिड़ियाघर पहुंच जाते थे। उनके वयस्क होते ही प्राकृतिक आवास में मुक्त किया जाना संभव हो सका। कान्हा टाइगर रिजर्व के घोरेला एन्क्लोजर में 9 बाघ शावकों को वयस्क होने पर मुक्त किया जा चुका है। प्रदेश को मिली इस सफलता को पूरी दुनिया में घोरेला मॉडल के रूप में प्रसिद्धि मिली है।

भारत में बाघों की गणना हरेक 4 साल में की जाती है। इसके तीन चरण निर्धारित हैं। प्रथम चरण में बाघों, अन्य मांसाहारी तथा बड़े शाकाहारी प्राणियों के चिन्ह अर्थात् उनके पंजों के निशान, उनकी विष्ठा, खरोंच के निशान और उनके द्वारा किए गए शिकार आदि के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस बाघ आंकलन को फेस वन कहा जाता है। यह प्रक्रिया एक सप्ताह तक चलती है। वन कर्मचारी इन सातों दिन जंगलों में भ्रमण कर वन्य-प्राणियों की उपस्थिति के चिन्ह पहले तीन दिन और अगले तीन दिन वन्य-प्राणियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की संख्या एकत्रित करते हैं। द्वितीय चरण में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में बाघ आंकलन किया जाता है। वैज्ञानिक सैटेलाइट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ो का अध्ययन कर बाघ के रहवास क्षेत्र की स्थिति के बारे में आंकड़े जुटाते हैं। तीसरे चरण में कैमरा ट्रेपिंग की जाकर बाघों की उपस्थिति के चित्र लिए जाते हैं। इन तीन चरणों में मिले आंकड़े और सबूतों के सांख्यिकी विश्लेषण से किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या का आंकलन निकाला जाता है।

अखिल भारतीय बाघ गणना में संपूर्ण भारत में तकरीबन 30 हजार बीटो में गणना कार्य किया जाता है। इसमें 9 हजार बीट केवल मप्र में ही मौजूद हैं। यह एक बहुत श्रम साध्य और व्यापक कार्य है। प्रदेश के वन विभाग ने इस चुनौती को अंगीकार करते हुए वर्ष 2017 से अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत वन रक्षकों के कई चरण आयोजित कर उन्हें इसके काबिल बनाया गया। इस तरह दक्षतापूर्ण तरीके से दुष्कर कार्य की गणना कराई जाती है। बाघ सभी को भयभीत करने वाला और शक्तिशाली जंतु के रूप में जाना जाता है। इसकी दहाड़ और गुर्राहट भयानक के साथ डराने वाली होती है। 3 किमी की रेंज तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है। बाघ के पिछले पैर आगे वाले पैरों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

कार्यालय नगर पालिका परिषद, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

अपील

- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।
- मास्क लगाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- सर्दी-जुकाम और बुखार आने पर अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर मिलें।

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, खिलचीपुर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, माचलपुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

अपील

- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।
- मास्क लगाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- सर्दी-जुकाम और बुखार आने पर अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर मिलें।

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, माचलपुर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कागजों पर संस्थागत प्रसव

देश में बुंदेलखंड ऐसा इलाका है जहां सरकारें विकास की तो बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, लेकिन हकीकत में योजनाएं कागजों से बाहर नहीं आ पाती हैं। विकास में पिछड़े बुंदेलखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह बदहाल हैं। यहां संस्थागत प्रसव तो कागजों पर चल रहा है। आलम यह है कि अकेले उप्र के चित्रकूट जिले के करवी ब्लॉक में 55 महिलाओं को इस साल जुलाई में संस्थागत प्रसव की सुविधा नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इन 55 महिलाओं में से 23 के पास प्रसव के दौरान कुशल परिचारिका अथवा किसी तरह की कोई चिकित्सा किट तक उपलब्ध नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रसव के दौरान या तो किसी रिश्तेदार या स्थानीय दाई ने इन महिलाओं की सहायता की।

चित्रकूट जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस जिले में मई 2019 में 1,179 संस्थागत प्रसव के मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन मई 2020 में यह संख्या घटकर 1,086 हो गई। 2021 में इसी महीने यह संख्या और भी कम होकर 1,016 हो गई। जून महीने के आंकड़े भी संस्थागत प्रसव के मामलों में इसी तरह की गिरावट दिखाते हैं। जून 2019 में, 1,420 संस्थागत प्रसव हुए थे, जो 2020 में घटकर 1,342 और 2021 में 1,232 हो गए। इस साल अप्रैल से जून तक, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, चित्रकूट में घर पर प्रसव के 196 मामले दर्ज किए गए। 2020 में पूरे साल के लिए यह आंकड़ा 955 और 2019 में 965 था। जिला स्वास्थ्य अधिकारी संस्थागत प्रसव में आई इस गिरावट के पीछे कोविड महामारी, लॉकडाउन और टीकाकरण अभियान का हवाला देते हैं।

चित्रकूट के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राम किशोर करवरिया कहते हैं, 'उस समय पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था और हमारा सारा का सारा कार्यबल कोविड के प्रबंधन में लगा हुआ था। कभी-कभी एम्बुलेंस भी देर से पहुंचती थी। साथ ही, प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद भी, परिवार वाले आशा कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला अस्पतालों से संपर्क करने के लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह चीजों को और मुश्किल बना देता है।'

संस्थागत प्रसव में आई इस गिरावट ने जिला प्रशासन में खतरे की घंटी बजा दी है। 2 अगस्त को हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस तरह की गिरावट के कारण का पता लगाने और उन परिवारों की पहचान करने को कहा जहां घर पर बच्चों को जन्म दिया गया है। 32 वर्षीया सावित्री देवी ने इस 10 जुलाई को अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। वे अपने पति गोरे लाल, जो बाहर काम करने वाले मजदूर हैं, के साथ मई में पंजाब से लौटी थीं। सावित्री ने बताया कि वह पंजाब या उप्र के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए अपना नाम नहीं लिखवा सकीं। सावित्री बताती हैं, 'मेरी सभी बेटियों का जन्म पंजाब के एक अस्पताल में हुआ था, लेकिन हमें वहां कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ा। इस साल हमने अपना काम-धंधा खो दिया था। इसलिए मैंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया।' सावित्री और उनके पति दोनों पंजाब में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे।

किसी भी आशा कार्यकर्ता अथवा ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम) द्वारा निगरानी के आभाव में सावित्री किसी भी तरह नियमित जांच और आयरन एवं कैल्शियम की गोलियों से भी वंचित रहीं। उनके नवजात बेटे को जन्म के 24 घंटे के भीतर ओपीवी-0, हेप-बी और बीसीजी के इंजेक्शन भी नहीं दिए गए। राधा की बेटी को भी ये टीके नहीं लगाए गए थे। राधा ने बताया था कि वे भी गर्भावस्था के दौरान अपनी चौथी नियमित जांच नहीं करा पाईं थीं, क्योंकि उनकी एएनएम टीकाकरण अभियान में व्यस्त थीं। उनका मातृत्व एवम् शिशु प्रतिरक्षा (मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन) कार्ड यह दिखाता है कि उनकी पिछले 13 मार्च, 10 अप्रैल और 5 मई को नियमित जांच की गई थी।

● सिद्धार्थ पांडे

कार्यालय नगर परिषद, सुठालिया, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

अपील

- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।
- मास्क लगाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- सर्दी-जुकाम और बुखार आने पर अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर मिलें।

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, सुठालिया,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

अपील

- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।
- मास्क लगाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- सर्दी-जुकाम और बुखार आने पर अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर मिलें।

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सारंगपुर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

मप्र में बढ़ रहा है लाल आतंक

मप्र में नक्सली अपनी गतिविधियों को फिर से बढ़ाने लगे हैं। उन्हें हथियारों की भरपूर सप्लाई हो रही है, जिससे नक्सलियों के तमाम दलमों के हौसले बुलंद हैं। उनके लगातार हो रहे मूवमेंट ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। एजेंसियां नक्सलियों के खात्मे के लिए कई प्रयास कर रही हैं। प्रदेश में नक्सली कई रास्तों के सहारे पहुंच बनाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में नक्सलियों ने बीते कई वर्षों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्हें हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हाल ही में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पता चला कि हथियार मुख्य रूप से राजस्थान से खरीदे जाते थे। यहां से उन्हें महाराष्ट्र ले जाया जाता था। इसके बाद महाराष्ट्र की सीमा से लगे मप्र के जिलों से इन्हें नक्सलियों तक पहुंचाया जाता था। गिरोह से बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी।

इंस्पेक्टर जनरल (नक्सल विरोधी) फरीद शापू ने बताया कि मप्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के ट्राई-जंक्शन में सक्रिय नक्सल दलमों को अवैध हथियार, विस्फोटक सामग्री की सप्लाई महाराष्ट्र से होती है। पिछले एक साल में 7-8 बार हथियार, विस्फोटक, नाईट विजन, बायनाकुलर, हाईरेंज टॉर्च, टेक्टिकल शूज समेत अन्य घातक सामग्री नक्सलियों तक पहुंची हैं। बालाघाट जिले में सक्रिय टांडा दलम, मलाजखंड दलम, दर्रेकसा दलम, विस्तार प्लाटून-2, विस्तार प्लाटून-3 और खटिया मोचा एरिया कमेटी के नक्सलियों को अवैध हथियार मिल रहे हैं। रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव, ने बताया कि हथियारों की सप्लाई के लिए महाराष्ट्र से लगने वाले बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी जिलों की सीमाओं का उपयोग किया जाता है। खरगोन जिले की झिरन्या तहसील का पाल क्षेत्र और बड़वानी जिले के सेंधवा की सीमा आरोपियों के लिए ज्यादा आसान होती है। यह क्षेत्र घने जंगलों वाला है। साथ ही, आदिवासी बहुल होने के कारण समाजसेवा के नाम पर नक्सलियों का कुछ नेटवर्क भी यहां है। इन्हीं क्षेत्रों में सिकलीगरों द्वारा अवैध हथियार बनाने का इतिहास रहा है। राजस्थान के गिरोह के अलावा सिकलीगर भी हथियार मुहैया कराते थे।

मप्र में नक्सली हमले की घटनाओं ने साल 2020 में ही रफ्तार पकड़ ली। कहने को मप्र का बालाघाट जिला नक्सल घटनाओं को लेकर रेड जोन में है, लेकिन लाल आतंक का दायरा अब डिंडोरी और मंडला जिलों तक फैल चुका है। कोरोना की एंट्री के बाद लॉकडाउन हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे नक्सली घटनाएं भी थम गई हैं, लेकिन इस दौरान नक्सलियों ने आदिवासी बहुल छोटे-छोटे गांवों में अपना वर्चस्व जमा लिया। नक्सली धमक की वजह से इन गांवों से सटे आसपास के गांव में रहने वाले आदिवासी भी दहशत में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अपनी पहुंच बना चुके नक्सली मप्र के भी इलाके में वर्षों से सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि अब मामला सिर्फ पर्चों और धमकियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लाल आतंक जानलेवा होता जा रहा है। मासूम ग्रामीणों को जान से मारना हो या फिर गांव में वर्चस्व जमाए रखने के लिए मासूम गरीब आदिवासियों को ब्लैकमेल करना, नक्सलियों की फितरत बन गई है। मप्र के लिहाज से नक्सली वारदातों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार हो चुकी है जो बताती है कि न केवल लाल आतंक का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि दहशत भी बढ़ रही है।

नक्सली मामलों के जानकार बताते हैं कि अब नक्सली मप्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ते हुए एक कॉरिडोर बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लगा गोंदिया, मप्र के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बीच ऐसा नेटवर्क डेवलप होता दिख रहा है। सिर्फ बालाघाट ही नहीं बल्कि डिंडोरी और मंडला भी नक्सलियों के टारगेट पर हैं और वे अमरकंटक तक अपना वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में हैं। विशेष तौर पर आदिवासी गांवों में नक्सली खुद को स्थापित करने में एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। भट्ट ने कहा कि इन दिनों आम लोगों से लेकर सरकारी कांट्रेक्टर और आदिवासी बाहुल्य इलाकों में संचालित कंपनियों से वसूली इसी कारण आम हो गई है।

● राकेश ग्रोवर

पिछले एक साल में बढ़े मामले

प्रदेश में पिछले एक साल में नक्सलियों की सक्रियता के मामले बढ़े हैं। खासकर बालाघाट में तो नक्सलियों ने अपनी पैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा पिछले एक साल की घटनाओं से लगाया जा सकता है। 17 सितंबर 2020 को बालाघाट पुलिस ने बस्तर कमेटी के विस्तार दलम के कमांडर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया नक्सली बादल सिंह मरकाम 50 लाख का ईनामी था। इसी दौरान बांदा में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। 7 नवंबर 2020 को बालाघाट से 70 किलोमीटर दूर बहियार थाने के उमा देवी के मालखेड़ी में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा उग्रवादी घायल हुए। 12 दिसंबर 2020 को किरनापुर थाने के बोरवन जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो महिला नक्सलियों को मार गिराया। 31 जनवरी 2021 को बालाघाट के लांजी थाने के देवरबेली मलकुआ में निर्माणाधीन सड़क मार्ग पर नक्सलियों ने एक ट्रक और दो ट्रैक्टरों को आग लगा दी। 29 जून 2021 को नक्सलियों ने रूपझर थाने के बिठली चाकी के ब्रम्हनी निवासी ग्रामीण भागचंद आर्मो को पुलिस मुखबिर बताते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। एक दर्जन से ज्यादा सशस्त्र नक्सलियों ने खाना खाने बैठे ग्रामीण भागचंद आर्मो के घर में घुसकर पहले उसे अगवा किया फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान नक्सलियों ने एक पर्चा भी छोड़ा था।

कार्यालय नगर परिषद, तलेन, तह.-पचोर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

अपील

- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं।
- मास्क लगाकर रखें। 2 गज की दूरी बनाकर रखें।
- कोरोना के इस संक्रमणकाल के दौरान अपने आसपास साफ-सफाई बनाकर रखें।
- सर्दी-जुकाम और बुखार आने पर अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर मिलें।

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, तलेन, तह.-पचोर,
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

वन विभाग जंगली हाथियों को खिलाएगा धान

वन मंत्री के अनुसार, प्रदेश के सूरजपुर, धरमजयगढ़ व बालोद वनमंडल के अलग-अलग स्थानों पर खुले में धान रखा गया था, सूरजपुर वनमंडल के बंशीपुर व टुकुडांड में चार-चार व बगड़ा पी-9 में हाथियों ने 6 क्विंटल धान खाया है। विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि खरीफ सीजन 2019-20 का संग्रहित धान पूरी तरह से सड़ चुका है, जिससे अब हाथियों के नाम पर खरीदी की योजना बनाई गई है। मोहम्मद अकबर ने बताया कि हाथी धान, चावल व महुआ के लालच में गांवों में घुसते हैं और घरों को तोड़ते हैं। हाथी धान के बोरों को बाहर निकालकर अपने दल के साथ खाते हैं। इसलिए अगर धान को पहले ही खुले में रख दिया जाए तो हाथी उसे खाकर संतुष्ट हो जाएंगे और गांवों में घुसकर घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही लोगों की जान भी नहीं लेंगे। धान के लालच में हाथी एक ही स्थान पर बार-बार आएंगे और वहीं रहेंगे। इससे राज्यभर में लोगों के घर तोड़ने व मौत की घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि राज्य सरकार के इस फैसले के पक्ष में न तो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं और न ही विपक्ष, दोनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। लेकिन सरकार का दावा है कि हाथियों को धान खिलाने का प्रयोग सफल होता भी दिख रहा है।

वन्य जीव विशेषज्ञ मीतू गुप्ता, बिना किसी अध्ययन के इस तरह के राज्य सरकार के फैसले से असहमत हैं। मीतू गुप्ता कहती हैं, 'हाथी लगातार धान खाते रहे हों, ऐसा कोई शोध अब तक नहीं हुआ है। जंगल में उपलब्ध भोजन के अभाव में धान खाना अलग मुद्दा है, लेकिन उसे नियमित आहार बना देने के अपने खतरे हो सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किसी भी वन्य जीव को इस तरह से भोजन देना कानूनन अपराध है। मीतू गुप्ता का कहना है कि इस संबंध में अगर कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया हो तो उसके नतीजे सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।' मीतू गुप्ता के मुताबिक, हाथी धान नहीं खाते। उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो थोड़ा-बहुत धान खा सकते हैं, लेकिन धान उनका मुख्य भोजन नहीं है और न ही वे धान के लालच में घरों में जाते हैं और उसे क्षतिग्रस्त करते हैं। हाथियों का मुख्य भोजन पेड़ों की छाल व पत्ते हैं। हाथी एक बार में 100 से 150 किलो खाना खाता है। हाथियों के दल को इतना भोजन एक जंगल में नहीं मिल पाता। इसलिए भोजन की तलाश में वह जंगल से बाहर निकलता है। हाथी लॉन्ग रेंज एनिमल है। हाथी वही घर तोड़ते हैं, जो उनके रास्ते में आते हैं। दस में से कोई एकाध मामला होता है, जब हाथी घर तोड़ने के बाद धान निकालकर खाते हैं।

मीतू गुप्ता कहती हैं कि बिना गहन शोध और अध्ययन के यह फैसला कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि अगर किसी जगह चार क्विंटल धान हाथियों के खाने के लिए डाला गया है, हाथियों ने उसमें से दो क्विंटल धान खा लिया, बाकी धान वहीं पड़ा रह गया, जिसे अन्य दूसरे जानवर खाएंगे। इससे न केवल हाथियों का बल्कि दूसरे जीवों को फूड हैबिट बदल जाएगा।

● रायपुर से टीपी सिंह

रुकेगा राजनीति का अपराधीकरण?

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में चुनावी प्रक्रिया में बदलावों की बात लंबे समय से होती रही है। 23 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईवीएम में नोटा का बटन जोड़ा गया था। नोटा का बटन जोड़ने का उद्देश्य था कि इससे राजनीतिक दलों पर दबाव बनेगा और वो साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे। लेकिन, आज तक 'राजनीति के अपराधीकरण' पर रोक नहीं लग सकी है। सामने आने वाले आंकड़ों के अनुसार, तो यह लगातार बढ़ा ही है। 2019 के आम चुनाव में चुनकर आए लोकसभा सांसदों में से करीब 43 प्रतिशत नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन संसद सदस्यों में से 29 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये आंकड़ा 34 फीसदी ही था। राजनीति में अपराधीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए कोई भी सियासी दल ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण रोकने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के चुनाव के 48 घंटों के भीतर उनके आपराधिक इतिहास को सार्वजानिक करना होगा। सियासी दलों को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का कैप्शन देकर इन उम्मीदवारों की सूचना सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए एक सेल बनाए जाने का निर्देश दिया है। यह सेल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन पर निगरानी रखेगा और इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को देगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहा जा सकता है कि अपराधिक छवि वाले नेताओं के लिए मुश्किल हो सकती है। इस स्थिति में सवाल खड़ा होना लाजिमी है क्या राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति मिल पाएगी?

आपराधिक छवि वाले नेताओं को उनकी जाति और धर्म के लोगों का भरपूर साथ मिलता है। अब इसे डर कहें या पैसों का प्रभाव ये नेता किसी भी सियासी दल में शामिल होकर या निर्दलीय चुनाव लड़कर भी आसानी से जीत जाते हैं। इस दौरान इन पर लगे आपराधिक मामलों के बारे में लोग कतई नहीं सोचते हैं। राजनीति में वोटों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में सियासी दलों के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपने पाले में लाने की होड़ लगी हुई है। भारत में राजनीति के मुद्दे शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधाएं न होकर जाति और धर्म होते हैं। जिसकी वजह से इन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की जीत आसानी से सुनिश्चित हो जाती है।

भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे नेताओं के खिलाफ दर्ज अभियोजन को अब हाईकोर्ट की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर इस तरह के फैसले करता रहा है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के चुनाव में उम्मीदवारों को उनकी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करने का फैसला किया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा कारावास की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को उनके पद पर बने रहने की अनुमति के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसी साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम में नोटा का बटन जोड़ा गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से गंभीर अपराध के आरोपों वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल न करने की सिफारिश की थी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जन-प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया था।

● **लोकेंद्र शर्मा**

बाढ़ में बह गया विकास भी, अरमान भी

तबाही का मंज़र

देश के हृदय स्थल में स्थित मप्र प्राकृतिक आपदा-विपदा में सबसे सुरक्षित प्रदेश माना जाता है। इस बार आफत की बारिश ने सारी मान्यताएं तोड़ते हुए ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ का वह मंजर दिखाया, जिसे वर्तमान पीढ़ी ने महसूस भी नहीं किया होगा। मप्र की इस बाढ़ में सरकारी विकास के साथ ही लोगों के घर-द्वार और अरमान भी पानी में बह गए। प्रारंभिक आंकलन में बाढ़ से 8 जिलों में 29 लोगों की जान गई। 3,746 पशुओं की मौत, 30 हजार घर टूटे और 1.11 लाख हैक्टेयर की फसलें तबाह हो गई हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र में नर्मदा सहित तमाम नदियों को प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है। लेकिन इस बार मूसलाधार बारिश से सिंध, पार्वती, चंबल, सीप, कूनो और अमराल नदियों के रौद्र रूप ने ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 जिलों ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में सबकुछ तबाह कर दिया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आने लगा है। सड़कें गायब हो गई हैं, पुल-पुलिया के अवशेष भर नजर आ रहे हैं। गांवों में जहां सुसज्जित मकान थे वहां खंडहर दिख रहा है। जिन खेतों में हरी-हरी फसलें लहलहा रही थीं, वहां सफाचट मैदान नजर आ रहा है। यानी सबकुछ तबाह हो गया है। जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं, वे ऊंचे स्थान पर टेंट लगाकर रह रहें हैं। प्रारंभिक आंकलन में करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान पाया गया है। सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में जुट गई है। लेकिन तबाही का दर्द इतना जल्दी कम होने वाला नहीं है।

मप्र में वैसे तो हर साल कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन इस बार 71 साल बाद ग्वालियर-चंबल अंचल में आई बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने हर प्रभावित व्यक्ति को पूरी मदद करने के लिए खजाना खोल दिया है। इस बीच अफसरों की प्रारंभिक रिपोर्ट में माना गया है कि बाढ़ के लिए नदी, तालाब, नालों, चरनोई भूमि पर अतिक्रमण बड़ी वजह है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बाढ़ के हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोग सरकारी राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक जो राहत पहुंचाई है, वह नाकाफी साबित हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस बाढ़ में उनका सबकुछ तबाह हो गया है। अब सरकार नुकसान का अलग-अलग तरीके से आंकलन करा रही है।

10 हजार करोड़ का नुकसान

सरकार ने प्रारंभिक तौर पर बाढ़ से 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान लगाया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। केंद्र का अध्ययन दल मप्र आएगा। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राहत पैकेज देगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग समेत अन्य जिलों में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षति पहुंची है। 36 हजार 291 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब डेढ़ लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ में मकान गिरने व अन्य वजहों से 36 लोगों की जान गई है, जबकि 2058 जानवर बह गए। राजस्व विभाग के मुताबिक बाढ़ में 5 हजार से ज्यादा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। सड़क, पुल-पुलिया आदि को दुरुस्त करने में करीब 207 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बाढ़ में 6 पुल भी बह गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है, फसलों को नुकसान की जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। इसके मुताबिक करीब डेढ़ लाख हैक्टेयर क्षेत्र की फसल या तो पूरी तरह नष्ट हो गई है या फिर 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान हो चुका है। सरकार राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत फसल, आवास, जनहानि और पशुहानि का मुआवजा देगी। राज्य सरकार ने आवास की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी 6-6 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानों के अनुसार आवास बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है, पहली प्राथमिकता आवागमन की व्यवस्था बनाना है। इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। सड़क, पुल और पुलिया को दुरुस्त कर चलने लायक बनाया जा रहा है।

बाढ़ में जो पशु बह गए और उनके शव नहीं मिले, उनके मालिकों को मुआवजा देने के लिए राज्य में अभी तक कोई नियम नहीं है। इस कारण अलग-अलग जिलों के एसडीएम ने वरिष्ठ अफसरों से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। डबरा एसडीएम प्रदीप शर्मा के मुताबिक बाढ़ में हर बार पशु बहते हैं लेकिन इससे पहले इनके बदले में मुआवजा नहीं बांटा गया। अभी तक पशु की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम होने पर ही पशु मालिक को मुआवजा दिया जाता रहा है। इस बार बड़ी संख्या में पशुहानि हुई है इसलिए शासन स्तर से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।

2 लाख से अधिक प्रभावित

ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना जिले में बाढ़ से हुए नुकसान के इस प्रारंभिक अनुमान में सड़क, पुल, पुलिया और बांध टूटने से सरकारी विभागों को हुआ नुकसान शामिल नहीं है। राजस्व विभाग ने यह रिपोर्ट सरकार से साझा की है।

बारिश से 300 पुल टूटे

अगस्त के शुरुआती 10 दिन आधे मप्र में हुई झमाझम बारिश से सड़कों की दशा बिगड़ गई है। 300 से ज्यादा छोटे-बड़े पुल ध्वस्त या तहस-नहस हो गए। 471 किमी की सड़कें बर्बाद हो गई हैं। इन्हें सुधारने के लिए तुरंत 400 करोड़ रुपए चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल संभाग के विदिशा सहित 10 जिलों में हुआ है। विदिशा-राजगढ़ सड़कें तबाह हो गई हैं। नेशनल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है, इन्हें सुधारने के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए। ये स्थिति तब बनी है, जब आधा मप्र अभी भी सूखा है। इन सड़कों और पुलों को सुधारने के लिए पीडब्ल्यूडी ने राज्य सरकार से कहा है कि वो बचत मद से 161 करोड़ रुपए दे। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई और ईएनसी अखिलेश अग्रवाल से स्थिति की समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रतनगढ़ में बाढ़ में बहे पुल को नई डिजाइन से बनाया जाएगा। नए कंसलटेंट तय होंगे। पीडब्ल्यूडी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि 23 बड़े और 293 छोटे पुलों को नुकसान हुआ है। 7 बड़े पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। सड़कों में ज्यादा नुकसान मुख्य जिला मार्ग को हुआ है। यह कुल क्षतिग्रस्त सड़कों का 70 प्रतिशत है। कई प्रमुख मार्ग भी तबाह हो गए हैं। अब सरकार पुल-पुलियों और सड़क की मरम्मत के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रही है। वहीं छोटे-छोटे निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके।

ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होंगे बाढ़ से प्रभावित गांव

जो लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उन्हें ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। जिनके मकान बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए नए आवास ऊंचे स्थानों पर ही स्वीकृत किए जाएंगे। प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था की स्थापना, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, अधोसंरचना को स्थापित करने, नुकसान हुई फसलों के आंकलन और गिरने वाले घरों के सर्वे को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावितों को छह-छह हजार रुपए की राहत राशि मिलना शुरू हो गई है। अब तक 6 करोड़ 50 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं। वही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पुनर्वास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बाढ़ से बेघर हुए लोगों को स्थाई आवास उपलब्ध कराने नीति बनाने की जरूरत है। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कई परिवारों के सिलेंडर बाढ़ में बह गए। उन्हें दोबारा दिलाने केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश में बनाई टास्क फोर्स के सदस्य, जिलों के प्रभारी मंत्री तथा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्य ने भी सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भिंड, विदिशा के अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों से चर्चा के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी को निर्देश दिए। प्रदेश में केंद्रीय दल 16 को अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने क्षेत्र का भ्रमण करेगा।

इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं। बाढ़ से बचाव कार्य में 8832 लोगों को बचाया गया और 32 हजार लोगों को सुरक्षित राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक लगभग पौने दो हजार करोड़ रुपए के पुल, सड़क, सरकारी भवन के साथ बिजली वितरण व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। एक लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। राजस्व विभाग के सूत्रों ने बताया कि 1 हजार 131 गांवों के 1 लाख 13 हजार 929 बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। 8 हजार 318 बिजली के खंभे गिरने और 66 सब स्टेशन तहस-नहस हो गए। इसकी वजह से कई दिनों तक गांवों में बिजली नहीं रही। ऊर्जा विभाग के अमले ने दिन-रात एक करके बिजली आपूर्ति बहाल कर ली है। सरकारी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। 2 हजार 444 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 1 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके और बढ़ने की संभावना है। राज्य आपदा राहत कोष में 1 हजार 941 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसमें से 565 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए 161 राहत शिविर लगाए गए थे, जिसमें 21 हजार 555 लोगों को रखा गया। ग्वालियर-चंबल संभाग के 8 जिलों में सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इस कारण लोग गांवों में ही कैद होकर रह गए हैं। वहीं गांवों में अब बीमारी फैलने की संभावना बढ़ गई है।

लापरवाही में बेघर हुए ग्रामीण

अंचल में बाढ़ से तबाही की एक वजह यह रही कि बिना सूचना के ही बांधों का पानी छोड़ दिया गया। मड़ीखेड़ा के कैचमेंट एरिया में लापरवाही से डैम खोलने के आरोप में मड़ीखेड़ा के प्रभारी ईई एसके अग्रवाल को लापरवाही का दोषी मानते हुए प्रमुख अभियंता मदन सिंह ने हटा दिया है। उनके स्थान पर मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना दतिया मनोहर बोराते को मड़ीखेड़ा का प्रभारी ईई बनाया गया है। एसके अग्रवाल को सहायक यंत्री कार्यालय में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में राजघाट बांयी नहर खनियाधाना पदस्थ किया गया है। दरअसल यह पूरी घटना 2 अगस्त की है, जब मड़ीखेड़ा डैम प्रबंधन ने डैम के गेटों को खोलने में लापरवाही बरती थी। जिस वजह से शिवपुरी समेत दतिया और ग्वालियर के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। शिवपुरी में 1 और 2 अगस्त को लगातार तेज बारिश हो रही थी। जिसके कारण 346.25 मीटर की भराव क्षमता वाला डैम 343 मीटर भर गया। जब डैम के कैचमेंट एरिया में दबाव बढ़ने लगा तब देर रात ग्रामीणों को बिना अलर्ट दिए 10 में से 8 गेटों को खोल दिया गया और थोड़ी देर बाद बाकी बचे 2 गेटों को भी खोल दिया गया था। जिनमे से एक गेट को 9 मीटर तक खोला गया। जिसके कारण डैम के नीचे बसे गांवों में पानी भर गया। अचानक बाढ़ की स्थिति बनने से कई लोग गांव में ही फंस गए थे। जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर के सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। शिवपुरी के साथ साथ दतिया और ग्वालियर के कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालत बन गए थे। इस अचानक आए बाढ़ के कारण जान हानि तो नहीं हुई लेकिन हजारों लोगों के घर, खेत और अनाज आदि को काफी नुक्सान हुआ था। जिसका आंकलन अभी जारी है।

सड़कें टूटीं, पुल-पुलिया बहे

ग्वालियर-चंबल संभाग में बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। जगह-जगह सड़क मार्ग कट गए हैं, कई बड़े पुल व सैकड़ों पुलियां भी बह गई हैं। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर दूसरे मार्गों से आना पड़ रहा है। क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत करने पीडब्ल्यूडी का सेतु संभाग अमला जुटा हुआ है। इन पुल एवं पुलियाओं को 10 से 15 दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एक-दो माह में सड़कों से आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। अंचल में रतनगढ़ का बड़ा पुल, सेवढ़ा में सनकुआं क्षेत्र का लांच-पिछोर पुल बाढ़ के बहाव में टूटकर बह गए थे। वहीं जो पुल डूबने वाले डिजाइन से बने थे, वह बाढ़ के बहाव को झेल गए, लेकिन पानी की तेज टक्कर के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन पुलों की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, कई जगह

सड़क कट भी गई है।

मुरैना में क्वारी नदी पर बने तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें नेपरी पुल और दिमनी पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है। यहां मरम्मत के बाद पुलों पर आवागमन शुरू कर दिया गया है। जौरा में तोर तिलावली पुल क्षतिग्रस्त है, इस पर आवागमन बंद है। पहाड़गढ़ क्षेत्र में ग्राम कहार, गेहतोली की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बंद है। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की करीब 20 व पीडब्ल्यूडी की 12 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। सबलगढ़ से कैलारस हाईवे पर कटाव व गड्ढ़े हो गए हैं। जिले में 70 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्योपुर में कूनो नदी का छोटा पुल और श्योपुर-बारां मार्ग में पार्वती नदी का कुहांजापुर पर छोटा पुल कट गया है। गोरस नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त है। इन पुलों पर मरम्मत कार्य चल रहा है। सेतु निर्माण विभाग 10 दिनों में यहां आवागमन शुरू करने की बात कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 12 जगह पुलिया टूटी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तीन सड़क व जिले में करीब 38 किमी की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं चंबल दाहिनी मुख्य नहर 10 से ज्यादा जगहों पर 50-50 मीटर से अधिक लंबाई में क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे चंबल कमांड एरिया में सिंचाई प्रभावित हो सकती है। दतिया में रतनगढ़ का बड़ा पुल, सेवढ़ा सनकुआं क्षेत्र का पुल एवं लांच-पिछोर का पुल बह गए हैं। दो पुलिया भी टूटी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की एक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जिलें में कुल करीब 138 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इंदरगढ़-पिछोर, दतिया-सेवढ़ा, सेवढ़ा बायपास की सड़कें पूरी तरह उखड़ गई हैं। आरडीसी के रीजनल मैनेजर राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि इन्हें बनाने में करीब तीन माह लग सकते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री मनीष उदैनिया कहते हैं कि एक माह में सड़कें ठीक कर ली जाएंगी। इनमें कुछ सड़कें एमपीआरडीसी (मप्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन) के तहत आती हैं।

घाव भरने में लगेगा समय

ग्वालियर-चंबल संभाग में हुई भारी बारिश के बाद अब जैसे-जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है, चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। जिन खेतों की फसलों को किसानों ने उम्मीदों से रोपा था वहां सिर्फ कीचड़ है। आशियानों की छतें ढह चुकी हैं। शहर, कस्बों को जोड़ने वाली सड़कें, पुल-पुलियों का नामो निशान मिट चुका है। कितने का नुकसान हुआ इसके आंकलन के लिए सरकारी टीमें अब मैदान में उतर गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक जितनी तबाही हुई है यदि तुरंत प्रक्रिया शुरू की गई तो इस पुनर्निर्माण में महीनों से लेकर कई साल लग सकते हैं। सर्वाधिक बुरी हालत ग्रामीणों की है। दुनिया का पेट भरने वाले किसान के घर में खाने के लिए अन्न के दाने तक नहीं बचे हैं। पानी भर जाने के कारण घरों के अंदर रखा अनाज और पशुओं का चारा, भूसा तक बह गया है। लोगों को अपने गांवों से पलायन करना पड़ा है। अंचल में करीब 300 गांवों से लोगों को पलायन कर अपना सबकुछ छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है।

शिवपुरी जिले में करीब 40 पुल-पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, नेशनल हाईवे की सड़कें शामिल हैं। नरवर और मगरौनी के बीच पुल टूटने से आवागमन बंद है। नरवर के पास मड़ीखेड़ा पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं खनियांधाना-कदवाया रोड भी क्षतिग्रस्त है। 10 माह पहले शुरू हुआ शिवपुरी फोरलेन बायपास भी धसक गया है। पोहरी क्षेत्र में कूनो पर बना पुल क्षतिग्रस्त है। पोहरी-छर्च के बीच पार्वती नदी पर बनी कई पुलियां भी टूट गई हैं। यहां मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। जिले में 50 किमी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भिंड में भिंड-जखमौली मार्ग व लहार-अमायन मार्ग सहित जिले के 10 मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सिंध नदी पर बने जखमौली और इंदुर्खी पुल बाढ़ में बह गए। ज्वाइंट कलेक्टर वरुण अवस्थी कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का सर्वे किया जा चुका है, जल्द इनका निर्माण कराया जाएगा। ग्वालियर के डबरा, भितरवार, घाटीगांव ब्लॉक की करीब 29 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई स्थानों पर बाढ़ से सड़कें बह गई हैं। इन सड़कों पर बने छोटे पुल व पुलियाएं भी टूट गई हैं। तीनों ब्लॉक में 37 पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं।

अतिक्रमण बना बाढ़ का कारण

ग्वालियर-चंबल के जिलों में आई बाढ़ के बाद किए गए प्रारंभिक आंकलन में यह बात सामने आई है कि अंचल की नदियों, तालाबों, नालों, चरनोई भूमि आदि पर अतिक्रमण बड़ी-बड़ी कॉलोनियां, व्यावसायिक संस्थान, मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि बनाई गई हैं। इस कारण पानी का बहाव बाधित हो रहा है। जिसके कारण बाढ़ की विभीषिका का सामना लोगों को करना पड़ा। अफसरों की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग प्रदेशभर में सरकारी जमीनों, नदी, नालों और चरनोई भूमि पर किए गए अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उसके बाद संभवत: सितंबर से अभियान चलाकर सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अफसरों का दावा है कि प्रदेश में माफिया के कब्जे में करीब 450 अरब की जमीन है। गौरतलब है कि प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी ग्वालियर-चंबल में आई बाढ़ के लिए भू-माफिया को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि तालाबों में कॉलोनियां और नालों में मकान बनेंगे तो बाढ़ जैसे हालात निर्मित होंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे।

बीहड़ों में बढ़ा अतिक्रमण

चंबल नदी किनारे बीहड़ों में प्रस्तावित फोरलेन मेगा हाईवे अटल चंबल प्रोग्रेस-वे के निर्माण की ईंट कब रखी जाएगी इसका किसी को पता नहीं, लेकिन प्रोग्रेस-वे की आहट ने बीहड़ों में अतिक्रमण बढ़ा दिया है। श्योपुर से लेकर मुरैना तक हजारों बीघा बीहड़ों को समतल करके खेत बना लिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह अतिक्रमण उस जगह बढ़ रहा है, जहां प्रोग्रेस-वे का निर्माण होना है। गौरतलब है कि भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान के दीगोद से लेकर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश तक को जोड़ने के लिए 404 किमी लंबा अटल चंबल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई मप्र के श्योपुर, मुरैना व भिंड जिले में 309.08 किमी होगी और इसके निर्माण पर 6 हजार 58 करोड़ 26 लाख रुपए का खर्च आंका जा रहा है। प्रोग्रेस-वे से पहले बीहड़ों में बढ़ रहे अतिक्रमण का उदाहरण ऐसे समझिए कि जौरा क्षेत्र के तिंदोखर से लेकर देवगढ़, कोटरा और कोल्हूडांडा तक जिन बीहड़ों में मिट्टी के पहाड़ नजर आते थे वहां अब सैकड़ों बीघा समतल जमीन और कईयों जगह उस जमीन पर खेती नजर आ रही है।

ताल-तलैया हो गए गायब

राजस्व विभाग के अफसरों का दावा है कि प्रदेश में दशकों पहले भूमाफिया ने रसूखदारों के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है। आलम यह है कि प्रदेशभर में हजारों ताल-तलैया गायब हो गए हैं। बकौल यशोधरा राजे रियासत काल में जो ताल-तलैया हुआ करते थे, अब उन तालाबों में भू-माफिया ने कॉलोनी काट ली हैं। अगर तालाबों में कॉलोनी काटी जाएंगी तो बाढ़ के हालात तो निर्मित होंगे ही। राजस्व विभाग से मिली

जानकारी के अनुसार ग्वालियर-चंबल में बाढ़ से 23 हजार से ज्यादा मकान टूटे हैं। 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। 166 सड़कें, 25 बड़ी सड़क और पुल, 2427 शहरी क्षेत्र के पुल-पुलिया और सड़कें, 315 नहर फूटे हैं। नदियों के मुक्त प्रवाह के लिए संघर्ष कर रहे रणजीव कहते हैं कि विकास की मिसाल के रूप में बहुमंजिला इमारतें तैयार करते हुए हम सिर्फ नदियों का घर नहीं छीन रहे, बल्कि नदियों तक पानी लाने वाली छोटी-छोटी जल धाराओं, नाला-खाला और ढांगों को पाटकर हम पानी के हर रास्ते पर कब्जा कर रहे हैं। जिसका खामियाजा हमें ही उठाना पड़ रहा है। वह कहते हैं कि अगर सचमुच हम बाढ़ की आपदा से मुक्ति चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक नदी तंत्र को फिर से जिंदा करना होगा। तथाकथित विकास के हस्तक्षेप ने नदी को रिसोर्स मान लिया है और उसे गटर में बदल दिया है। वे कहते हैं कि हमने तटबंधन, सड़क, पुल-पुलिया और रेलवे का गलत तरीके से निर्माण कर नदियों के रास्ते को बाधित किया है। इसके अलावा नदियों के पेट में अवैध निर्माण हो रहा है। यह अवैज्ञानिक विकास ही बाढ़ के आफत में बदलने की वजह है।

बाढ़ से खतरे में आने वाली आबादी में हुई एक चौथाई वृद्धि

बाढ़ अब तक की चरम मौसम की घटनाओं में सबसे आम है, जिसकी बढ़ोतरी के लिए जलवायु परिवर्तन काफी हद तक जिम्मेवार है। वर्षा पैटर्न में भी बार-बार बदलाव आ रहे हैं, जिससे बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में भारत, चीन, जर्मनी और बेल्जियम जैसे देशों में घातक बाढ़ से अरबों का नुकसान हुआ है, जो अक्सर समाज के गरीब इलाकों को असमान रूप से प्रभावित करता है। भारत में तो बाढ़ आने का दौर जारी है, यहां मानसून किसी राज्य में जरूरत से ज्यादा बरस रहा है, तो वहीं कुछ राज्यों में बारिश में काफी कमी देखने को मिल रही है। अध्ययन के मुताबिक 2000 से 2019 तक दुनियाभर में बाढ़ की वजह से लगभग 65,100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। उपग्रह आधारित आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो दशकों में दुनियाभर में बाढ़ के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या में लगभग एक चौथाई की वृद्धि हुई है। जिससे पता चलता है कि दुनियाभर में 8.6 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में रहते है जहां बाढ़ आने की सबसे अधिक आशंका है। अधिकांश बाढ़ मानचित्र आधारित वर्षा और ऊंचाई जैसे जमीनी स्तर के अवलोकन मॉडलिंग पर निर्भर करते हैं, लेकिन वे अक्सर उन क्षेत्रों को पूरी तरह से याद कर सकते हैं जिन इलाकों में पहले बाढ़ नहीं देखी गई थी। उन अंतरालों को पूरा करने के लिए, अमेरिका के शोधकर्ताओं की एक टीम ने 2000 के बाद से 169 देशों में 900 से अधिक हरेक बाढ़ की घटनाओं की दो बार हर दिन इमेजिंग के आधार पर उपग्रह के आंकड़ों का पता लगाया। उन्होंने दुनियाभर में आने वाली बाढ़ के लिए डेटाबेस बनाने हेतु आंकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें 913 बाढ़ की घटनाओं में से प्रत्येक से जुड़े मरने वालों की संख्या, विस्थापन और वर्षा के स्तर पर जानकारी प्रदान करता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2000-2015 के बीच 8.6 करोड़ लोग उन इलाकों में चले गए जहां बाढ़ अधिक आती है, जिसमें कि 24 फीसदी की वृद्धि दिखाई दी। 22.3 लाख वर्ग किमी यानी 8,60,000 वर्ग मील, जो कि ग्रीनलैंड के पूरे क्षेत्र से अधिक है, इतने बड़े इलाके में 2000 से 2018 के बीच आई बाढ़ ने 29 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। भविष्य में स्थिति बद से बदतर होने वाली है। कम्प्यूटर मॉडलिंग के द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से लोग दूसरे जगहों पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इतनी बड़ी आबादी का मतलब होगा कि 2030 तक 25 अतिरिक्त देश बाढ़ के सबसे अधिक खतरे का सामना करेंगे।

नए सियासी समीकरण

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में शिवसेना सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार एक साथ दिखाई दे रहे थे। वहीं मुंबई में भाजपा और राज ठाकरे चुपके-चुपके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2019 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाजपा के खिलाफ थी, अब वहीं शिवसेना के खिलाफ भाजपा के साथ आती मनसे नजर आ रही है।

दरअसल 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी उद्धव ठाकरे यह सफाई देते रहे कि भाजपा ने उनके साथ वादाखिलाफी की इसलिए उन्हें कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ी। सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस के साथ शिवसेना के रिश्ते कितने दिन चलेंगे, इस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। कांग्रेस-शिवसेना के मजबूरी वाले गठबंधन पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी लोगों के लिए हैरान करने वाला है। उन्होंने यह कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी थी कि कांग्रेस अपने बलबूते पर आगे का चुनाव लड़ेगी। माना यह जा रहा था कि नाना पटोले, राहुल गांधी के कहने पर यह सियासी बयानबाजी कर रहे थे।

यह बयानबाजी दरअसल तब शुरू हुई जब अपने बयानों के लिए मशहूर शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से बयानों को लेकर काउंटर अटैक किया जा रहा था। अब शिवसेना और राहुल गांधी दोनों को समझ आ गया है कि भाजपा के वर्चस्ववाद के शिकार दोनों राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं। दोनों अतीत तो नहीं सुधार सकते हैं लेकिन वर्तमान और भविष्य को बचा सकते हैं।

कांग्रेस अपने वैभव को भूलकर उन राज्यों के छोटे दलों के साथ गठबंधन को मजबूत कर रही है, जहां वे कांग्रेस से बेहतर भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। वहां उन क्षेत्रीय दलों की ताकत को कांग्रेस मान रही है। राहुल गांधी सभी विपक्षी पार्टियों को जुटाकर, विचारधारा भुलाकर पार्टियों के साथ एकजुट हो रहे हैं। 1965 से लेकर 1989 तक विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ माहौल तैयार किया। अब कांग्रेस अतीत भूलकर विपक्षी पार्टियों को मनाने में जुटी है। महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना बेहद मजबूत पार्टी मानी जाती है, वहां कांग्रेस अलग जाने का लोकसभा चुनावों में जोखिम नहीं लेगी। उप्र के बाद महाराष्ट्र ही है, जहां बड़ी संख्या में लोकसभा सीटे हैं।

दूसरी तरफ शिवसेना में एक वर्ग है, उसे लगता है कि अब केंद्र में भी भाजपा के खिलाफ राजनीति करने का वक्त आ गया है। उस वर्ग को लगता है कि साथ में रहने के बाद भी भाजपा उन्हें निगल सकती है। इससे बेहतर कमजोर कांग्रेस का साथ देना होगा, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए कम से कम कुछ साल के लिए चैलेंज नही बन सकती। अगर उद्धव ठाकरे की मौजूदा सरकार टिकेगी तो 2024 में भाजपा के लिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव मुश्किल भरे हो सकते हैं। भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राज ठाकरे को साथ में कैसे लिया जाए। लेकिन दोनों दलों को सियासी माहौल ने यह इशारा कर दिया है कि दोनों को साथ आना होगा अगर शिवसेना से लड़ाई लड़नी है। दरअसल भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल राज ठाकरे से मिले और उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया को कहा कि जैसे दो हिंदू एक-दूसरे से मिलने के बाद कहते वैसे हम फिर मिलेंगे। चंद्रकांत पाटिल ने यह भी कहा कि राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोधी नहीं हैं। भाजपा को भी इस बात का एहसास है कि 2022 में होने वाले महानगरपालिकाओं के चुनाव में अगर पार्टी शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को मात नहीं देगी तो बेहद मुश्किल होगी। मुंबई, ठाणे, कल्याण और नासिक में भाजपा का सीधा मुकाबला शिवसेना से है। पुणे में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से और नागपुर में कांग्रेस से। भाजपा की मुख्य लड़ाई मुंबई में रहेगी, ऐसे में अगर शिवसेना और एनसीएसी अगर साथ आ गए, तो भाजपा की राह मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे राज ठाकरे को साथ लेकर भाजपा उन्हें राजनीतिक जीवनदान दे सकती है, लेकिन इस समय वे भी फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं।

● **बिन्दु माथुर**

दिल्ली आईं ममता बनर्जी यही दोहराती दिखीं कि सोनिया गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं मगर राहुल को लेकर मौन रहीं। देश में अब तक अलग-अलग तरह के कई प्रयोग हो चुके हैं और किसी को कोई भ्रम नहीं है कि एकजुटता के लिए धुरी का मजबूत होना जरूरी है।

कमजोर धुरी पर विपक्षी एकता

मई के पहले सप्ताह में बंगाल चुनाव के नतीजे आए, जिसमें ममता बनर्जी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की और उसके साथ ही पूरे देश खासकर उत्तर भारत में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा तैयार करने की बहस छिड़ गई। विपक्ष मजबूत रहे, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन रोचक बात यह है कि यह बहस राजनीतिक स्तर पर बाद में छिड़ी, इंटरनेट मीडिया पर पहले शुरू हो गई। बाद के दिनों में राजनीतिक स्तर पर भी हलचल दिखी। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय राजनीतिक मजबूरी के बीच अक्सर फंसे दिखे शरद पवार ने दिल्ली में अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की और कांग्रेस को छोड़कर अन्य विपक्षी दलों और अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। फिर ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपनी धमक दिखाई, पर अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस कथित विपक्षी एकता के लिए क्या दल वास्तव में तैयार हैं? वे दल कौन से हैं, जो इस मोर्चे का अंग हो सकते हैं? इस संभावित मोर्चे का स्वरूप क्या होगा? देश में अब तक अलग-अलग तरह के कई प्रयोग हो चुके हैं और किसी को कोई भ्रम नहीं है कि एकजुटता के लिए धुरी का मजबूत होना जरूरी है। फिलहाल क्षेत्रीय दलों की ओर से जिस तरह राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, उससे परिधि के मजबूत और धुरी के कमजोर होने का ही अहसास होता है।

विपक्ष कमजोर नहीं है

एक अर्से से और खासकर 2014 के बाद से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है और इसी कारण वह प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। यह एक मिथ्या धारणा है। यदि किसी एक दल या गठबंधन की सरकार बहुमत हासिल कर ले तो इसका यह मतलब नहीं होता कि विपक्ष कमजोर हो गया है। 2014 और 2019 में मोदी के नेतृत्व में राजग ने बहुमत अवश्य हासिल किया, लेकिन वैसा नहीं जैसा राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में हासिल किया था। उन्होंने चार सौ से अधिक सीटें हासिल की थीं। तब विपक्ष के दिग्गज नेता तक चुनाव हार गए थे और उसका संख्याबल भी सिमट गया था। आज यह स्थिति नहीं है।

विपक्षी एकजुटता की बात होते ही सबसे पहले 1977 ही उभरता है, जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट नहीं, बल्कि एक हो गया था। उस वक्त अभूतपूर्व स्थिति बनी थी। देश में आपातकाल लागू हो गया था। मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, एक्टिविस्टों को जेल मे बंद कर दिया गया था। इन घटनाओं का प्रभाव राजनीति तक सीमित नहीं था। जनता के अंदर खौफ था। लिहाजा कुछ दल, जिनमें जनसंघ भी बड़ा घटक था, एक हो गए। इस विलय से दलों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो दिया और नाम पड़ा जनता पार्टी। इस विपक्षी एकजुटता को जनता का समर्थन भी मिला था, लेकिन दक्षिण भारत में इसका असर नहीं दिखा। आपात स्थिति में अभूतपूर्व विलय के बावजूद आंतरिक दबाव भारी पड़ा और दो साल के अंदर सरकार चरमरा गई। जाहिर है आज के दिन ऐसी एकजुटता और ऐसे किसी विकल्प पर विचार संभव ही नहीं है।

क्या तुक : विपक्ष किसी मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दे और सदन में नारेबाजी भी करे...

आखिर इस बात का क्या तुक है कि विपक्ष किसी मसले पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे और सदन में नारेबाजी भी करे? वह जितनी मेहनत किसी मसले पर चर्चा के लिए नोटिस देने में करता है, उससे अधिक विभिन्न मसलों पर नारेबाजी के लिए तख्तियां बनाने और उन्हें सदन में लहराने के लिए करता है। न जाने कितने सांसद ऐसे हैं जो अपनी सारी ऊर्जा इसी में खपा देते हैं कि उनकी तख्ती लोकसभा या राज्यसभा टीवी के कैमरे में कैद हो जाए। कैमरे इससे बचते हैं। इसीलिए जनता को वह बेहूदा दृश्य देखने को नहीं मिला जब तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ रहे थे।

जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद वह चाहे वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार हो या फिर 1996-98 तक दो प्रधानमंत्रियों के साथ चली संयुक्त मोर्चा सरकार, उसने बार-बार साबित किया कि धुरी कमजोर हो तो बिखरना तय है। एक और बात जो हर किसी के ध्यान में है कि विपक्ष एक स्वर से आवाज उठा रहा हो तो राजनीति पर असर कुछ और होता है। अगर अंदर से ही आरोप उठने लगें तो सरकार के लिए स्थिति विकट हो जाती है। बोफोर्स का जो भूत अब तक कांग्रेस के सिर से नहीं उतर पाया है, वीपी सिंह सरकार उसी की उपज थे, लेकिन उनकी सरकार बाहर से समर्थन दे रही भाजपा के रहमोकरम पर टिकी थी। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर सरकार कांग्रेस की मोहताज बनी और वह चार माह भी नहीं चल सकी।

इसके कुछ अंतराल के बाद कांग्रेस की मेहरबानी से बनी संयुक्त मोर्चा सरकार बार-बार ध्वस्त हुई। पहले देवगौड़ा की सरकार गई, फिर गुजराल सरकार। गुजराल सरकार महज इसलिए चली गई थी, क्योंकि जैन आयोग ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में द्रमुक को कठघरे में खड़ा कर दिया, जो उस गठबंधन सरकार में शामिल था। यानी एक क्षेत्रीय दल पर आई आंच प्रधानमंत्री पर भारी पड़ी। वही कांग्रेस अब तमिलनाडु में द्रमुक की बगलगीर बनी हुई है।

इसमें शक नहीं कि अपनी राजनीतिक गति और रणनीति से चमक रही भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना चाहता है, लेकिन उसे इतिहास भी याद है और आज के दिन विचारधारा से लेकर रणनीति तक के स्तर पर आपसी टकराव की जानकारी भी। चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और फिर मनमोहन सिंह की दो सरकारों की सफलता जरूर उन्हें उत्साहित कर रही होगी, लेकिन तब और अब में एक बड़ा अंतर केंद्रबिंदु का ही है। दोनों के कार्यकाल में मुख्य पार्टी तो मजबूत थी ही, खुद नेतृत्व को लेकर गठबंधन में आपत्ति नहीं थी। वे स्वीकार्य थे। आज यही सबसे बड़ा सवाल है, जिसे साथी दलों को सबसे पहले सुलझाना होगा। हाल में दिल्ली आईं ममता बनर्जी बार-बार दोहराती दिखीं कि सोनिया गांधी से उनके अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सवाल पर वह चुप ही रहीं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता का यह बयान अवश्य आया कि नेतृत्व का सवाल बाद में आना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं कि यह एकजुटता के लिए जरूरी मूल सवाल को टालने के अलावा और कुछ नहीं है।

कांग्रेस के अंदर की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। औपचारिक नेतृत्व का बड़ा सवाल मुंह बाएं खड़ा है। चूंकि कांग्रेस में राहुल गांधी ही औपचारिक और अनौपचारिक नेता हैं इसलिए उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट रणनीति बनाने के लिए हाल में विपक्षी दलों को नाश्ते पर बुलाया। बसपा और आम आदमी पार्टी को छोड़कर 14 दल उपस्थित हुए। पहली बार तृणमूल कांग्रेस के नेता भी आए। यह कांग्रेस को उत्साहित कर रहा होगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि सदन के अंदर तृणमूल ही सबसे उग्र विपक्षी दल दिखने की कोशिश कर रहा है। यह भी देखें कि एकजुटता की कोशिश में विपक्ष जनता के मुद्दे को ही भूल गया। न महंगाई मुद्दा बना, न कोरोना। बस वह पेगासस छाया रहा, जो विपक्ष को जोड़ने और जनता को आकर्षित करने का काम नहीं कर सकता।

विपक्ष का संख्याबल कमजोर नहीं कहा जा सकता, न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। सच तो यह है कि मोदी सरकार राज्यसभा में अभी भी बहुमत से दूर हैं। आखिर इस स्थिति में विपक्ष को कमजोर बताने का क्या मतलब? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मिथ्या धारणा का बंधक बनकर रह गया है कि वह कमजोर है। विडंबना यह है कि इस धारणा को बनाने का काम खुद विपक्ष ने यह कहकर किया है कि मोदी सरकार बहुमत के बल पर मनमानी कर रही है। जिसे विपक्ष सत्तापक्ष की मनमानी बताता है, वह दरअसल सरकार का संसदीय कौशल है। इसी कौशल के कारण राज्यसभा से ऐसे भी अनेक विधेयक पारित हो गए, जिन पर विपक्ष को आपत्ति थी। ये विधेयक इसलिए पारित हो गए, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था या फिर उसने तार्किक रवैये का परिचय नहीं दिया। वह राज्यसभा में अक्सर ऐसा व्यवहार करता रहा जैसे उसे लोकसभा की गलतियों को ठीक करने का अधिकार मिल गया है। वह यह भी आभास कराता रहा कि देश की जनता ने मोदी सरकार को बहुमत देकर गलती कर दी है और इस गलती को सुधारने का दायित्व उस पर आ गया है। जब कभी वह ऐसा करने में नाकाम रहा तब उसने यह रोना रोया कि सरकार बहुमत के बल पर अपनी ही चला रही है। इसी के साथ यह मिथ्या धारणा बनाई जाने लगी कि विपक्ष तो कमजोर है। संसद में हंगामा मचाने के प्रति विपक्ष की अतिरिक्त दिलचस्पी से यही लगता है कि उसका मकसद सदन की कार्यवाही ठप कराना होता है। निसंदेह वह अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे यह कभी नहीं लगता कि वह एक मजबूत विपक्ष है। वह जमाना बीत गया जब सदन की कार्यवाही बाधित होना बड़ी खबर बनती थी। ऐसी खबरें अब जनता का ध्यान भी मुश्किल से ही आकर्षित करती हैं।

● इन्द्र कुमार

'संसद लोकतंत्र का वो सर्वोच्च मंदिर है, जहां जनता के प्रतिनिधि हजारों-लाखों प्रजा की आवाज बनकर सार्थक बहस करते हैं और देश की प्रगति की राह प्रशस्त करते हैं। संसद में देश की करोड़ों जनता की ताकत सन्निहित है। संसद देश की गरिमा का प्रतीक है, देश के मस्तक का भाल है। अगर कोई संसद की गरिमा को खंडित करने का प्रयास करता है, वो जनता की नजरों में गिर जाता है। राज्यसभा की गरिमा को कुछ सांसदों ने जिस तरह तार-तार किया, उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए।'

संसद में शर्मसार होता लोकतंत्र

संसद का मानसून सत्र तय समय से दो दिन पहले ही खत्म हो गया। 19 दिन चला ये सेशन इस लोकसभा का सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन रहा। 19 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान कुल 19 दिन संसद के दोनों सदन चलने थे, लेकिन केवल 17 दिन ही चले। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 22 प्रतिशत रही तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 29 प्रतिशत।

लोकसभा में इस दौरान कुल 96 घंटे कामकाज होना था, लेकिन सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट ही काम हुआ। यानी, कामकाज के तय घंटों में से 74 घंटे 46 मिनट काम नहीं हो सका। इस दौरान 20 बिल पास किए गए। इनमें ओबीसी बिल भी शामिल है। जिसमें ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार एक बार फिर राज्यों को दे दिया गया।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 6 सेशन हुए हैं। इनमें ये सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन रहा है। मौजूदा लोकसभा में ये लगातार चौथी बार है जब सेशन की कुल अवधि को कम किया गया है। वहीं, 2020 का शीतकालीन सत्र कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था। इस सेशन में पास हुए कई बिल बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए।

भारत स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की उमंग में है। इस बीच भारत ने राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में छलांग लगाई है। यहां अपने संविधान की सत्ता है। अनेक संवैधानिक संस्थाएं है। प्रतिष्ठित न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखने वाली विधायिका है। विधायिका में केंद्रीय स्तर पर संसद व राज्यों में विधानमंडल हैं। संसद के पास कानून बनाने व संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से संसद ने निराश किया है। अमृत महोत्सव के ठीक पहले संसद की कार्यवाही में बाधा डालने वाली घटनाओं से राष्ट्र सन्न है और संसद बाधित करने वाले महानुभाव प्रसन्न।

संविधान निर्माताओं ने लंबी बहस के बाद संसदीय प्रणाली अंगीकृत की थी। संविधान सभा की कार्यवाही भी संसदीय प्रणाली से ही चली थी। सभा 165 दिन चली थी। अल्पसंख्यक आरक्षण पर हुई बहस में उत्ताप था, लेकिन कागज छीनने, अध्यक्ष के आसन पर चढ़ाई करने और अधिकारियों से धक्का-मुक्की करने जैसी घटनाएं नहीं हुईं। सामान्यतया 1968 तक सदन में व्यवधान नहीं थे। संसद पवित्र मानी जाती थी। आरंभिक दौर में संसद ने बहुत उत्पादक कार्य किया। शालीनता और मर्यादा स्वाभाविक आचरण थी। लोकसभा में अध्यक्षीय आसन के पीछे 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' लिखा हुआ है। धर्म भारत के मन, आचरण और प्रज्ञा की आचार संहिता है। इसी सभा में पहले दिन प्रवेश करते

हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीढ़ियों पर साष्टांग प्रणाम किया था। डॉ. राममनोहर लोहिया संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए आक्रामक रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी संसदीय शिष्टाचार के शिखर पुरुष थे। उनकी आक्रामकता में भी विनम्रता का मधुरस था। पहली लोकसभा में पं. नेहरू, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि महानुभाव थे, लेकिन अब उसी सभा भवन में अध्यक्षीय आसन पर भी हमला है।

अध्यक्ष-सभापति का आसन आदरणीय होता है। संसदीय नियमों के अनुसार अध्यक्ष-सभापति के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन ताजे विवाद में विपक्ष ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया। पीठ पर भी आरोप लगाए गए। संसदीय इतिहास में संभवत: पहली बार मार्शल के साथ दुर्व्यवहार हुआ। प्रक्रिया नियमावली तार-तार हो गई। माननीयों के ऐसे आचरण के विरुद्ध नियमावली में कार्रवाई के विधान हैं, लेकिन ऐसे कठोर नियमों से उदारता बरती गई। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आहत हैं। उन्होंने ऐसे आचरण का संज्ञान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभद्र आचरण को गंभीरता से लिया है। कई दिन चले सुनियोजित हंगामे से सारी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। यह सब किसी तात्कालिक घटना का विस्तार नहीं है। सदन में कभी-कभी गहमागहमी बढ़ती है, लेकिन मानसूत्र सत्र का धाराप्रवाह हंगामा विपक्ष का सचेत और सुनियोजित कृत्य है। यह संसदीय व्यवस्था पर सीधा हमला है।

सर्वोच्च न्यायपीठ ने संसदीय प्रणाली को संविधान का मूल ढांचा बताया था। यही संसदीय प्रणाली निशाने पर है। राष्ट्र जीवन प्रश्न बेचैन है। अनेक मूलभूत प्रश्न हैं। क्या हमारे जनप्रतिनिधि संवैधानिक शपथ के प्रति निष्ठावान नहीं हैं? क्या वे संसद और सड़क में फर्क नहीं करते? क्या वे संसदीय कार्यवाही को राष्ट्रहित का साधन नहीं मानते? क्या वे सदन के भीतर हुड़दंग को ही सभी समस्याओं का उपचार मानते हैं? क्या वे सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए संसद के सदुपयोग पर विचार नहीं करते? अंतिम प्रश्न यह है कि क्या वे हुड़दंग को ही विपक्ष का कर्तव्य मानते हैं? आखिरकार संसदीय मंच के सार्थक वाद-विवाद के संबंध में उनका दृष्टिकोण क्या है? सत्ता और विपक्ष परस्पर शत्रु नहीं होते। दोनों जनादेश की कोख से ही निकलते हैं। सत्ता पक्ष सरकार के माध्यम से अपने नीति कार्यक्रम लागू करता है। विपक्ष निगरानी करता है। सत्ता व विपक्ष संसद के ही भाग हैं। संसद का पोषण दोनों की जिम्मेदारी है। संसद चलाने और कार्यवाही को उत्पादक बनाने की जिम्मेदारी भी दोनों की है, लेकिन यहां विपक्ष ही संसद संचालन में बाधक है।

हंगामे के बीच पास हुए 15 बिल

इस हंगामेदार मानसून सत्र के दौरान 15 बिल सदन में पास हुए। वैसे मौजूदा सत्र में कुल 20 बिल पेश हुए। संसद में एक बिल पेश होने के औसतन सात दिन के भीतर वह पास हो गया। कुछ बिल तो पेश होने के अगले ही दिन पास कर दिए गए। मौजूदा लोकसभा में तो 70 प्रतिशत बिल एक ही सेशन में पेश हुए और पास हो गए। इससे पहले पिछली लोकसभा में एक ही सेशन में बिल पेश और पास होने का औसत 33 प्रतिशत था। मौजूदा सत्र में लोकसभा में जितने बिल पास हुए हैं उनमें एक बिल पर औसतन 34 मिनट चर्चा हुई। कुछ बिल तो पेश होने के बाद महज 5 मिनट बाद पास भी हो गए। वहीं, राज्यसभा में एक बिल के पास होने से पहले उस पर औसतन 46 मिनट चर्चा हुई। केवल 127वां संविधान संशोधन बिल ऐसा बिल रहा, जिसके पास होने से पहले दोनों सदनों में 1 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। ये बिल 9 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद 10 अगस्त को ये बिल लोकसभा से पास हुआ। इसके बाद राज्यसभा में भी 6 घंटे की चर्चा के बाद इसे 11 अगस्त को पास कर दिया गया। इसके पास होने से आरक्षण के लिए ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को मिल जाएगा। मौजूदा लोकसभा की बात करें तो एक बिल को पास करने से पहले लोकसभा में औसतन 2 घंटे 23 मिनट चर्चा होती है। वहीं, राज्यसभा किसी बिल को पास करने से पहले औसतन 2 घंटे चर्चा करती है। इस सत्र में लोकसभा में 15 बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिए गए।

प्रकृति के सभी अंग विधि नियम बंधन में हैं। जल नियमानुसार नीचे की ओर प्रवाहमान हैं। अग्नि ताप लेकर ऊर्ध्वगामी हैं। वैदिक दर्शन में देवता भी नियम बंधन में हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मजेदार टिप्पणी है कि ईश्वर भी इन नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर और देवता भी विधि विधान के अधीन हैं, लेकिन इसी भारत में विधि निर्मात्री संसद में घोर नियमविहीनता है। विधि निर्माता अपनी बनाई कार्य संचालन नियमावली व परंपरा पर आक्रामक हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था का चीरहरण दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को उचित बताते हुए कहा था कि 'भारत में पहले भी लोकतंत्र था, लेकिन भारत से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था मिट गई। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हम सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं।' इसके विपरीत यहां संसद जैसी संस्थाओं को ही तहस-नहस किया जा रहा है। देश आहत और असहाय है। सदन की शक्ति में राष्ट्र की शक्ति अंतर्निहित है। सभा महाभारत काल में भी थी। उसमें एक खंड का नाम ही 'सभा पर्व' है। सभा की शक्ति घटी। विमर्श घटा। तब महाभारत हो गया।

प्राचीन भारत के लोग सभा की शक्ति और सौंदर्य पर मोहित थे। ऋग्वैदिक काल में भी सभा थी। ऋषि की प्रार्थना है 'हम वाणी भद्र बनाएं। सभा में भद्र बोले-उच्यते सभासु। सभा में भाग लेने वाले सभ्य थे।' वहीं इसी भारत की संसद में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और राष्ट्र लाचार है। यूरोपीय विद्वान अर्सकिन मे ने 'पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रेक्टिस' में 'भ्रष्टाचार के साथ अशोभनीय व्यवहार के कारण भी सदस्यों की बर्खास्तगी की परंपरा बताई है।' कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। संसदीय बाधा और हंगामों पर सदन का विशेष सत्र भी उपयोगी हो सकता है। सदस्यगण हंगामा और धक्कामुक्की के औचित्य पर अपना मंतव्य दें। संभव है कि कुछ माननीय अध्यक्षीय आसन व मार्शल से भिड़ने को भी उत्कृष्ट संसदीय व्यवहार मानते हों। दंडात्मक कार्रवाई भी एक विकल्प है। चुनौती बड़ी है। संसदीय संवाद का कोई विकल्प नहीं है। संसदीय प्रणाली को अग्नि स्नान करना ही होगा। इसी में राष्ट्र की रिद्धि-सिद्धि और समृद्धि है।

● रजनीकांत पारे

भाजपा में असंतोष की आंच

प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया। मैडम राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले रोहिताश्व शर्मा ने अपने क्षेत्र अलवर के बानसूर में जन्मदिन का जोरदार आयोजन किया। इस आयोजन में हजारों लोग मौजूद रहे। रोहिताश्व शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया और कहा- वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाकर ही चैन लूंगा। इस दौरान रोहिताश्व ने कहा कि, 'अलवर जिले में भाजपा को मजबूत करने में मैंने अहम भूमिका निभाई, भाजपा में जिनका जनाधार नहीं है, उन नेताओं ने मुझे पार्टी से निकाला है।' पार्टी से बाहर निकाले जा चुके पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने भाजपा नेताओं पर जमकर हमला किया। रोहिताश्व ने कहा कि, 'मेरा रथ तैयार हो चुका है, बारिश का दौर रुकने के बाद मैं प्रदेश के गांव-गांव जाकर लोगों से बात करूंगा और प्रदेश में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा।' पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने अपनी नेता वसुंधरा राजे के लिए बताया कि जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनको फोन करके बधाई दी है। साथ ही उनको आगे बढ़ने उनकी मनोकामना पूरी करने की बात कही है।' भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने प्रदेश भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि, 'जिन लोगों का कोई जनाधार नहीं है। बेपैंदे के लोगों ने मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।' शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों की संख्या बता रही है कि मैं असली भाजपाई हूं। मुझे उन लोगों के निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।' रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि, 'मैं किसी से नहीं डरता। जो नेता चाटुकारिता करके आगे बढ़े हैं, उनसे मुझे कोई डर नहीं है। मैं इन लोगों को जनाधार वाला नेता नहीं मानता हूं। जनाधार वाला नेता वो होता है जिसको जनता चुनती है, वह सिस्टम से आगे पहुंचता है।' किसान आंदोलन पर रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि, 'देश में किसान आंदोलन कर रहा है, जबकि पंडित दीनदयाल ने कहा था कि देश का किसान समृद्ध रहना चाहिए। अगर किसान समृद्ध रहेगा तो देश समृद्ध रहेगा। लंबे समय से किसान धरना दे रहे हैं। लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है।' प्रधानमंत्री मोदी के लिए रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि, 'देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय बड़े-बड़े आश्वासन दिए थे। किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था। किसान को मजबूत करने का वादा किया था।' इधर पूरे मामले पर नजर रखने वाले राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजस्थान भाजपा में असंतोष की आंच तेज होती जा रही है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पर कतरने की कोशिश में लगा है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीएम प्रोजेक्ट करने की रणनीति में बदलाव किया है। राजे इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने की व्यूह रचना करने में लग गई हैं। तो इधर राष्ट्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे रही है कि पार्टी से इतर जाकर कोई काम ना करें।

हाल ही में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके वफादारों को एक कड़ा संदेश दिया है। पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रह चुके रोहिताश्व शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यह राजे के लिए एक चेतावनी थी कि पार्टी लाइन से अगर अलग चलेंगी तो ऐसा ही कुछ उनके या अन्य समर्थकों के साथ भी किया जा सकता है। रोहिताश्व सार्वजनिक रूप से वसुंधरा को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे। इतना ही नहीं वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की आलोचना भी कर रहे थे। जिसकी वजह से रोहिताश्व शर्मा को इसकी कीमत चुकाते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वसुंधरा राजे को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजस्थान में दबदबा है वो इसे भली प्रकार जानती है। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हैं। इसलिए वसुंधरा राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए व्यूह रचना में लग गई हैं। बताया जा रहा है कि राजे समर्थक प्रमुख नेता पूरे राजस्थान में दौरे करके माहौल बनाने में जुटेंगे। ये दौरा गुप्त तौर पर होगा। राजे के विश्वासपात्र नेता प्रदेश में गुप्त यात्रा करेंगे। इतना ही नहीं खुद पूर्व मुख्यमंत्री राजे भी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए गुप्त यात्रा पर निकलेंगी।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव अगले साल होने वाले उप्र विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सत्ता के गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव ही वो इकलौते शख्स हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। कांग्रेस की महासचिव और उप्र प्रभारी प्रियंका गांधी ने 'ऑफ द रिकॉर्ड' सपा के साथ गठबंधन करने के लिए खुद को ओपन माइंडेड बताकर इस बात को काफी हद तक सही भी साबित कर दिया है। माना जा रहा है कि मिशन 2024 के लिए कांग्रेस उप्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि, अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर लगातार अपने पुराने बयान को दोहरा रहे हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस और बसपा से पूछा कि वे पहले ये तय करें कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से। अखिलेश यादव के इस बयान से संकेत मिल रहा है कि वो उप्र में भाजपा को हराने के लिए गठबंधन कर सकते हैं। अखिलेश यादव की छोटे दलों से गठबंधन की बात के अनुसार कहा जा सकता है कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन मूर्तरूप में आ सकता है। लेकिन, 2019 में सपा और बसपा के बीच बढ़ी कड़वाहट के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का गठबंधन में शामिल होना मुश्किल है। राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि आखिर अखिलेश यादव के हालिया बयान के क्या मायने हैं?

अखिलेश गठबंधन को तैयार!

अखिलेश यादव का ये दांव काफी कुछ वैसा ही है, जैसा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चला था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा से किसके पक्ष में होने का सवाल पूछ कर राजनीति के इस खेल में एक तरह से दोनों ही पार्टियों पर मानसिक तौर पर बढ़त बना ली है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वामदलों के गठबंधन को पार्श्व में ढकेलने की नीयत से अधिकांश विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखकर समर्थन की मांग की थी। हालांकि, ममता बनर्जी को पहले से ही कई विपक्षी दलों का साथ मिला हुआ था। लेकिन, इस चिट्ठी के सहारे उन्होंने कांग्रेस और वामदलों के गठबंधन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद अगर कांग्रेस और वामदल बैकफुट पर नहीं आते, तो भी ममता बनर्जी को फायदा मिलना तय था। वहीं, कांग्रेस और वामदलों के बीच चुनाव में कदम पीछे खींच लेने से ममता बनर्जी को क्या फायदा हुआ, ये सबके सामने है। अखिलेश यादव ने भी अपने हालिया इंटरव्यू के सहारे उप्र में भी पश्चिम बंगाल जैसा माहौल रचने की कोशिश की है। सीधी सी बात है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बसपा से किसकी तरफ होने का सवाल उठाकर ममता बनर्जी की रणनीति अपनाने के संकेत दे दिए हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सपा प्रमुख आने वाले समय में कांग्रेस और बसपा पर इस तरह के सियासी हमलों को और तेज करेंगे।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

राजनीतिक भविष्य की खोज

नीतीश कुमार की मुश्किल ये है कि एनडीए में वापसी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी तो बची हुई है, लेकिन इर्द-गिर्द भाजपा ने पहरा लगा रखा है। नीतीश कुमार को कमजोर करने का कोई भी मौका भाजपा नहीं छोड़ती और मजबूरी में मन मसोस कर रह जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। बकौल नीतीश कुमार विधानसभा की सीटें कम होने पर इनकार के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कुर्सी के बदले में भाजपा हर चीज उनसे छीन लेना चाहती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार के विधायक हों या फिर जेडीयू के अध्यक्ष ही क्यों न हों, भाजपा नेतृत्व ने नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां तो बढ़ा ही दी है। भाजपा के साथ हो जाने के बाद नीतीश कुमार एक-एक करके उन सभी मुद्दों पर समझौते करते गए, जिनको लेकर उनका अपना अलग स्टैंड हुआ करता रहा है, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो, तीन तलाक का मुद्दा हो या जम्मू-कश्मीर से जुड़े धारा 370 का ही मसला क्यों न हो। अब तो ऐसा लगता है नीतीश कुमार की राजनीति तो बस भाजपा को फॉलो करने भर ही बची है।

जातीय जनगणना को तो नीतीश कुमार एक खास रणनीति के तहत एजेंडे के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन पेगासस पर तो करीब-करीब वैसा ही स्टैंड है जैसा दबी जुबान सीएए-एनआरसी जाहिर किया था। सीएए-एनआरसी को लेकर तो नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव प्रचार के भाषण के बाद सख्त लहजे में रिएक्ट भी किया था, देखते हैं किसमें इतना दम है कि हमारे लोगों को बाहर कर पाता है, लेकिन प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर भी कर दिया था। तब प्रशांत किशोर का आरोप था कि नीतीश कुमार ने कदम दबाव में उठाया है। जातीय जनगणना की मांग के साथ पेगासस जासूसी की जांच की डिमांड करने वाले नीतीश कुमार एनडीए के पहले नेता हैं जो जांच की मांग कर रहे हैं। पेगासस पर नीतीश कुमार का स्टैंड विपक्ष की मांग से ज्यादा मेल खा रहा है, लेकिन विपक्ष उससे ज्यादा एक्सेस देने को तैयार नहीं है और जमानत पर जेल से छूट कर राजनीति में फिर से सक्रिय लालू यादव ही नीतीश कुमार के सामने दीवार बनकर खड़े हो जा रहे हैं। कहने को तो लालू यादव यही कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके दिल में रहते हैं, लेकिन ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि विधानसभा चुनाव में, 'उसीने हरवा दिया।' हो सकता है नीतीश कुमार को भी अपना राजनीतिक भविष्य वैसा ही नजर आने लगा हो जैसा कभी इंदिरा गांधी या वीपी सिंह को नजर आया होगा। इंदिरा गांधी और वीपी सिंह के पास तो इमरजेंसी या मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की हैसियत भी रही, लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसी चीजें भी भाजपा के हाथों गंवा चुके हैं, लेकिन जातीय जनगणना में नीतीश कुमार को काफी स्कोप नजर आ रहा है, ऐसा लगता है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग ऐसे वक्त उठाई है जब भाजपा और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की गतिविधियां तेज हो चली हैं, और भाजपा भी मन ही मन इसे गंभीरता से लेने लगी है। उप्र चुनाव में उतरने से पहले पश्चिम बंगाल की हार भाजपा को काफी परेशान कर रही है।

ममता बनर्जी के एक्टिव होने से राहुल गांधी और अब पूरा विपक्ष आगे कुछ पाए या नहीं फिलहाल दबाव बनाने में तो सफल लगता ही है। ऐसे में जबकि भाजपा नेतृत्व आने वाले उप्र विधानसभा चुनाव पर फोकस है, नीतीश कुमार की जातीय जनगणना की डिमांड एक नई चुनौती बनकर उभर रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार को मल्टीपरपज हथियार जैसा लग रहा है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना के नाम पर तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लालू यादव को नए सिरे से दोस्ती का ऑफर भी दे रहे हैं और भाजपा को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी-शाह को मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके नाम पर वो एनडीए फिर से छोड़ भी सकते हैं और भाजपा ऐसा फिलहाल तो नहीं ही चाहेगी। भाजपा की मुश्किल ये है कि उसके पास अभी तक नीतीश कुमार का विकल्प पूरी तरह तैयार नहीं है।

● विनोद बक्सरी

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

अफगान में अब तालिबान शासन

आखिरकार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। इससे अफगानिस्तान में अफरा-तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। अब पूरे विश्व की निगाह तालिबान हुकूमत पर रहेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के सत्ता संभालते ही यह बात स्पष्ट होने लगी थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से जल्द ही अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ समय पहले बाइडन ने अचानक यह घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से अपने साजो-सामान के साथ लौट आएंगी। इस घोषणा के साथ ही तालिबान ने अपनी सैन्य सक्रियता और बढ़ा दी।

अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और 15 अगस्त को उसने काबुल को भी कब्जे में ले लिया। तालिबान की लड़ाई आसान बनाने के लिए पाकिस्तान से लश्कर और जैश के लड़ाके भी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। जब अमेरिका की बची-खुची सेनाएं अफगानिस्तान से लौटने की तैयारी कर रही हैं, तब अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि वह इराक से भी एक साल के अंदर अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा। अमेरिका ने दो दशक पहले अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया से आतंक को समाप्त करने के लिए यहां अपने कदम रखे थे, लेकिन वह ऐसा किए बगैर ही अपनी सेनाओं को वापस बुला रहा है। अफगानिस्तान और इराक से सेनाएं लौटाने का डेमोक्रेटिक पार्टी का फैसला अमेरिकी नागरिकों की इस सोच पर आधारित है कि आखिर उनके अपने लोग दूसरे देशों में अपनी जान क्यों गंवाएं? अमेरिका अब इस नीति पर पहुंच रहा है कि जिन देशों में आतंकी संगठन सक्रिय हैं और वे अमेरिकी हितों के लिए खतरा बन सकते हैं, वहां की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने से बचा जाए। इसके बजाय वह ड्रोन या हवाई हमलों से आतंकियों को निशाना बनाने का काम करेगा।

● ऋतेंद्र माथुर

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सभी किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में पेयजल एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, बड़वाह, जिला-खरगौन

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सभी किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में पेयजल एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, सेंधवा, जिला-बड़वानी

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- सभी किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में पेयजल एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, हरसूद, जिला-खंडवा

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में पेयजल एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सभी किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, खेतिया, जिला-बड़वानी

75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

अपील

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
- हम्माल तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ प्राप्त करें।
- मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएं।
- सभी किसान भाई सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएं।
- किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही करें।
- नीलामी के समय किसान भाई अपनी ढेर पर उपस्थित रहें।
- मंडी प्रांगण में पेयजल एवं कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है।

सचिव

भार साधक अधिकारी

कृषि उपज मंडी समिति, अन्जड़, जिला-बड़वानी

चुनौतियों से घिरे इमरान खान

पाक अधिकृत कश्मीर में हाल में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जोरदार जीत हासिल कर ली। इससे पहले यहां नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में थी। इस जीत से इमरान खान खासे उत्साहित इसलिए भी हैं, क्योंकि उन्होंने यहां शिकस्त पंजाब के दिग्गज नेता नवाज शरीफ की पार्टी को दी है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर में सत्ता वही हासिल करता है जिसका नेशनल असेंबली में बहुमत होता है और जिसे सेना का पूर्ण समर्थन हासिल होता है। नवाज शरीफ की पार्टी भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सत्ता उस वक्त हासिल करने में सफल हो गई थी जब नवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान ने भी इसी परंपरा को दोहराया है। अगर इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं होते और सेना का समर्थन नहीं मिला होता तो पाक अधिकृत कश्मीर में सत्ता हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के चुनाव नतीजे कुछ कारणों से इमरान खान के लिए सुखद हैं। वे इस जीत की आड़ में अब अपनी सरकार की तमाम नाकामियों को छुपाने में जुट गए हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव 2023 में होने हैं। इसके लिए इमरान हालिया चुनाव नतीजों को भुनाएंगे। पाकिस्तान लंबे समय से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और इमरान सरकार इन समस्याओं से निपटने में नाकाम रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। बेशक पाक अधिकृत कश्मीर में इमरान की पार्टी जीत गई हो, लेकिन कश्मीर मसले को लेकर उनका पलड़ा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत ने कई इस्लामिक देशों को अपने पक्ष में कर पाकिस्तान की कूटनीति को बड़ा झटका दिया है। अफगानिस्तान का संकट भी इमरान के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में अपने को सत्ता में बनाए रखना इमरान खान के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री अभी तक विफल साबित हुए हैं। लेकिन उनकी पार्टी की सफलता यह जरूर है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी उन्हें सत्ता मिल गई है। वे अब सिंध की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं जहां अभी तक बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को सत्ता से हटाना तमाम राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल भरा काम रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जीत इमरान खान को सिंध में कितनी मदद देगी, यह तो समय ही बताएगा। क्योंकि जाति, बिरादरी, नस्ल और प्रांतों में विभाजित पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान की बिरादरी कमजोर है। वे पश्तून बिरादरी के हैं जिसका वर्चस्व खैबर पख्तूनख्वा में ही है। इमरान खान पर जाति, बिरादरी का कट्टर समर्थक होने का आरोप लगता रहा है।

पंजाब की राजनीति इमरान के लिए चुनौती भरी साबित होगी। खैबर पख्तूनखवा प्रांत पश्तून बिरादरी का वर्चस्व वाला है। यहां प्रांतीय असेंबली में इमरान खान के पास 94 सीटें हैं। लेकिन पंजाब में नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी ने इमरान की पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। आज भी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में लोग बिरादरी और जाति के नाम पर वोट देते हैं। इमरान खान ने दक्षिण पंजाब में मजबूत बलूच जाति के उस्मान बुजदार को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब की राजनीति में नया खेल शुरू किया। उन्होंने मजबूत जाट, राजपूत और अरैण बिरादरी को किनारे लगाने की कोशिश की। इमरान खान की इस राजनीति को पंजाब की राजनीति में हावी राजपूत, जाट, गुर्जर और अरैण जातियों ने स्वीकार नहीं किया। उत्तर पंजाब की राजनीति में राजपूत मजबूत हैं और मध्य पंजाब में जाट। दूसरी ओर, कश्मीरी मूल के होने के बावजूद नवाज शरीफ ने पंजाब की राजनीति में मजबूत जातियों को बड़ी चालाकी से साधा। 1980 और 1990 के दशक में चौधरी परिवार (चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही) ने इन्हें पंजाब की राजनीति में चुनौती दी थी। लेकिन अंत में उन्हें नवाज शरीफ के साथ लंबे समय तक चलना पड़ा। हालांकि पंजाब की राजनीति में जाट कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जाट बिरादरी से संबंधित इस चौधरी परिवार को न तो नवाज शरीफ नजरअंदाज कर पाए, न ही परेवज मुशर्रफ।

● राजेश बोरकर

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M.: 9329556524, 9329556530 **Email : ascbhopal@gmail.com**

महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक ओर वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने आर्थिक मंदी के चलते काम से बाहर कर दिया और दूसरी ओर वे जिन्होंने बीते डेढ़ साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण स्वयं रोजगार छोड़ दिए। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं काम से बाहर हो रही थीं तभी पुरुषों के भी रोजगार छीने गए इसलिए सिर्फ महिलाओं की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, परंतु क्या वास्तविकता इतनी भर है या इससे इतर कुछ सत्य ऐसे भी हैं, जिनकी चर्चा हम जानबूझकर नहीं करना चाहते?

क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं कितनी भी प्रतिभाशाली और शिक्षित क्यों न हों उन्हें पुरुषों के मुकाबले नौकरी का अपेक्षाकृत कम हकदार माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं की पहली प्राथमिकता समाज द्वारा परिवार की देखभाल निश्चित की गई है। अगर पेशेवर जिम्मेदारियां किसी भी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे अड़चन बनती हैं तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित रूप से अपनी पेशेवर जिंदगी का त्याग करें। समाज महिलाओं के प्रति इससे भी कहीं अधिक निष्ठुरता बरतता है और उन्हें विकल्प के रूप में देखता है। एक ऐसा विकल्प जिसे आवश्यकता होने पर कार्यबल की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाता है और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो पुनः हाशिये पर धकेल दिया जाता है।

इस तथ्य की तह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध खोलते हैं। 18वीं सदी तक स्त्री को घरेलू दायरों तक सीमित करने वाली वैश्विक सोच यकायक प्रथम विश्व युद्ध के समय तब परिवर्तित हो गई जब सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने के लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली जगह की भरपाई महिलाओं द्वारा करने के लिए मुहिम चलाई गई। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और उनकी विपुल क्षमताओं को याद दिलाया गया। महिलाओं से श्रमबल का हिस्सा बनने के लिए आव्हान किया गया। जिन महिलाओं में मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति के अभाव का उलाहना देकर उन्हें कमजोर और डरपोक कहा जाता रहा था वे महिलाएं उन सारी धारणाओं को गलत सिद्ध करते हुए उन फैक्ट्रियों में काम करने लगीं, जहां खतरनाक विस्फोटक सामग्री बनती थी। यहां काम करते हुए उनकी त्वचा पीली पड़ गई जिससे उन्हें 'कैनरी' उपनाम दिया गया।

परिवहन, अस्पताल और वे तमाम क्षेत्र, जो पुरुषों के एकाधिकार माने जाते थे महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। यहां तक कि 6 हजार रूसी महिलाएं 'बटालियन आफ डेथ' का हिस्सा बनीं, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा 'द रेस्टोरेशन ऑफ प्री-वार प्रैक्टिस एक्ट-1919' ने महिलाओं पर दबाव बनाया कि वे अपने पद छोड़ दें जिससे विश्व युद्ध से लौटे सैनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें और ऐसा हुआ भी। वे महिलाएं जिन्होंने पुरुषों के समकक्ष ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन्हें सिर्फ इसलिए कार्यबल से हटा दिया गया, क्योंकि इस पर पुरुषों का अधिकार माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इतिहास पुनः दोहराया गया। इस दौरान 60 लाख महिलाओं ने तमाम ऐसी भूमिकाएं निभाईं, जिन पर पुरुषों का वर्चस्व था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद सांस्कृतिक रूढ़िवादियों ने उन पर दबाव बनाया कि वे नौकरी छोड़ दें। यहां तक कि जिन महिलाओं ने ऐसा करने की अनिच्छा जाहिर की, उनको 'फूहड़' कहा गया।

● ज्योत्सना अनूप यादव

लोककल्याण का मार्ग है गीता

श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीताजी का वर्णन करने के उपरांत कहा है कि 'गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै: शास्त्रविस्तरै:, या स्व्यं पद्मनाभस्य मुखमद्माद्विनि:सुता।' अर्थात् गीता सुगीता करने योग्य है इसे भली प्रकार पढ़कर अंतकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्रीविष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। स्वयं श्री भगवान ने भी गीता के महात्मय का बखान किया है। गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं- एक सांख्ययोग और दूसरा कर्मयोग। उन्होंने कर्म की महत्ता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने फल की आसक्ति छोड़ कर्म करने को कहा है। गीता में भगवान ने मानव जाति के लिए धर्मपरक सदाचार व त्यागपरक आचरण के अनुसरण पर जोर दिया गया है। गीता निराशा के भंवर में फंसे संसार को सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसे ही कर्मयोग कहा गया है।

गीता के शब्द अमृत वचन हैं। संसाररूपी भवसागर से पार उतरने की औषधी है। हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था जब वे सत्य की रक्षा के लिए अपने बंधु-बांधवों से युद्ध करने से हिचक रहे थे। मोहग्रस्त होकर युद्धस्थल में आयुध रख दिए थे। लेकिन श्रीकृष्ण ने उन्हें नश्वर भौतिक शरीर और नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर को समझाकर युद्ध के लिए तैयार किया। बिना फल की आशा किए बिना कर्म का संदेश दिया। श्रीकृष्ण के उपदेश से अर्जुन का संकल्प जाग्रत हुआ। कर्तव्य का बोध हुआ। ईश्वर से आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अधर्मी कौरवों को पराजित किया। सत्य और मानवता की जीत हुई। अन्याय पराजित हुआ।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जगत को समझाया है कि निष्काम कर्म भावना में ही जगत का कल्याण है। श्रीकृष्ण का उपदेश ही गीता का अमृत वचन है। उन्होंने गीता के जरिए दुनिया को उपदेश दिया कि कौरवों की पराजय महज पांडवों की विजयभर नहीं बल्कि धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर और सत्य की असत्य पर जीत है। श्रीकृष्ण ने गीता में धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य और न्याय-अन्याय को भलीभांति परिभाषित किया है। उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्रों को अधर्मी, पापी और अन्यायी तथा पाडुं पुत्रों को पुण्यात्मा कहा है। उन्होंने संसार के लिए क्या ग्राहय और क्या त्याज्य है उसे भलीभांति समझाया। श्रीकृष्ण के उपदेश ज्ञान, भक्ति और कर्म का सागर है। श्रीकृष्ण साक्षात परब्रह्म और ईश्वर हैं। संसार के समस्त पदार्थों के बीज उन्हीं में निहित है। वे नित्यों के नित्य और जगत के सूत्रधार हैं। शास्त्रों में उन्हें साक्षात व साकार ईश्वर कहा गया है। भारतीय चिंतन और धर्म का निचोड़ उनके उपदेश में ही समाहित है। गीता में समस्त संसार और मानव जाति के कल्याण का मार्ग छिपा है। गीता श्रीकृष्ण द्वारा मोहग्रस्त अर्जुन को दिया गया उपदेश है। विश्व संरचना का सार तत्व है।

● ओम

दिवा स्वप्न

जाने कितने दिनों के बाद वह हिम्मत जुटाकर चांदनी रात में उसी नदी के कछार पर पैर लटकाए बैठी है जहां वह पिछले वर्ष भर जाने कितनी बार अपने प्रेमी के कंधे पर सर टिकाए आसमान में उगे चांद पर आशियां बनाने के सपने देखा करती थी। बड़े-बूढ़ों की नसीहतों का अर्थ चोट खाने के बाद समझ में आया, 'जो लड़कियां विधर्मियों से, बेमेल खानपान या संस्कृति वालों से या फिर अधिक उम्र वाले लड़कों के साथ अपने परिवार वालों से विद्रोह कर या भागकर शादी करना चाहती हैं, वे कभी सुखी नहीं रहतीं। लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, खानपान और संस्कृति मिलाकर, पारिवारिक आधार पड़ताल करके ही घर बसाना चाहिए।'

वह भी एक ऐसी ही चांदनी रात थी। वह घर से गहने, कपड़े-लत्ते, पैसे समेटकर आधी रात के बाद सरक आई थी और यहीं उसका इंतजार कर रही थी। बहती ठंडी हवाओं के कारण लघुशंका निवृत्त होने वह अपने सीमित सामान सहित घनी झाड़ियों के पीछे चली गई। तभी वह आता दिखा। मन ही मन प्रसन्न होते कुछ देर गायब रहकर उसकी फिरकी लेने की सोच अपने मोबाइल की घंटी भी बंद कर दी, 'देखे जरा, वह उसे कितना प्यार करता है?' वह झाड़ियों के पीछे दुबकी रही।

उसके इंतजार में हैरान-परेशान वह बार-बार उसका नंबर डायल करता रहा। जवाब नहीं मिला, तो तनाव में बड़बड़ाने लगा, 'कहां रह गई, साली? अता पता नहीं है। मैंने उसकी डील भी पक्की कर दी थी। कुछ देर और नहीं पहुंची तो मुंबई जाने वाली रात्रि बस छूट जाएगी।' तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी।

'मैं भी क्या करूं? चिड़िया अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही, मौसी! लगता है फुर्र हो गई। मैंने उसे जो वक्त दिया था, घंटेभर ज्यादा हो चुका है। ये लड़कियां भी न, इतने पैसे खर्च करो, घुमाओ फिराओ और जब हलाल करने का वक्त आता है तो इनकी मातृ-पितृ भक्ति उमड़ने लगती है', पुनः एक गाली।

निशाचर जीव-जंतुओं का डर तो था, पर इस दोपाया जीव के डर से वह कांप गई। उसके पैर झाड़ियों के पीछे जम गए।

वह देर तक इंतजार करता रहा, बेचैनी में इधर-उधर फोन करता रहा, फिर थक-हारकर लौट गया। उसके जाते ही वह निकलकर घर की ओर सरपट भागी। माता-पिता को सब सच बताकर पुलिस में रपट लिखाई। छानबीन के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, तो आज डरते-डरते पुनः नदी के कछार पर आ बैठी, ताकि अपनी नादानियों पर विचार कर भविष्य की सोच सके।

- नीना सिन्हा

जिओ जिन्दगी

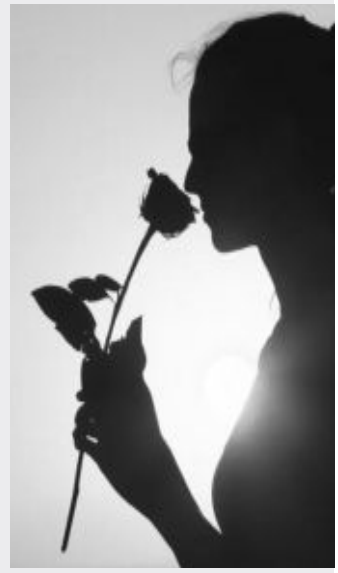

साज का तार बनकर जिओ जिन्दगी।
एक झंकार बनकर जिओ जिन्दगी।
बोझ बनकर जिए तो भला क्या जिए,
एक उपहार बनकर जिओ जिन्दगी।।

चूर थककर हुआ पर सफर में रहा।
जिस्म चलता हुआ हर नजर में रहा।
हाथ आ ही न पाए किनारे कभी,
जिन्दगी का सफीना भंवर में रहा।
उम्र की सीढ़ियों ने सिखाया यही,
एक पतवार बनकर जिओ जिन्दगी।।

ठीक है, गलतियां हो गई हैं कई।
हाथ से कामयाबी फिसल भी गई।
जब खुली आंख, समझो सवेरा हुआ,
और फिर से शुरूआत कर लो नई।
ग्लानि के भाव से मुक्ति पाते हुए,
इक नवाचार बनकर जिओ जिन्दगी।।

क्या करें जब सभी मतलबी हो गए।
मीत भी आजकल अजनबी हो गए।
लोग यूं हो लिए साथ बदलाव के,
छोड़ इंसानियत, मजहबी हो गए।
विश्व-बंधुत्व का भाव कायम रहे,
एक परिवार बनकर जिओ जिन्दगी।।

- बृज राज किशोर राहगीर

इंडिया मांगे मोर

स्वाभाविक ही अनेक रोमांचित देशवासी भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा कांटे के मुकाबले में जर्मनी को चार के मुकाबले पांच गोलों से हराकर जीते कांस्य पदक को 'सोने से कम नहीं' बताकर खुश हो रहे हैं। यह और बात है कि उन्हें महिला हॉकी में कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के हाथोंहाथ आई शिकस्त की कसक भी कुछ कम नहीं सता रही। सुपरमॉम मैरीकॉम के खाली हाथ लौटने का मलाल भी उन्हें है ही। लेकिन यह खुशी इस कसक और मलाल से ऊपर है कि देश ने इस ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का अपना 2012 का लंदन का रिकार्ड तोड़ डाला है। 2012 में उसने दो रजत व चार कांस्य मिलाकर कुल छः पदक जीते थे, जबकि इस बार सात जीते हैं। अब सरकारें, अपनी परम्परा के मुताबिक, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों पर धनवर्षा और उनके घरों तक की सड़कें पक्की करा देने जैसे लोकलुभावन ऐलान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वे ओलंपिक में भाग लेने गए खिलाड़ियों को स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि के तौर पर लाल किले पर तो आमंत्रित करेंगे ही, अपने आवास पर उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे और बात करेंगे।

इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में रचे गए इतिहास और प्रदर्शित जज्बे की सराहना करते हुए कहा है कि वह अब नए भारत की पहचान बन रहा है। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचने का अभूतपूर्व करिश्मा कर दिखाने वाली भारतीय टीम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस ओलंपिक को उनके करिश्मे के लिए ही याद किया जाएगा। नीरज चोपड़ा के गोल्ड की तारीफ तो खैर सारे खिलाड़ियों पर भारी है। लेकिन इन घोषणाओं के बीच मीडिया के एक बड़े हलके का राष्ट्रवाद इतना जोर मारने लगा है कि वह इस 'उपलब्धि' को हाइप देते हुए खेलों की दुनिया में हमारे बुरे हाल से जुड़ी सारी जमीनी हकीकतों को झुठला देना चाहता है। इस कड़वे सच को भी कि लंदन ओलंपिक का रिकार्ड तोड़कर भी हम अपने बुरे हाल की जमीनी हकीकत में बहुत सुधार नहीं कर पाए हैं। दरअसल, यह हकीकत इतनी कड़वी है कि जिस पड़ोसी चीन को हमारे 'राष्ट्रवादी' फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते और जो हमारे बाद गुलामी से आजाद हुआ, आज वह दुनिया के चौधरी अमेरिका के साथ पदकों की होड़ में शामिल है जबकि हम 48वें स्थान पर हैं और हमारी झोली में सिर्फ एक स्वर्ण पदक है, जो 13 साल बाद हासिल होने के कारण अकाल के फल जैसा लग रहा है। कई छोटे-छोटे और अनाम से देश अभी भी हमसे बेहतर स्थिति में और हमसे ऊपर हैं।

● आशीष नेमा

टोक्यो ओलंपिक में भारत के सूरमा

नीरज चोपड़ा	गोल्ड (जेवलिन थ्रो)
रवि दहिया	सिल्वर (रेसलिंग)
मीराबाई चानू	सिल्वर (वेटलिफ्टिंग)
पीवी सिंधू	ब्रॉन्ज (बैडमिंटन)
लवलीना	ब्रॉन्ज (बॉक्सिंग)
बजरंग पूनिया	ब्रॉन्ज (रेसलिंग)
पुरुष हॉकी टीम	ब्रॉन्ज

20 साल की उम्र में सैफ अली खान ने 12 साल बड़ी अमृता सिंह से की थी शादी

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते टूट गया था रिश्ता

नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ अली खान 51 साल के हो चुके हैं। सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे जिन्होंने एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से शादी की थी। माता-पिता में से सैफ ने मां शर्मिला का कैरियर चुना और इंडस्ट्री में आ गए। सैफ ने यश चोपड़ा की फिल्म परंपरा से बॉलीवुड डेब्यू किया था जिसके बाद एक्टर आशिक आवारा, पहचान और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। सैफ का शुरुआती बॉलीवुड कैरियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में रही है।

अमृता सिंह ने तलाक के बाद लगाए सैफ पर गंभीर आरोप

सैफ और अमृता ने शादी के 13 सालों बाद साल 2004 में तलाक ले लिया, जिसके बाद बच्चों की कस्टडी एक्ट्रेस के पास गई। तलाक में अमृता ने 5 करोड़ रुपए की एल्यूमनी और इब्राहिम के 18 साल के होने तक हर महीने 1 लाख रुपए की मांग की थी। अमृता ने तलाक के बाद आरोप लगाया था कि सैफ उन्हें खर्चा नहीं देते और उनके दूसरी महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो सैफ अली खान अमृता से शादी के दौरान ही इटली की मॉडल रोजा कैटलोन के साथ रिलेशन में थे, जो उनकी शादी टूटने का कारण बनी। साल 2004 में शुरू हुआ दोनों का रिश्ता 4 सालों तक चला था। खबरों के अनुसार सैफ के मूड स्विंग्स से परेशान होकर रोजा ने उनसे 2007 में ब्रेकअप कर लिया था।

कैसी थी सैफ-अमृता की लव स्टोरी

बेखुदी फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात अमृता सिंह से हुई थी। उस समय अमृता अपने कैरियर के टॉप पर थीं, और सैफ के कैरियर का कोई ठिकाना नहीं था। पहली मुलाकात में सैफ, अमृता के दीवाने हो गए थे। कुछ दिनों बाद सैफ ने अमृता से डिनर पर चलने को कहा, तो एक्ट्रेस ने साफ इंकार कर दिया। अमृता ने कहा कि वो बाहर डिनर पर नहीं जातीं लेकिन अगर सैफ चाहें तो घर पर आ सकते हैं। सैफ घर पहुंचे और पहली मुलाकात में ही उन्होंने अमृता को प्रपोज कर दिया। सैफ उस समय महज 20 साल के थे और अमृता उनसे 12 साल बड़ी थीं। दोनों की उम्र और कैरियर का फासला सैफ के घरवालों को खटक रहा था। नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ हिंदू अमृता से शादी करना चाहते थे। घरवाले चाहते थे कि अमृता इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थीं। इसी बीच सैफ ने परिवार के खिलाफ जाकर अमृता से अक्टूबर 1991 में शादी कर ली। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2012 में सैफ ने करीना के साथ दूसरी शादी कर ली।

हमारे प्रथम मिलन में ही दबंगीलाल ने मुझे बताया कि अपने विद्यार्थी काल में जब वह हॉकी खेला करते थे, तब स्टिक का उपयोग दूसरे पक्ष की टंगड़ियां तोड़ने में करते थे। और जब क्रिकेट के बैट को हाथ लगाया था तो मुहल्ले की खिड़कियों के इतने कांच तोड़े कि लोगों ने वहां पर दीवारें उठवा लीं। उनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेयर होने की ताकत थी, मगर लोकल राजनीति ने उन्हें उठने नहीं दिया।

स्वयंभू खिलाड़ी

बड़े लोगों के खेल भी बड़े होते हैं और उनकी बातें भी, ऐसा मैं दबंगीलाल से मिलकर ही जान पाया। वह हमारे क्षेत्र के एक कुविख्यात खिलाड़ी हैं। उनका असली नाम इतिहास के गर्त में दफन हो चुका है और अब वह पूरे इलाके में दबंगीलाल के नाम से ही पहचाने जाते हैं। दबंगीलाल से मिलकर मैं धन्य हो गया। वह खेलों के इतने शौकीन हैं कि जहां एक तरफ हमारे क्षेत्र की गिल्ली-डंडा की टीम के आजीवन संरक्षक हैं, वहीं दूसरी ओर महिला वॉलीबाल टीम को भी अपने कब्जे में लेने की खातिर नजरें गड़ाए हुए हैं। उनको इसका पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन सफलता उनके चरणों में लोटती मिलेगी, उसी तरह जिस तरह जब उन्होंने स्थानीय स्टेडियम पर कृपादृष्टि डाली थी तो उसका जीर्णोद्धार करके ही माने थे। इसी के चलते आज उस स्टेडियम के पड़ोस में उनके द्वारा संचालित निजी स्कूल के विद्यार्थियों को एक क्रीड़ागाह हासिल हो गया है।

हमारे प्रथम मिलन में ही दबंगीलाल ने मुझे बताया कि अपने विद्यार्थी काल में जब वह हॉकी खेला करते थे, तब स्टिक का उपयोग दूसरे पक्ष की टंगड़ियां तोड़ने में करते थे। और जब क्रिकेट के बैट को हाथ लगाया था तो मुहल्ले की खिड़कियों के इतने कांच तोड़े कि लोगों ने वहां पर दीवारें उठवा लीं। उनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्लेयर होने की ताकत थी, मगर लोकल राजनीति ने उन्हें उठने नहीं दिया। फिर भी स्थानीय स्तर पर ही सही, वह रिकार्ड और कमाई के मोर्चे पर किसी भी खिलाड़ी से उन्नीस नहीं बैठेंगे। जब वेल्थ की चर्चा आ ही गई तो दबंगीलाल की बातों का कामनवेल्थ गेम्स से होते हुए ओलिंपिक में अपने देश के प्रदर्शन पर आ जाना स्वाभाविक था। वह कहने लगे, 'हाय हम न हुए वहां, वरना दुनिया वालों को समझा आते कि असली खेल क्या होता है? हमसे बड़ा एथलीट कौन होगा? होललाइफ भागादौड़ी में ही गुजरी है। हम अपने जमाने के ऐसे फर्राटा धावक रहे हैं कि कई राज्यों की पुलिस पार्टियां हमारे पीछे भागती रहीं, पर हमसे सोना नहीं छीन सकीं।'

मुझे पूछना पड़ा, 'वाकई आप इस लेबल के खिलाड़ी रहे हैं!' दबंगीलाल अपनी हंसी के स्विमिंगपूल में गोता मारते हुए मुझे समझाने लगे, 'आज के तैराक तो हमारे सामने कल के छोकरे हैं। हमने अपने टाइम में ऐसी-ऐसी गोताखोरियां की हैं कि तरणताल का सारा पानी सोख गए। हमने इद्दी-पिद्दी खेलों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। हमने हमेशा वही गेम खेला जिसमें अपने लिए कम से कम एक-दो किलो सोने का इंतजाम हो सके।' मैंने दबंगीलाल से सवाल किया, 'क्या कभी आपकी तीरंदाजी में भी रुचि रही है?' उन्होंने शतरंजिया स्माइल मारी, 'तीरंदाजी की छोड़ो, पूरे चौबीस कैरेट के शूटर रहे हैं हम। आज हमारे खिलाड़ी एक स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक लाते हैं तो पूरा देश उन्हें सिर-आंखों पर बिठा लेता है।' इसके बाद वह फिर अपनी पर उतर आए और बोले, 'लेकिन यार ये बच्चे कितना सोना ला पाते होंगे?' मैंने कहा, 'वह मात्र सोना नहीं होता। उसमें अपने देश का सम्मान भी भरा होता है। हमारे ओलिंपिक के विजेता खिलाड़ी संपूर्ण राष्ट्र का गौरव होते हैं।' वह मेरी ही बाल मेरी ही कोर्ट में उछालते हुए बोले, 'तो क्या हम राष्ट्र-गौरव नहीं हैं? ओवरएज हो गए हैं, अन्यथा हम भी अपनी जवानी में शातिर शूटर रहे हैं। चाहो तो पुलिस के पुराने रिकार्ड से वेरिफाई करा सकते हो।' इसके बाद वह अपनी लफ्फाजी का हैवीवेट मुक्का तानते हुए कहने लगे, 'किसी से उन्नीस मत समझना हमको। हम अब भी अंधेरे में तीरंदाजी कर सकते हैं और अपना पुराना घूंसेबाजी का शौक आज भी बरकरार है। कल ही दो लोगों के जबड़े तोड़े हैं। हफ्ता-पंद्रह दिन में अपने प्रतिद्वंद्वियों को उनके ही अखाड़े में धूल न चटाएं तो पानी तक हजम नहीं होता है।'

दबंगीलाल के हाथों की खुजली और जिम्नास्टिकिया फ्री स्टाइल देखकर मैंने मन ही मन सोचा, अब शेष उपलब्धियों की जानकारियों के लिए इनका भी डोपिंग टेस्ट कराया जाना निहायत जरूरी है, क्योंकि ऐसे महान लोग यूं ही महान नहीं हो जाते हैं, इसके पीछे उनकी बरसों की नेटप्रैक्टिस की भूमिका भी मायने रखती है।

● **संतोष त्रिवेदी**

Science House Medicals Pvt. Ltd.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

SIEMENS
Ingenuity for life

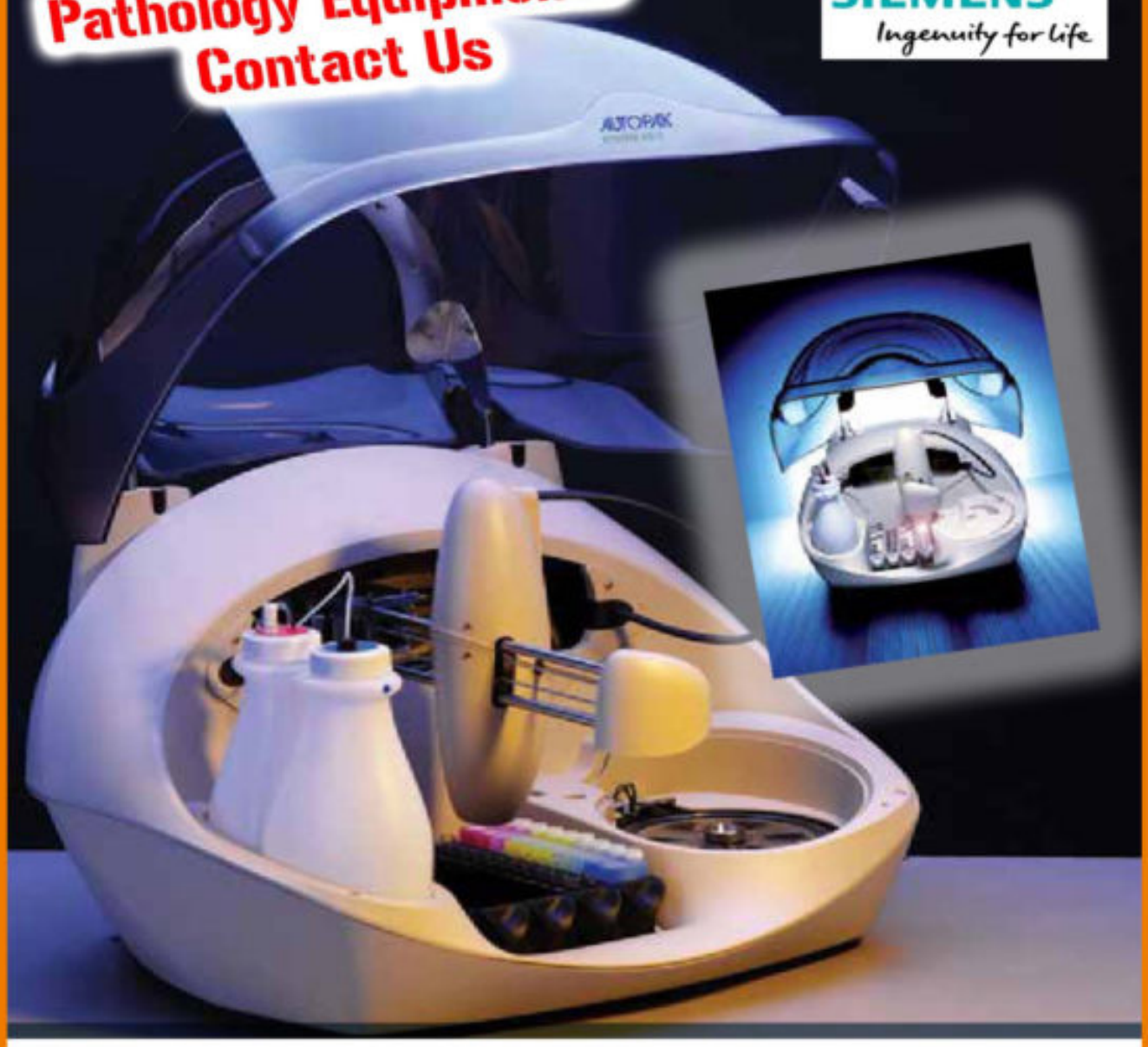

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

"भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी"

धन्यवाद मोदी जी

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

निःशुल्क राशन वितरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत
मिलने वाले नियमित राशन के साथ-साथ

5 किलो गेहूं एवं चावल

प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

मुफ्त

**मध्यप्रदेश के
एक करोड़ 15 लाख परिवार
लाभान्वित**

25 हजार 435
उचित मूल्य की दुकानों से
योजना अंतर्गत निःशुल्क
राशन वितरण।

**मुफ्त खाद्यान्न राशन थैले
में प्रदाय।**

सबको भोजन, पर्याप्त पोषण